हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल
तारांकित प्रश्न

26/03/2018/1400/RG/HK/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा हेतु दिया था। इसलिए सबसे पहले उस पर चर्चा करने के लिए मुझे मौका दें।

अध्यक्ष : माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी, आप एक मिनट के लिए बैठिए। आज मध्याह्न 01.00 बजे नियम-67 के अन्तर्गत मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जोकि माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी द्वारा दी गई है। मैंने सारी स्थिति को गंभीरता से देखा। बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों पर चर्चा लगी है और कटौती प्रस्तावों की चर्चा में सत्ता पक्ष के लोग भाग नहीं लेते हैं। आप ही लोगों के लिए वह सारी चर्चा चार दिन तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त नियमों की परिधि में भी यह है कि बजट पर चर्चा चल रही हो, उस समय में नियम-67 या अन्य नियमों में चर्चा देने का प्रावधान नहीं है।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष : श्री राम लाल ठाकुर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब नियम की परिधि के अन्तर्गत यह चर्चा नहीं आती है अन्यथा मैं आते ही इस पर चर्चा की अनुमति देता। इसलिए आपका यह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मान्य नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे यही आग्रह है।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपकी भाषा से मैंने अन्दाज़ा लगा लिया कि आप यही कहेंगे। ये कहते हैं कि ये लोग रात के अंधेरे में मुझे टेलीफोन करते हैं और बजट के लिए मेरी पीठ थपथपाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यह टेलीफोन कौन करता है? दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने ऊना में कहा कि---(व्यवधान)---जो चुनाव हारा है और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वहां का जो हारा हुआ आदमी है, वह हारा हुआ विधायक है। ---(व्यवधान)---उसके काम होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट में कटौती प्रस्तावों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। ---(व्यवधान)---

26/03/2018/1400/RG/HK/2

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए आपको इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं। ---(व्यवधान)---

श्री राम लाल ठाकुर : इन्होंने कहा कि यह वीरभद्र सिंह टैक्स लगा हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। ---(व्यवधान)---यह सहन करने वाला विषय नहीं है। ---(व्यवधान)---ये कहते हैं कि क्या यह संसदीय कार्य मंत्री का काम है?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)---आप मेरी बात तो सुन लें। तो फिर मेरी बात भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जिस प्रकार से ये झूठ बोलने का कम्पटीशन कर रहे हैं। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : जब आपके सदस्य बोलते हैं, तो माईक ऑन हो जाता है और जब हम बोलते हैं, तो माईक बन्द कर दिया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री : ऐसा होता है और प्रश्नकाल पर ऐसी चीजों के लिए माईक ऑन नहीं होगा। ---(व्यवधान)---बिना किसी कारण के या बिना किसी मुद्दे के---(व्यवधान)---जो चीजें आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। जब कोई कारण ही नहीं है और ऐसे मुद्दे आप सदन में उठाना चाहते हैं---(व्यवधान)---बिना मुद्दों के बात कर रहे हैं---(व्यवधान)---मुझे मालूम नहीं था कि श्री राम लाल ठाकुर जी इतना असत्य भाषण करने वाले हैं।

26.03.2018/1405/जेके/एचके/1

संसदीय कार्य मंत्रीः-----जारी--------

आप कोई ऐसी एक स्टेटमैंट दिखा दें जहां मैंने यह कहा हो ...व्यवधान ...एक भी शब्द मेरा बता दें। एक भी शब्द मेरा इनके पास इस प्रकार का नहीं मिलेगा। .....व्यवधान..... इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। झूठ बोलने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती । आप 100 झूठ बोलेंगे तो वह बात सत्य नहीं हो जाएगी। आप मुझे एक भी चीज़ दिखा दीजिए जो मैंने बोली हो। .....व्यवधान.....

अध्यक्षः कृपया बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप भी बैठिए। माननीय सदस्य आप बैठिए प्लीज। माननीय रामलाल जी, विनोद जी प्लीज एक मिनट बैठिए। आप लोग एक मिनट बैठिए। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? .....व्यवधान..... आप बैठेंगे। आप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा। मुकेश जी आप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा।.....व्यवधान..... मुकेश जी आप बैठिए। ....व्यवधान...रामलाल जी एक मिनट प्लीज। .....व्यवधान.....विनोद जी आप प्लीज बैठिए। मुकेश जी एक मिनट प्लीज। .....व्यवधान.....आप बैठिए फिर मैं बताता हूं। .....व्यवधान..... प्लीज आप लोग मत बोलिए, प्लीज़। .....व्यवधान.....मुकेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। .....व्यवधान.....एक मिनट, रामलाल जी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप एक मिनट में बोलिए। आपके ही प्रश्न है और आपकी ही चर्चा है और आपका प्रस्ताव मैंने अलाऊ नहीं किया है। अलाऊ न करने के बाद केवल आपकी सदन में बात आ जाए इसलिए आपको समय दिया है।

श्री रामलाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऊना गए। ऊना में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े लम्बे-चौड़े भाषण दिए। वहां पर जा करके एंटी ड्रग्ज के बारे में भी चर्चाएं हुई। ...व्यवधान....

अध्यक्षः आप लोग प्लीज इन्हें बोलने दीजिए।

26.03.2018/1405/जेके/एचके/2

श्री रामलाल ठाकुरः आप लोग मेरा एक मिनट भी नहीं ले सकते हैं। ....व्यवधान...

अध्यक्षः मुकेश जी, आप इनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री रामलाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, बोलने तो सत्तापक्ष के सदस्य भी नहीं दे रहे हैं। मेरे दो मिनट तो ये ही खा गए।

अध्यक्षः आप बोलिए और मुझे रैफर करिए।

श्री रामलाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, ...व्यवधान..... मेरा आपसे ज़वाब नहीं है। आप मेरा जवाब नहीं देंगें। ...व्यवधान....

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी, आप बैठिए।

श्री रामलाल ठाकुरः माननीय सदस्य, पठानिया जी आप ज़वाब नहीं देंगे।

अध्यक्षः राकेश पठानिया जी, आप बैठिए।

श्री रामलाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो अखबारों में छपा है वह अखबार वालों ने घर में नहीं लिखा । अखबार में कहा गया कि सत्र में विरोध तो घर में जाकर बजट अच्छा, इस बारे में मुख्य मंत्री जी को टैलिफोन करते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि ये बताएं कि यहां पर कौन-कौन ऐसे एम0एल0ए0 हैं? सबको पता लग जाए कि कौन आपको रात के अंधेरे में फोन करते हैं? ....व्यवधान.... हमने बजट का विरोध किया है। यह बजट लोगों के विरोध में है और युवाओं के विरोध में है। .....व्यवधान.....

26.03.2018/1410/SS-YK/1

अध्यक्षः काफी हो गया। माननीय राम लाल जी प्लीज़। आपका विषय आ गया। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। --(व्यवधान)-- हर्ष जी, यह नॉट एलाउड है। मैंने इस पर रूलिंग दी है उसके बाद भी आप बात कह रहे हैं। वह (माननीय मुख्य मंत्री) उसका जवाब दे रहे हैं। आज आप ही के प्रश्न और कट मोशन लगे हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, श्री राम लाल जी ने नियम-67 के अन्तर्गत इस विषय को उठाने की कोशिश की है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः नियम-67 डिस-एलाउड है।

मुख्य मंत्रीः जिसका माननीय सदस्य ज़िक्र कर रहे हैं, जिसकी आपने अनुमति नहीं दी है। मुझे लगता है कि यह विषय इस प्रकार से उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। लोकतंत्र है उसमें विश्वास करिये। हम भी करते हैं। जनसभा में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अगर इस पर आप चाहते हैं कि विपक्ष का ही नियंत्रण रहे तो मुझे लगता है कि वह सम्भव नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं बहुत तर्क के साथ बात कहता हूं और बिना वजह के बात का बतंगढ़ बनाना मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का समय व्यर्थ करने वाली बात है। माननीय सदस्यों की गरिमा और उनकी भावनाओं का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है और मैं उसे करता भी हूं। अभी मुकेश जी ने कहा कि जब पार्लियामैंट मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उनकी बात रिकॉर्ड पर आ रही है। मुकेश जी, आप याद करिये, अभी बहुत वक्त थोड़े बीता है, ढाई-तीन महीने का कार्यकाल हुआ है, हम तो पांच वर्ष तक इस लट्टू (माइक) का इंतजार करते रहे कि कब जलता है, ऐसे इसको देखते थे। जब हम उधर से बोलते थे तो यह जलता ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बोलने का अवसर दिया है। हम आपकी तरह नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया है। आपका (श्री राम लाल) नाम लेकर आपको कहा गया कि आप अपनी बात कहिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहीं इस प्रकार से नहीं कहा। हमने बजट प्रस्तुत किया। बजट पर बहुत लम्बी चर्चा हुई। विपक्ष ने अपनी बात कही और हमारे लोगों ने भी उसमें बात कही। मुझे लगता है कि इसमें कहने की बात बहुत ज्यादा नहीं थी। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा कि बजट अच्छा पेश किया है, समर्थन सब लोगों का रहा लेकिन विपक्ष के लोगों की विवशता है क्योंकि विपक्ष में

26.03.2018/1410/SS-YK/2

बैठे हैं उसका विरोध करना उनकी विवशता है। मजबूरी है। इस बात को उस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री) बीच में मत बोलें, प्लीज़। मुकेश जी, उनको बात पूरी करने दें। --(व्यवधान)--

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप इमरजैंसी लगा दो। अगर आप हमें बोलने नहीं देना चाहते तो आप इमरजैंसी लगा दो।

Speaker: What do you mean by Emergency? इमरजैंसी का क्या मतलब है? --(व्यवधान)-- आप ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो डिस-एलाउड है उसके बाद भी बोल रहे हैं। --(व्यवधान)--

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः --(व्यवधान)--

Speaker: Not to be recorded.

मुख्य मंत्रीः क्या हमारा बात करना भी गुनाह है? --(व्यवधान)-- नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। हमने जो कहा है, आप सुन लीजिए। मैं आपके ही विधान सभा क्षेत्र में था --(व्यवधान)-- यह मैंने नहीं कहा है, आप रिकॉर्ड लाईये। मैंने कहा कि हमारी पार्टी के जो साथी यहां पर हैं उनके कहने पर काम करेंगे। इसमें क्या बुरा है? --(व्यवधान)--

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः आप विरोध कर रहे हैं कि 60 करोड़ की घोषणा करके आए हैं। --(व्यवधान)--

26.03.2018/1415/केएस/वाईके/1

अध्यक्षः कृपया बैठिए। वो बता रहे थे, आप सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान) प्लीज़ बैठिए। मैं प्रश्नकाल आरम्भ कर रहा हूं। (व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि हमारे इन मित्रों को क्या हो गया ? (व्यवधान)

अध्यक्षः मुकेश जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप हाथ खड़ा करिए, मैं आपको समय देता हूं। आप हाथ ही खड़ा नहीं करते। (व्यवधान) उसको तो अस्वीकार कर दिया लेकिन बोलने के लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप लीडर हैं। (व्यवधान) जब आप हाथ खड़ा करेंगें कि मैंने बोलना है (व्यवधान) ऐसे थोड़े ही होगा। He will have to take the permission.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सचमुच में मुझे लगता है कि इससे बड़ा मज़ाक कोई और नहीं हो सकता। इस माननीय सदन में हम उम्मीद करते थे कि मुकेश जी को नई जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को ये गम्भीरता के साथ निभाएंगें। हमारे विधान सभा क्षेत्रों में भी, जब इनकी सरकार थी तो ये किस प्रकार से जाते थे? मैं तो अभी एक ही बार गया था और मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये, इनका सारा परिवार बारी-बारी से आता था । मैं आज भी बता सकता हूं कि वहां पर जो कुछ भी नहीं थे, सिर्फ राजनीतिक पद पर थे, उनके हाथों से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूमि पूजन हुए, उनके हाथों से उद्घाटन हुए। मैं अगर कहीं उद्घाटन के लिए गया, जहां पर मेरी पार्टी का विधायक चुन कर नहीं आया, तो हमने तो वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही है कि ये इस बात को हमसे पूछ रहे हैं कि कौन है? ये तो इनकी जांच का विषय है। हमसे बहुत सारे लोग बात करते हैं। दिन में भी बात

करते हैं, शाम को भी बात करते हैं। काम के सिलसिले में बात करते हैं लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में उनके ही नेता ने आज एक स्टेटमैंट दी है कि अब तो हद हो गई, सारी सीमाएं इन्होंने लांघ दी ।

26.3.2018/1420/av/ag/1

मुख्य मंत्री-------जारी

कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार की स्टेटमैंट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीजों को लेकर के खुद ही समझ लेना चाहिए कि उनकी पार्टी में चल क्या रहा है। आज मैं यहां पर देख रहा था कि राम लाल ठाकुर जी उस भूमिका में आना चाह रहे थे जहां मुकेश जी हैं क्योंकि यह भी उनके बीच का एक विषय है। वैसे मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, इस सारे विषय की गम्भीरता इस प्रकार नहीं है। नियम 67 के तहत बहुत ही गम्भीर मसले लाए जाते हैं। मैं माननीय सदस्यों के स्वाभिमान के प्रति सजग हूं और मुझे इस जिम्मेवारी को ठीक प्रकार से निभाने की आदत है और मैं निभाता भी हूं। मैं ऊना और हरोली विधान सभा क्षेत्र में प्रवास पर था और मैंने कहीं किसी को नहीं कहा कि ये विधायक है। मैंने यह कहा है कि ये मेरी पार्टी के साथी है, सरकार इनके कहने पर भी कार्य करेगी / विकास करेगी। ये जनहित के जिन मुद्दों को लेकर हमारे पास आयेंगे उस कमी को विकास की दृष्टि से पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसमें मैंने गलत क्या कहा है? इसलिए मुझे लगता है कि इस सारी बात का कोई अर्थ नहीं था। काफी दिन बीत गये, बीच में छुट्टियों का अंतराल था और उस कारण से इनकी खबर नहीं बन रही थी। आज इनको मौका मिला कि यहां आकर के खबर बनायेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम इनसे निवेदन कर रहे थे कि 67 से आगे की गिनती भी शुरू करो, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। आने वाले समय में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये लोग सदन के संचालन में पूरा सहयोग करेंगे। यहां पर हमारे सारे मंत्री और विधायक किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम हर चर्चा का जवाब देने के लिए सक्षम / तैयार हैं। मगर ऐसे अनावश्यक विषय को लेकर के जिसका कोई अर्थ न हो, मात्र सिर्फ खबर बनाने के लिए वाकआउट करते हैं। इनके समय में विधायकों के खिलाफ किस-किस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थीं, मैं उन शब्दों को यहां

रिकार्ड में नहीं लाना चाहता हूं। यदि आप उस समय की टिप्पणियां रिकार्ड में देखेंगे तो पायेंगे कि

26.3.2018/1420/av/ag/2

हमारे विधायक और इस संस्था की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाती थी। फिर भी मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीजों को देखते हुए विपक्ष के लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करेंगे और विश्वास करने के साथ अपनी सारी बातें इस मान्य सदन के अंदर ठीक तरह से रखेंगे। यहां पर इनकी ओर से रखी गई बातों का सरकार की तरफ से उचित जवाब दिया जायेगा। अभी इनके आधे लोग चले गये और आधे लोग अंदर रह गये, उसके बाद फिर बोले; इनके बीच में कोई समन्वय नहीं है। एक उठता है और दूसरा बैठता है; इसलिए मैं इन सारी चीजों में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुझे इतना ही कहना है कि आज के जिस वाकआउट को ये लोग वाकआउट कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि यह वाकआउट भी था या नहीं। आप रिकार्ड के हिसाब से देख लें लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं था। मैं माननीय विधायकों के सम्मान और दायित्व के प्रति उनसे ज्यादा सजग हूं और हमारी किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में और पीठ से फैसला दिया। आज प्रश्नकाल भी इनका है और उसके बाद कटमोशन भी हैं। आज के दिन नियम 67 की परिधि के अंतर्गत कोई भी चर्चा देना सही और सामयिक नहीं है। उसके बावजूद विषय रखने के लिए और समय दिया। उसके बाद भी अपनी टिप्पणियां वह भी आसन की तरफ करना, अनुचित है।

26.3.2018/1420/av/ag/3

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, आज जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष की तरफ से किया गया है, मेरा भी इस मान्य सदन में लगभग 30 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।

26.03.2018/1425/TCV/AG-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ... जारी।

हम विपक्ष की तरफ बैठकर जब भी आसन की तरफ से कभी समय मांगते थे तो उस समय कितना समय हमें मिलता था, कितना नहीं मिलता था, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं 1993 से 1998 तक कांग्रेस पार्टी का विधायक था और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस व़क्त श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। 23 दिसम्बर, 1997 को उस व़क्त के मुख्य मंत्री जी का प्रवास मेरे चुनाव क्षेत्र में था। जब वह पहले कार्यक्रम में मण्डप में आये, स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया था, इनके साथ उस व़क्त के उद्योग मंत्री श्री रंगीला राम राव जी भी थे। श्री नत्था सिंह जी उस व़क्त चेयरमैन थे और मैं वहां का विधायक था। जैसे ही सभा को सम्बोधन करने का कार्यक्रम शुरू हुआ और डी0पी0आर0ओ0 ने श्री रंगीला राम राव का नाम सम्बोधन के लिए लिया, मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मुख्य मंत्री जी, मैं यहां का विधायक हूं। कांग्रेस पार्टी से हूं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैंने यहां के लोगों की समस्याएं आपके समक्ष रखनी है। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वहां के एस0पी0 को आदेश दिए कि इनको अरैस्ट करो। मेरे चारों तरफ सिविल ड्रैस में नौजवान खड़े थे। मैं तो यह सोच रहा था कि ये कांग्रेस युवा मोर्चा के होंगे या एन0यू0एस0आई0 के होंगे। लेकिन जैसे ही मुख्य मंत्री ने कहा कि इनको अरैस्ट करिए, एस0पी0 ने मुझे पकड़ लिया। वहां जो नौज़वान खड़े थे, उन्होंने मुझे 8 फुट ऊंचे स्टेज़ से नीचे फैंका और फिर जैसे बकरे को काट करके उसको चारों टांगों से उठाकर ले जाते है, उस प्रकार से ले गये। वहां पर सामने ही एक जीप्सी खड़ी थी और मुझे 2 डी0एस0पीज0 ने उसमें डाल दिया। जब मुझे वहां से ले जा रहे थे, तो वहां स्कूल के बच्चे व अन्य लोग भी खड़े थे। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि एक विधायक के नाते, जब मुझे ले जा रहे थे, तो मुझे लातें मारी गईं और जो मुख्य मंत्री स्टेज पर बैठे थे, वह कह रहे थे कि कोई ऑब्जैक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 व 5 लोग

आब्जैक्शन कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा था। वहां का पुलिस स्टेशन सरकाघाट वहां से केवलमात्र 20

26.03.2018/1425/TCV/AG-2

किलोमीटर दूर था। मुझे पुलिस स्टेशन सरकाघाट नहीं ले गये, मुझे वहां से 80 किलोमीटर दूर जोगिन्द्रनगर के पुलिस स्टेशन ले गये और वहां पर जेल में बन्द कर दिया। उससे अगला कार्यक्रम उस व़क्त के मुख्य मंत्री का मेरे घर के पास उच्च माध्यमिक पाठशाला, मढ़ी में था। मेरी छोटी-सी बेटी और वहां के लोगों ने पूछा कि हमारे विधायक कहां हैं? अध्यक्ष जी, मेरी 14 वर्ष की बेटी को अरैस्ट कर लिया गया, इसके बाद मेरी धर्मपत्नी और हमारे लोगों को अरैस्ट कर लिया गया। इसके अलावा 22 दिसम्बर, 1997 को रात 11.00 बज़े 2 डी0एस0पी0 जोगिन्द्रनगर जेल में आये और उन्होंने कहा कि आपको ज़मानत के लिए मण्डी ले जाना है। मैंने कहा कि मण्डी में कौन-सा न्यायालय मेरी ज़मानत के लिए खुल गया। वे कहने लगे कि ए0डी0एम साहब का कार्यालय है।

26-03-2018/1430/NS/DC/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ----जारी

मैंने कहा ए0डी0एम0 साहब एच0ए0एस0 काडर का है और यहां जो एस0डी0एम0 बैठता है, वह भी एच0ए0एस0 काडर का है, यहां पर जमानत करवा दो। उन्होंने कहा कि हमारी मज़बूरी है, हम आपको वहीं ले जायेंगे। मैंने कहा चलो, मण्डी ले चलो। अध्यक्ष जी, रात को 01.00 बजे मण्डी की जेल में डाल दिया गया और डेढ़ घंटा दूसरी जेल में डालने के उपरांत कहा कि चलो। मैंने सोचा कि ए0डी0एम0 के कार्यालय ले जा रहे होंगे। ठीक 03.00 बजे जिप्सी में डाला और वहां से ए0डी0एम0 कार्यालय की तरफ न जा करके जब सुन्दरनगर रोड की तरफ गाड़ी चली तो मैंने ड्राईवर को बाजू से पकड़ा और पूछा कि कहां ले जा रहे हैं? अध्यक्ष जी, ड्राईवर ने कहा कि सर, हमें आदेश हैं कि जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के रूप में धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर दो दिन के लिए हैं, तब तक आपको धर्मपुर क्षेत्र के बीच में नहीं रखना है और आपको बाहर-बाहर ही घूमाना है। इन्होंने

03.45 बजे गोहर थाने की जेल में रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वे लोग इस बात के लिए हमें दोषी ठहरा रहे हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी को कह रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी ही पार्टी के विधायक को 24 घंटें में तीन जेलों में रखा और वहां से मुझे तब निकाला, जब इनको वायरलैस से मैसेज़ आया कि अब वीरभद्र जी अवाह देवी से धर्मपुर क्षेत्र से बाहर निकल गये हैं। तब जा करके इन्होंने मुझे छोड़ा। मुझे आज भी पूरा याद है। आज मैं इन सभी (विपक्ष) को देख रहा हूं। ठाकुर राम लाल जी दस साल तक सत्ता से बाहर रहे हैं और ये दस साल की भड़ास यहां निकालना चाहते हैं। बाकी लोगों को इस तरफ की कुर्सियों का नशा चड़ा हुआ था, अब वह नशा उतर रहा है और नशा अब नहीं रहा है। इसलिए उस तरफ (विपक्ष) के लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि सत्ता हमारे हाथ से चली गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो लोकतंत्र है। यह कोई हमारी जेब में नही है या किसी की जेब में नहीं है, यह तो जनता-जनार्द्धन का फैसला है और आदरणीय जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में प्रदेश में सरकार बनी है। मैं ऐसा समझता हूं। हमने डॉ0 वाई0एस0 परमार जी के साथ काम नहीं किया है लेकिन बाकी सारे मुख्य मंत्रियों के साथ काम किया है, सभी मुख्य मंत्री चाहे वे कांग्रेस के रहे हों या भाजपा के रहे हों। मैं एक बात इस माननीय सदन के बीच में कहना चाहूंगा कि सबसे मिलनसार और सबके साथ इस प्रकार से बात करने वाले और सरल स्वभाव के मुख्य मंत्री ठाकुर जय राम जी हैं। ये (विपक्ष) जिस प्रकार से

26-03-2018/1430/NS/DC/2

कह रहे हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है। हाउस को चलाना मात्र सत्ता पक्ष का काम नहीं है या सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं है, इसके लिए इनको (विपक्ष) सहयोग करना चाहिए। प्रश्नकाल तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल के उपरांत आज कट-मोशन्ज़ लगे हुए हैं तथा कट-मोशन्ज़ हमेशा विपक्ष की तरफ से आते हैं। इन्हीं के कट-मोशन्ज़ हैं, ये अपने कट-मोशन्ज़ में जो मर्ज़ी कहें, इनको कौन रोकेगा कि आप इस बात को न कहें। इसलिए अध्यक्ष जी, आज इन्होंने जो ट्रैंड शुरू किया है, यह शोभायमान नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र जी ने बैग ऊपर उठा करके नीचे फैंका है, यह उनकी उम्र के तकाज़े को भी शोभायमान नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि जो छः बार मुख्य मंत्री रहे हों, वे इस प्रकार की हरकत करें। इसलिए इस माननीय सदन में ये लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इन्होंने

नियम-67 को तो ऐसा बना दिया है ऐसा तो नियम-62 भी नहीं होता है। नियम-67 पर चर्चा तब होती है अगर कोई ऐसी घटना घटे, जिस पर सारा काम रोक करके उस पर चर्चा करनी पड़े। इन्होंने जो आज या इससे पहले किया है, पूरा सदन इसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है और साथ में इनसे (विपक्ष) आग्रह करता है कि मिल बैठ करके इस सदन को चलाने का काम करें। इस सदन की तरफ पूरे प्रदेशवासियों की नज़र है। प्रेदशवासी देख रहे हैं कि हमारे चुन हुए नुमाईंदे इस सबसे बड़े मंदिर में क्या-क्या जनहित के फैसले लेते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.03.2018/1435/RKS/DC-1

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र कुछ चीजों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के लिए जो 20 प्रश्न लगे हुए हैं उनमें से सत्तापक्ष की ओर से 16 प्रश्न दिए गए हैं और विपक्ष की ओर से केवल 4 ही प्रश्न दिए हुए हैं। बेसिकली न तो ये हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं और न ही कोई काम कर रहे हैं। ये प्रदेश की जनता के हित के प्रश्न ही नहीं उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता के पक्ष में ये कटौती-प्रस्ताव पर बोल सकते थे परन्तु उस पर भी ये बोलना नहीं चाहते हैं। आपसी लड़ाई के कारण ये नियम-67 का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये मिसयूज घोर निंदनीय है। नियम-67 इसके लिए नहीं है। यहां तक कि नियम-62 में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाए तो ये बात इस नियम का भी मुद्दा नहीं है। अध्यक्ष जी, पिछले पांच वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारे लिए 'मक्कड़झंडू' नाम के शब्द कहे जाते थे। क्या हम मक्कड़झंडू थे? रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास डॉ0 यशवंत सिंह परमार की जयन्ती के ऊपर कार्यक्रम होता है। वहां पर पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा कहा जाता है कि बी.जे.पी. के विधायक, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है उनका काम करने लायक भी नहीं है। ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन हम ऐसे शब्द सुनकर भी सदन चलाते रहे हैं और इस प्रदेश के लोक हित के मुद्दे उठाते रहे हैं। आज ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय

है। प्रश्नकाल हमेशा विपक्ष का होता है, जनता का होता है। प्रश्न काल को स्थगित करना बहुत rarest of the rare cases में होता है। ये इस नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने ठीक व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था के अनुसार यदि इनको वाक आउट करना था तो ये वाक आउट करते। लेकिन यह तो कोई वाक आउट नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोग अंदर थे और कुछ लोग बाहर चले गए । कुछ यहां पर किताबें पटक कर चले गए। इस बात की हमेशा निंदा होनी चाहिए। यह सदन इसकी भर्त्सना करता है, घोर निंदा करता है। आज बजट पास होना है। अगर ये कट-मोशन में नहीं आना चाहते हैं तो सारे-का-सारा बजट आज पास हो जाएगा और दिनांक 29.03.2018 तक इस सदन को चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बात का इनको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से

26.03.2018/1435/RKS/DC-2

माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि मैंने कोई स्टेटमैंट दी है कि हम कांग्रेस के बिना भी इस सदन को चला लेंगे। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार तो हम इनके बिना चला लेंगे क्योंकि जनता ने हमको मैनडेट दिया है। सरकार तो हमारे नेता श्री जय राम ठाकुर जी ही चलाएंगे। लेकिन सदन हम सबके साथ मिलकर चलाना चाहते हैं। उसमें जो जनता की सेवा की दृष्टि से काम है, उन कामों को हम सब मिलकर करना चाहते हैं। मेरी एक भी स्टेटमैंट बता दें, जिसमें यह कहा गया हो कि हम इनके बिना भी सदन को चला देंगे। ऐसा एक भी शब्द मैंने कहीं नहीं कहा है। अगर इस प्रकार का एक भी शब्द ये बता देंगे तो इसके लिए मैं सजा भुगतने को तैयार रहूंगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जो विषय रखा कि ऊना में मेरे कार्यक्रम में श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का नाम लगा है। वह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से गैर सरकारी कार्यक्रम था। पूर्व सैनिक सेवा समिति द्वारा वीर समाज का एक-एक पैसा इक्ट्ठा करके उसका निर्माण वहां पर किया है। उसके लोकापर्ण के अवसर पर हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी को वहां पर बुलाया गया था। उसमें उनका नाम लिखा गया। वह सरकारी कार्यक्रम नहीं था। लेकिन मैं

यह कहना चाहता हूं कि यह झुंझुलाहट कुछ और ही है। पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर थे। उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ वहां पर आई। इन्होंने लोगों के आवाहन के ऊपर करोड़ों रुपये की सौगात हरोली विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदरी दी। मैं इनकी झुंझुलाहट को समझ सकता हूं। जो इनका असंसदीय व्यवहार आज यहां देखने को मिल रहा है और जिस तरह से लोकप्रिय निर्णय हमारी सरकार ले रही है। मैं उस झुंझुलाहट को समझ सकता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर नियम-67 पर चर्चा चल रही है तो हम भी इस पर भाग लेंगे।

26.03.2018/1440/बी0एस0/एच.के-1

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्या 161

श्री विनय कुमारः अनुपस्थित।

26.03.2018/1440/बी0एस0/एच.के-2

प्रश्न संख्याः 162

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष जी, यह बड़ा ज्वलंत इशू है और हम तो चाहते हैं कि सरकार इस बारे में सुदृढ़ हों। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे कर्मचारी/अधिकारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप करूणामूलक आधार पर इनकी मदद करे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये जो नीति है इसके तहत ई.पी.एफ. और ई.पी.एस. 60 प्रतिशत ही जब ये सेवानिवृत होते हैं तो उनका पैसा रीलीज होता है। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष के बाद सेवानिवृत होता है तो उन्हें यह राशी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलती है। सेवानिवृत के बाद दो वर्ष तक वह अपना जीवन-

यापन किस प्रकार करता है, यह उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है? इसके साथ ही जो 40 प्रतिश पैसा सेवानिवृति के बाद बचता है उससे उन्हें पैंशन दी जाती है उसमें भी उम्र काफी मायने रखती है यदि कोई 40-42 वर्ष की आयु में नौकरी लगता है तो उसे 1,000 रुपये या 1,500 रुपये पैंशन लगती है। लेकिन अगर कम उम्र में जैसे 25-30 वर्ष की आयु में कोई सरकारी सेवा में लग जाए तो उसे ज्यादा पैंशन लगती है, लगभग 3000 रुपये उसे पैंशन लग जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपने कर्मचारियों की इस बजट में मदद की है। इसके अलावा जो 80 वर्ष के बुजुर्ग थे उनकी आयु भी पैंशन का लाभ पाने के लिए आपने 70 वर्ष कर दी है। यह जो भविष्य निधि है इससे ही जीवन यापन करना पड़ता है। आज-कल के बच्चे बुजुर्गों की सेवा नहीं करते।

अध्यक्षः कृपया आप प्रश्न पूछिए।

26.03.2018/1440/बी0एस0/एच.के-3

श्री रमेश चन्द धवालाः जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी को अपने बच्चों की शादी करनी है तो वह अपनी भविष्य निधि को निकाल लेता है, उसे मकान बनाना है तो वह अपनी भविष्य निधि निकाल लेता है और इसके अलावा उसने अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करना हो तो भी अपनी भविष्य निधि को निकाल लेता है। लेकिन ई.पी.एफ. वालों को 10 प्रतिशत अपना व 10 प्रतिशत सरकार की तरफ से पैसा मिलता है वह सारे का सारा 58 साल या 60 साल के बाद ही उन्हें मिलता है। क्या सरकार इस बारे कोई गम्भीरता से विचार करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके साथ ही कुछ और पूछ लूं क्यों बार-बार प्रश्न करने पड़ेंगे। मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बत कर रहा हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं। उनमें से एक आई.पी.एच. विभाग में और एक बिजली विभाग में कर्मचारी कार्यरत थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस

पैंशन नीति के तहत उन्हें क्या मिलेगा? इसलिए जो केन्द्र सरकार की नीति है उसके अनुसार उस परिवार को करूणामूलक आधार पर नौकरी दी जाए या उस परिवार को पैंशन मिलनी चाहिए।

26.03.2018/1445/DT/HK-1

प्रश्न संख्या...162 जारी

श्री रमेश चंद ध्वाला ...जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करुंगा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाए।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय , जो मूल प्रश्न है वह कुछ और है लेकिन जो माननीय सदस्य की ओर से पूरक प्रश्न आया है, वह प्रश्न से थोड़ा अलग है। अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि नई पैंशन प्रणाली देश के सभी राज्यों में लागू हुई है। यह प्रणाली सभी प्रकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर लागू है। चाहे वह IAS अधिकारी हो या क्लास फोर हो, यह सब पर लागू है। दूसरा, जो माननीय सदस्य जी ने 60 प्रतिशत का जिक्र किया कि यह पैसा रिटायरमैंट के दो वर्षों के बाद रिलिज होता है। इसमें वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है कि जो 60 प्रतिशत पैसा रिलिज़ किया जाता है उसमें रिटायरमैंट के बाद, साठ साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको एक महीने के बाद रिलिज़ कर दिया जाता है। उसके अलावा जो 25 प्रतिशत पैसा होता है can be withdrawn for the marriage of children after ten years of service. जिनकी 10 वर्ष की नौकरी होती है उन्हें 25 प्रतिशत पैसा लेने का भी अधिकार होता है। अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य जी ने यहां पर ई0पी0एफ0 का जिक्र किया है। ई0पी0 पी0एफ0 तो पब्लिक सैक्टर कॉर्पोरेशन्ज के इम्प्लाइज पर लागू होता है। जो नई पैंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं,

उन स्टेट गवर्नमैंट इम्प्लाइज पर यह लागू होता है। कर्मचारी बार-बार यह आग्रह कर रहे हैं कि ओल्ड पैंशन स्कीम लागू की जाए। इस प्रकार के आग्रह हमारे पास बार-बार आ रहे हैं। नई पैंशन स्कीम को देश के सभी प्रांतों में स्वीकार कर लिया है। पुरानी पैंशन स्कीम पर हम जाएं तो उसका फाइनैंशियल इम्प्लिकेशन बहुत बड़ा है। उसके कारण हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है।

26.03.2018/1445/DT/HK-2

इस तरह से सारी चीजों को करना सम्भव नहीं होगा। वर्ष 2003 के पश्चात् नई पैंशन स्कीम लागू हुई है। आज की तारीख में अधिकांश कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यरत हैं, उन्होंने उसको लगभग स्वीकार कर लिया है। पूरे देश में सभी राज्यों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के हित के लिए हमने समय-समय पर कदम उठाए हैं। हम हमेशा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते रहे हैं। जो प्रश्न आपने उठाए हैं मुझे लगता है कि उस संदर्भ में यह जानकारी देना उचित है।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति वर्ष 2003 से पहले चाहे वह डेली वेज पर लगा था या कॉंट्रैक्ट पर लगा था

26.03.2018/1450/SLS-YK-1

प्रश्न संख्या : 162 ...जारी

श्री रमेश चंद ध्वाला.....जारी

ऐसे 25000 के लगभग लोगों ने वर्ष 2003 से पहले किसी-न-किसी विभाग में नौकरी की है जहां उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए थे लेकिन उनको भी पैंशन नहीं मिल रही है हालांकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार को बने हुए तो अभी दो-अढ़ाई महीने ही हुए हैं। इससे पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता। मैं मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वैसे तो कुछ प्रदेशों ने, जैसे कि

हरियाणा ने, ओल्ड पैंशन प्रणाली लागू कर दी है। जिन प्रदेशों के संसाधन अच्छे हैं उन प्रदेशों ने ओल्ड पैंशन प्रणाली लागू की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो इस तरह के कर्मचारियों के मसलों को, जो मैंने अभी यहां पर उठाए हैं; चाहे वह पैंशन का मसला है या कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार उनको पैंशन देने का मसला है, क्या माननीय मुख्य मंत्री कोई कमेटी गठित करके इन कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में कोई सकारात्मक विचार करके फ़ैसला लेने का विचार रखते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में ओल्ड पैंशन स्कीम लागू है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी अब न्यु पैंशन स्कीम ही लागू है। अब तक एक-दो प्रांत बचे थे जिनमें ओल्ड पैंशन स्कीम लागू नहीं थी लेकिन उन्होंने भी अब यह स्कीम लागू कर दी है। **आपने सुझाव के रूप में कहा है कि क्या आने वाले समय में कर्मचारियों की इस समस्या पर विचार करने के लिए कोई कमेटी गठित करेंगे, आपने सुझाव दिया है और हम इस पर विचार करेंगे। वैसे अध्यक्ष महोदय, मुझे काफी लोग ओल्ड पैंशन स्कीम के सिलसिले में मिले हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। हमने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करने के पश्चात इस सारी स्थिति पर विचार किया है। आपके सुझाव से पहले ही हमने विचार कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार करेंगे।**

26.03.2018/1450/SLS-YK-2

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री साहब ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, वह तथ्यों के विपरीत है। हरियाणा के बारे में तो मैं कह नहीं सकता लेकिन 2 राज्यों के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां आज भी पुरानी पैंशन स्कीम लागू है। मैं रमेश ध्वाला जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये माननीय सदस्य हैं और बहुत से पीड़ित वर्गों के लिए ये अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री अपने रिकॉर्ड को चैक करें तो त्रिपुरा आज भी पुरानी पैंशन योजना के अनुसार कार्य कर रहा है जो वर्ष 2003 से पहले की पैंशन स्कीम है। अब वहां आपकी सरकार आई

है, इसलिए क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस पर कोई कमेटी गठित करें तो मैं इनसे सहमत हैं। इस प्रश्न को यहीं बंद नहीं कर देना चाहिए बल्कि एक स्कोप रखना चाहिए। साधन पैदा किए जा सकते हैं लेकिन जो यह सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विधायकों को पैंशन मिल सकती है तो मैं समझता हूं कि जो कर्मचारी लंबे समय तक अपना योगदान देते हैं उनको भी पैंशन मिलनी चाहिए। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि जिन्होंने दिहाड़ीदार के रूप में काम किया है लेकिन 2003 के बाद वह पक्के हुए हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे। वह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए कमेटी गठित करनी ही पड़ेगी जो न्यायपूर्ण तरीके से अपना काम करे। इस पर मुख्य मंत्री साहब को स्पष्टीकरण देना चाहिए। केरल के अंदर आज भी पुरानी पैंशन प्रणाली ही चलती है।

26/03/2018/1455/RG/YK/1
प्रश्न सं. 162----जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत पुरजोर तरीके से इस स्कीम का समर्थन किया है। ये भी शायद हकीक़त से वाक़िफ नहीं हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक केरल में भी न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई है। यहां जैसे त्रिपुरा की बात कही गई है, तो मैं उसके बारे में पता करुंगा। मुझे भी इसकी फैक्चुअल पोजीशन जाननी है। हम सारी चीजों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझसे आग्रह किया। उनकी बात को मैंने सुना और सुनने के बाद समझा भी है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे आदरणीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने इसमें कोई समिति के गठन या इस तरह की कोई व्यवस्था करने के लिए कहा है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि हम उस सारी चीज पर विचार करेंगे। अगर आवश्यक हुआ, तो हम खुले मन से इस पर विचार करेंगे। चर्चा करने में कोई नुकसान या हर्ज नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब जिस बात को पूरा देश स्वीकार कर रहा है और यह राज्य का विषय है, इस बात को आप कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने

कहा कि जहां पूरा देश इसको स्वीकार कर रहा है और जहां हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो आज के दौर में या आज की तारीख में है, तो क्या उस परिस्थिति में यह सब हमारे लिए संभव है? ये सारी चीजें सोचने का विषय है। **जो सुझाव यहां दिए गए हैं, उनको हमने गंभीरता से सुना है और इस सबको लेकर आगे आने वाले समय में इस पर कंसलटेशन या चर्चा करने का दौर जारी रखेंगे। समिति के बारे में जो सुझाव यहां दिए गए हैं, हमने कहा कि हम इस पर खुले मन से विचार करेंगे।**

26/03/2018/1455/RG/YK/2

प्रश्न सं. 163

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सोलन जिले में कितने विकास खण्ड कार्यालय हैं? दूसरा, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी, कृपया इसकी समय-सीमा तय करें कि दून विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड कार्यालय कब तक खोला जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि पूरे प्रदेश में जैसे ही सीमांकन हुआ, तो बहुत सारे विधान सभा क्षेत्र ऐसे रह गए जो तीन-तीन विकास खण्डों में आते हैं। कहीं दो या कहीं तीन हैं। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार की यह नीति रही है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र का अपना विकास खण्ड हो। **इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं**। मैं यहां यह विश्वास दिलाता हूं कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में जैसे नालागढ़, धर्मपुर या सोलन में अपना विकास खण्ड नहीं है, खोलने का प्रयास कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि यदि आप लिखकर दें, जहां-जहां दो-दो विधान सभा क्षेत्रों में उनके अपने क्षेत्र आते हैं, यदि वे एक ही करना चाहते हैं, तो सरकार इस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष : वैसे तो यह एक पर्टिकुलर विधान सभा का प्रश्न था।

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में तो विकास खण्ड कार्यालय है, लेकिन दून में नहीं है और कसौली विधान सभा क्षेत्र का कार्यालय भी धर्मपुर में है। लेकिन दून में नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : <u>सरकार इस पर विचार कर रही है।</u>

श्री अशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पालमपुर विधान सभा क्षेत्र में भी डिलिमिटेशन के बाद अब बी.डी.ओ. ऑफिस नहीं है, तो जिस प्रकार से आपने दून के लिए आश्वासन दिया है, क्या पालमपुर के लिए भी यही आश्वासन देंगे?

26/03/2018/1455/RG/YK/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : <u>अध्यक्ष महोदय, हम पूरे प्रदेश में इसका पुनः पुनर्गठन करेंगे और सरकार इस पर विचार कर रही है।</u>

प्रश्नकाल समाप्त

26.03.2018/1500/जेके/एजी/1

<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जो इस प्रकार से हैः-

सोमवार, 26 मार्च, 2018 (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

मंगलवार, 27 मार्च, 2018 (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

बुधवार, 28 मार्च, 2018 (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

वीरवार, 29 मार्च, 2018 (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019

(i) मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(ii)विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

26.03.2018/1500/जेके/एजी/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः5-17/2009-ईएलएन. दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.11.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;
ii. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और
iii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 ।

26.03.2018/1500/जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यजीवी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-4/2016

दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.12.2017 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःफिश-ए(3)-1/2016 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 9.02.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.03.2018 को प्रकाशित ।

26.03.2018/1500/जेके/एजी/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे ।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं ।

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय मैं, आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का अष्टम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:32 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

26.03.2018/1500/जेके/एजी/5

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं:-

i. समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:21 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:5 के अन्तर्गत राजस्व विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः9 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

26.03.2018/1500/जेके/एजी/6

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18), का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः10 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18),समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

i. समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः18 के अन्तर्गत उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः14 के अन्तर्गत पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

26.03.2018/1505/SS-AG/1

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह-(जी)ए(3)/2013 दिनांक 18.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 को प्रकाशित;
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-॥, वर्ग-।॥(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए-(3)-44/99 दिनांक 28.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित;
iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, वर्ग-॥(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-1/2013 दिनांक 15.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2017 को प्रकाशित;

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, विज्ञापन रूपकार, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए-(3)-4/2014 दिनांक 4.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.09.2017 को प्रकाशित;

26.03.2018/1505/SS-AG/2

v. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तबला मास्टर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए 3(18)99 दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 को प्रकाशित;

vi. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

vii. हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17

26.03.2018/1505/SS-AG/3

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी नाइजीरियाई समुंद्री लुटेरों द्वारा नौसेना दल के तीन हिमाचली युवकों के अपहरण एवं इराक में चार युवकों के अपहरण के बारे में वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस सदन को इराक में मारे गए चार हिमाचलियों के बारे में तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। हिमाचल के चार युवक क्रमशः श्री अमन कुमार, गांव व डाकघर पासू, तहसील धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री संदीप सिंह राणा,

गांव समकर, डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 3. श्री इन्द्रजीत, गांव कदरेटी (लालहपुर), डाकघर भटेड़, तहसील देहरी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 तथा 4. श्री हेम राज, गांव बायला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, इराक के मसूल शहर में कार्यरत थे, जब जून, 2015 में ISIS ने उन्हें अपहरण कर लिया। अपहृत किए हुए भारत के कुल 40 व्यक्ति थे जिसमें एक व्यक्ति उनके चंगुल से छूट कर भाग गया।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद भारत सरकार अपहृत व्यक्तियों की खोजबीन के लिए इराक सरकार के साथ लगातार सम्पर्क में रही। बाद में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि इराक के बदूश शहर में एक बड़े पहाड़ के नीचे बहुत से मृत व्यक्तियों के शव दबे हुए हैं। इस सूचना की पुष्टि डिप रेडियेशन राडार के माध्यम से करवाई गई। भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वी0के0 सिंह ने बगदाद जाकर इस सारी प्रकिया की समीक्षा की। पहाड़ को खोदने के पश्चात् 39 भारतीयों के शव प्राप्त हुए, इनमें हिमाचल के चार युवक भी थे। उनके निकटतम परिवार वालों के ब्लड सैम्पल लेकर बगदाद भेजे गए, जहां उनके डी0एन0ए0 टैस्ट लिये गए। डी0एन0ए0 टैस्ट के बाद यह पाया गया कि यह चार शव हिमाचलियों के थे।

विदेश राज्य मंत्री जनरल वी0के0 सिंह पुनः बगदाद जाकर उन सभी 39 व्यक्तियों के शव लेकर भारत आने वाले हैं। यह शव ताबूतों में लाए जायेंगे। ऐसी सम्भावना है कि 27 या 28 मार्च, 2018 को करीब 12:00 बजे यह विमान अमृतसर पहुंच जाएगा, जहां उन हिमाचल के युवाओं के शव सौपे जायेंगे। इन शवों के साथ हर ताबूत पर व्यक्ति का फोटो, समूचा पता एवं डी0एन0ए0 की रिपोर्ट लगी होगी।

26.03.2018/1505/SS-AG/4

मेरी सरकार इन शवों को अमृतसर में प्राप्त करने की सम्पूर्ण व्यवस्था करेगी और उनके घरों तक पहुंचाने की भी सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार ने सम्बन्धित परिवारों के लिए 4 लाख रुपये Ex-Gratia Grant की घोषणा की है। मैं सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ये सब नौजवान ही थे, कम उम्र के थे जोकि इराक में कामकाज की तलाश में गए थे और काम करने के पश्चात् इनको वहां किडनैप किया गया। 2014 के बाद हमारी सरकार लगातार प्रयत्न/प्रयास में रही कि जो वापिस नहीं आए

26.03.2018/1510/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

उनके परिवार को किसी तरह से जानकारी मिले कि वे जिन्दा है या नहीं और केन्द्र सरकार ने गम्भीर प्रयास करने के पश्चात आखिरकार यह जानकारी हासिल कर ली कि 40 लोग थे जिनको वहां से अगुवा किया गया था । उनमें से एक भाग कर निकल आया और 39 लोगों की हत्या हो गई। उनमें से चार हिमाचली थे। चारों परिवार के सदस्यों के साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात हुई है। मैंने उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। सुन्दरनगर में जिस नौजवान की इराक में हत्या हुई है उनके परिवार में जाना भी हुआ है। हमने चार लाख रुपये उनको एक्स ग्रेशिया ग्रांट के तौर पर राशि स्वीकृत की है। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुखद घटना रही है।

अध्यक्ष महोदय, अभी इस घटना के दुख से ही प्रदेश बाहर नहीं निकला था कि इसके बाद एक और घटना की जानकारी हमें सूचना के माध्यम से मिली है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तीन युवकों सर्वश्री सुशील कुमार, निवासी नगरोटा सुरियां, पंकज कुमार, निवासी समलोटी और अजय कुमार निवासी पालमपुर का नाईजीरिया में वहां के नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज को हाईजैक करके फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है।

श्री सुशील कुमार के पिता श्री रघुवीर सिंह, निवासी नगरोटा सुरियां ने ज्वाली में इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 12 मार्च, 2018 को उनके परिवार को नाईजीरिया से उनके बेटे सुशील से एक सैटेलाइट कॉल प्राप्त हुई जिसने बताया कि कुछ नाईजीरियन

समुद्री लुटेरों/डाकुओं ने उसका व उसके समूह के दो अन्य हिमाचली सदस्यों का जहाज सहित अपहरण कर लिया था।

यह भी पता चला कि 24 मार्च को परिवार के सदस्यों को एक ओर कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें सुशील कुमार ने सूचित किया है कि नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों ने 26

26.03.2018/1510/केएस/डीसी/2

मार्च, 2018 को फिरौती के भुगतान की मांग की है अन्यथा मर्चेंट नेवी दल के हिमाचली मूल के इन तीनों सदस्यों को मार दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में इन युवकों के परिवार के साथ है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। इस मामले को लेकर मैंने विदेश मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती सुषमा स्वराज से कल ही बात की है और उनसे भी प्रयास करने का आग्रह किया है जिससे इन तीनों हिमाचली युवकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद प्रसंग है कि ये तीनों युवक भी कांगड़ा जिला से ही सम्बन्धित हैं और जो इराक में मारे गए थे, उनमें चार में से तीन युवक भी कांगड़ा जिला से सम्बन्ध रखते थे। हमारी सरकार प्रयत्नशील है, हमेशा कोशिश कर रही है और वहां अम्बैसी में केन्द्र सरकार में सुषमा स्वराज जी ने कल शाम को हमसे कहा है कि उनकी बात हुई है आज उन्होंने कहा कि हम दोबारा बात करके लेटैस्ट पोजीशन क्या है, उस सम्बन्ध में जो जानकारी वहां से मिलेगी उसको हम तक पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि वे सभी सुरक्षित हो। एक सदस्य के परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत भी हुई है बाकियों से अभी तक सम्पर्क नहीं हो पाया है लेकिन मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करुंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया। धन्यवाद।

26.03.2018/1510/केएस/डीसी/3

अध्यक्षः श्रीमती आशा कुमारी जी कुछ कहना चाहती है।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर एक वक्तव्य रखा। कांग्रेस पार्टी भी जिन चार युवकों की इराक में मृत्यु हुई, उनके दुख में अपने आप को सम्मिलित करती है। बहुत दुखद घटना थी। यह ठीक है कि 40 व्यक्ति किडनैप हुए थे । अध्यक्ष महोदय, यह सदन है सदन में रिकॉर्ड स्टैट रहे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि उनमें से एक व्यक्ति वापिस आ गया था। वह व्यक्ति वापिस आया और उसने सूचित कर दिया था कि बाकी 39 को मार दिया गया है। मगर बार-बार सवाल उठाने पर भी विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय ने, किसी की भी मौत राजनीतिक कारण नहीं हो सकती परन्तु यह विधान सभा है, यहां पर रिकॉर्ड सही होना चाहिए ।

26.3.2018/1515/av/dc/1

श्रीमती आशा कुमारी-------जारी

विदेश मंत्री ने बार-बार कहा कि हम उनके सम्पर्क में हैं जो जीवित हैं। दुःख की बात है कि उन लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो एक व्यक्ति वापिस आया था उसने विदेश मंत्रालय को सही बात बताई थी कि 39 के 39 व्यक्ति मारे गये हैं जिसमें 31 पंजाब के तथा चार हिमाचल के थे। आपने ठीक बताया कि उनमें से एक मंडी और तीन कांगड़ा के थे। वह एक दुःखद घटना थी और उनके परिवारों के साथ उनके शोक में कांग्रेस पार्टी अपने आपको सम्मिलित करती है। मगर ये तीन युवक जो नाइजीरियन सेलर / पायरेट्स द्वारा बंदी बनाये गये हैं और हाई सीज में इस तरह की सी-पायरेसी चलती है। मगर दुःखद बात यह है कि इसमें तीन बच्चे हमारे एक ऐसे जाल में फंसे हैं, ऐसा न हो कि इराक की तरह हम यह सोचते रहें कि वे जीवित हैं और वो पायरेट्स, they have no morals and issues. They are only looking for money and they kill for money. इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से दोबारा आग्रह रहेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर आग्रह कर चुकी है। सदन में भी मैं पार्टी की ओर से यह आग्रह करना चाहूंगी कि भारत सरकार इस मामले को बहुत गम्भीरता से उठायें। अगर वह फिरौती की मांग कर रहे हैं तो जान की सुरक्षा कैसे होगी, क्या सरकार फिरौती देगी? वे तो पायरेट्स हैं, they are

not for anything else but totally for money. तो इस मामले को भारत सरकार किस प्रकार से सुलझायेगी? हमारे चार युवक इराक से वापिस नहीं आ सके लेकिन जो कांगड़ा जीले से तीन युवक सम्बद्ध रखते हैं और जीवित हैं, उनके लिए हमारी सरकार कुछ करें। हम मृतकों के शोक में अपने आपको शामिल करते हैं और जीवित युवकों के लिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उनको वापिस लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

26.3.2018/1515/av/dc/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आशा कुमारी जी ने जो अपनी संवेदनाएं हमारे इस वक्तव्य के साथ शामिल की है, यह अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इन्होंने फैक्चुअल पोजिशन से हटकर बात कही कि माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह बात कही कि इराक में हम उनके सम्पर्क में हैं, यह गलत है। उन्होंने पार्लियामैंट में यह स्टेटमैंट दी थी कि हम वहां की सरकार के साथ सम्पर्क में हैं और अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। (---व्यवधान---) नहीं, पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के साथ सम्पर्क में होना अलग विषय है। बातों को इस तरह से ले जाना (---व्यवधान---) हम उनको जिन्दा नहीं ला पाये। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इतने प्रयास किए कि अगर वे जिन्दा नहीं है तो भी उनके शव वहां पर ढूंढे गये। डी0एन0ए0 मैचिंग के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन भारत सरकार ने उस प्रक्रिया को पूरा करवाया और कनफर्मेशन के बाद ही यह बात कही गई। ऐसी चीजों में बहुत जल्दबाजी में बोल देना सम्भव नहीं होता। डी0एन0ए0 में पुष्टि होने के बाद यह बात कनफर्म हुई कि वे लोग अब जिन्दा नहीं हैं। उसके पश्चात उनके शव यहां लाने की दृष्टि से सरकार को जो कार्य करना चाहिए था वह भारत सरकार कर रही है। दूसरी जो नाइजीरिया वाली बात कही गई है उस विषय में भी हम गम्भीरतापूर्वक लगे हुए हैं। हम इस बारे में आज भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या प्रोग्रैस हुई है और मेरी कल विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि इस बारे में जो भी अद्यतन स्थिति होगी हम हिमाचल सरकार को अवगत करवाते रहेंगे। उनकी रिहाई के लिए जो कुछ करने की सम्भावना

होगी, वह की जायेगी। वे जिन्दा हैं और अपने परिवार के साथ मिल सके हम उसके बारे में चिन्तित हैं। उसमें सरकार की तरफ से जो भी मदद करने की सम्भावना होंगी, वह की जायेगी।

26.03.2018/1520/TCV/HK-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूं, जो इस प्रकार हैंः-

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत
1	**2**		**3**
1	विधान सभा	(राजस्व) (पूंजी)	40,47,78,000 3,05,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	14,88,47,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व) (पूंजी)	1,84,89,67,000 15,09,00,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व) (पूंजी)	2,09,49,10,000 1,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	(राजस्व) (पूंजी)	6,80,62,23,000 10,00,00,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	76,06,61,000

		(पूंजी)	7,00,00,000
7	पुलिस और सम्बध्द संगठन	(राजस्व)	13,12,63,78,000
		(पूंजी)	64,43,03,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	61,24,08,90,000
		(पूंजी)	1,05,72,15,000

26.03.2018/1520/TCV/HK-2

9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	19,94,23,21,000
		(पूंजी)	1,86,77,30,000
10	लोक निर्माण- स़डक, पुल एवं भवन	(राजस्व)	33,08,06,03,000
		(पूंजी)	12,16,28,02,000
11	कृषि	(राजस्व)	4,82,27,38,000
		(पूंजी)	73,83,97,000
12	उद्यान	(राजस्व)	3,44,95,88,000
		(पूंजी)	16,93,13,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	25,30,55,93,000
		(पूंजी)	5,59,74,27,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	3,85,97,17,000
		(पूंजी)	16,97,26,000
15	योजना एवं पिछ़डा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	78,15,72,000
		(पूंजी)	2,62,43,45,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	5,43,35,55,000
		(पूंजी)	10,06,50,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	24,87,39,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	1,88,26,76,000
		(पूंजी)	62,38,00,000

19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	9,27,11,92,000 17,36,51,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) (पूंजी)	15,46,34,87,000 23,16,50,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	33,50,25,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व) (पूंजी)	2,61,51,64,000 2,01,15,000

26.03.2018/1520/TCV/HK-3

23	विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजी)	5,36,24,07,000 4,10,08,01,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व) (पूंजी)	27,94,53,000 41,58,000
25	सडक और जल परिवहन	(राजस्व) (पूंजी)	2,60,23,81,000 54,84,01,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व) (पूंजी)	68,88,39,000 55,33,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व) (पूंजी)	2,90,00,90,000 71,75,81,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामयोजना तथा आवास	(राजस्व) (पूंजी)	4,13,58,86,000 20,12,00,000
29	वित्त	(राजस्व) (पूंजी)	59,94,83,17,000 12,77,51,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व) (पूंजी)	89,89,50,000 50,66,03,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व) (पूंजी)	12,64,91,92,000 3,54,98,06,000

32	अनुसूचित जाति उप-योजना	(राजस्व)	13,49,89,20,000
		(पूंजी)	10,61,55,05,000
	ज़ोड	**(राजस्व)**	**3,15,88,80,59,000**
		(पूंजी)	**47,45,76,31,000**
		कुल ज़ोड	**3,63,34,56,90,000**

26.03.2018/1520/TCV/HK-4

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु आग्रह का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा। इसमें एक परिवर्तन हेतु आग्रह आया है कि पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और दूसरी प्राथमिकता- लोक निर्माण- सडक, पुल एवं भवन और चौथी प्राथमिकता सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की दी है। ये चौथी प्राथमिकता दूसरे नम्बर पर आये, ऐसा माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी ने आग्रह किया है और शायद इस बारे में माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री से भी बात की है। यदि सदन इसको स्वीकृत करता है तो हम दूसरी मांग के रूप में सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई को लेंगे। अन्यथा जो क्रम आपने दिया है, उसी हिसाब से चर्चा होगी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जो रिक्वैस्ट माननीय सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आई है, क्योंकि आज सैशन 7 बज़े तक चल रहा है, इसलिए ये तीसरे नम्बर पर कल चली जायेगी। लेकिन आज दो पर चर्चा हो जायेगी। इसलिए तीसरे नम्बर पर इसको ले लें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भाव एक ही है। माननीय मंत्री जी को परसों किसी काम से जाना है, इसलिए वे इस मांग पर कल चर्चा रखना चाहते हैं, तो कल ये चर्चा में आ जायेगी।

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

इससे पूर्व की अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोग कट-मोशन में भाग लें सकें। आपके पहले दिन 14 लोग सूची में सूचीबद्ध हैं। अब मैं सर्वप्रथम मांग संख्याः 9 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' को चर्चा एवं मतदान के लिए लेता हूं।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या :9 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः **26.03.2018/1520/TCV/HK-5**

19,94,23,21,**000** रुपये (राजस्व) एवं **1,86,77,30,000** रुपये (पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस मांग पर श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री जगत सिंह नेगी, श्री राम लाल ठाकुर, श्री राजेन्द्र राणा, श्री नन्द लाल, डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री राकेश सिंघा, श्री पवन कुमार काजल, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से 7 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगे या उनकी ओर से मैं प्रस्तुत हुआ समझूं।

सदस्यगणः प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गये जो इस प्रकार से हैंः-

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या:

<u>नीति का अननुमोदन</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग 9

च्स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणछ

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
10. श्री राकेश सिंघा,
11. श्री पवन कुमार काजल,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,

26.03.2018/1520/TCV/HK-6

13. श्री आशीष बुटेल,
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन।
4. सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
5. प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन।

2. <u>सांकेतिक कटौती</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

चस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणछ

की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

<u>श्री हर्षवर्धन चौहान:</u>

1. मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिलाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिम्बी, रेणुका, जाखना तथा कमराऊ में पैरा-मेडिकल व डाक्टरों की पदपूर्ति न कर पानें में सरकार की असफलता ।

2. मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिम्बी के भवन निर्माण हेतु धन का प्रावधान न कर पाने में सरकार की असफलता ।

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है।
अब इन कटौती प्रस्ताव में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी अपना विचार प्रस्तुत करेंगे।

26.03.2018/1520/TCV/HK-7

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगे चर्चा के लिए रखी गई है और मांग संख्याः 9 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर चर्चा हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े निराश हुए, क्यों हमारे सदन से बाहर जाने पर ये कह रहे थे कि बजट आज ही पास कर लेते हैं। इतने कच्चे हम भी नहीं है कि अपनी 4 दिन की चर्चा को बीच में ही छोड़कर चले जायें।

26-03-2018/1525/NS/HK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री ----जारी

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवायें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कटौती प्रस्तावों में सबसे पहले हमने स्वास्थ्य विषय लिया है। आज का दिन हमारा है और अगले आने वाले दिन भी हमारे हैं तथा सत्ता पक्ष को आराम से सुनना है। अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि इस समय केंद्र में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हमारे प्रदेश में भी युवा नये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने हैं और यहां पर डबल ईंजन

की बात बार-बार होती रही है तथा कहा जा रहा है कि डबल ईंजन वर्क कर रहा है। मुख्य मंत्री जी ने अपनी बज़ट पुस्तिका में स्वास्थ्य पर चर्चा की है। पैरा संख्याः 131 से ले करके 140 तक लगभग 10 पैरे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कन्सर्न प्रदेश के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। क्योंकि हैल्थ सैक्टर में जो एक्पैन्सन है, एक बहुत बड़ी एक्सपैन्सन पिछले कुछ सालों से प्रस्तावित है। यहां पर जब हैल्थ पर चर्चा रखी गई तो सबसे पहले एम्ज़ की बात आई कि एम्ज़ को प्रदेश में कैसे स्थापित करना है? इस पुस्तिका में भी यह लिखा गया है कि लगभग 1351 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदान कर दी है। लेकिन जब हमने इस माननीय सदन में प्रश्न लगाया तो उत्तर में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि बज़ट पुस्तिका में किस ढंग से लगभग 1351 करोड़ रुपये की राशि आई है? प्रश्न के जवाब में यह आ रहा है कि यह केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर केंद्र सरकार ही फैसला करेगी। वैसे तो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री आये थे और वे यह बात कह कर गये हैं कि चार साल में यह प्रोजेक्ट बनाया जायेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि वे किस ढंग से केंद्र सरकार से सम्पर्क में हैं, लैंड के बारे में क्या फैसला हुआ है? वैसे तो लैंड ट्रांसफर हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट ठाकुर राम लाल जी के विधान सभा क्षेत्र का है। आप इसके टैंडर की मोनिटरिंग किस ढंग से कर रहे हैं? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का समय भी अब कम रह गया है। केंद्र सरकार के लगभग 10-11 महीने ही रह गये हैं। यह समय कम होता जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नींव पत्थर प्रधान मंत्री जी ने विधान सभा चुनाव से 8-10 दिन पहले ही रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आगे क्या प्रगति हुई है?

26-03-2018/1525/NS/HK/2

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, तीन मैडिकल कॉलेजिज़ का विषय है जोकि हमारे नेता गुलाम नवी आज़ाद जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए सैंक्शन किये थे। इनमें से दो कॉलेज शुरू हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सत्र से हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज शुरू कर पायेंगे? प्रदेश में डॉक्टर्ज़ की स्ट्रैन्थ को किस तरीके से पूरा करेंगे? तीन मैडिकल कॉलेजिज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पी0जी0आई0 का

सैटेलाइट सैंटर ऊना में बन रहा है। हमने यहां पर भी प्रश्न लगाया था तो मंत्री जी ने उसमें कहा है कि यह इनसे सीधे तौर पर जुड़ा सवाल नहीं है और केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ कह सकती है। लेकिन ऊना में बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्ज़ लगे हुए हैं जोकि आपकी पार्टी के नेताओं ने लगा रखे हैं और उसमें लिखा गया है कि 400 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है, धन्यवाद प्रस्ताव भी हो गया है

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.03.2018/1530/RKS/YK-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री...जारी

और सैंकड़ों पोस्टों का उसमें उल्लेख किया हुआ है। आपके नेता बाहर बयान दे रहे हैं कि 400 करोड़ रुपये आ गए हैं और सदन में आप कह रहे हैं कि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जो 400 करोड़ रुपये के होर्डिंग्स लगे हुए हैं इनमें कितनी सच्चाई है? यह मसला सैद्धांतिक स्थिति पर ही लटका हुआ है। आप इस बात को स्पष्ट करें। आई.जी.एम.सी. और टांडा मैडिकल कॉलेज शुरू से ही चल रहे हैं। इनकी स्ट्रैंथनिंग के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आई.जी.एम.सी. तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आप बजट में बड़े इश्यूज़ को गौण कर गए हैं। आपने किसी भी चीज़ का उल्लेख करना वाजिब नहीं समझा है। हिमाचल प्रदेश की मैडिकल यूनिवर्सिटी जोकि ई.एस.आई, मैडिकल कॉलेज/अस्पताल में खोली गई है, उसकी क्या स्थिति है? उस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चलाएंगे? आप इसके साथ मैडिकल कॉलेज को कैसे एफिलिएट्स कर रहे हैं। यह भी एक इश्यू है क्योंकि लम्बे समय से मैडिकल यूनिवर्सिटी की बात चलती आई है। लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंद्ध रहे हैं। डॉक्टर्ज वगैरह की डिग्रियां वहीं से मिलती है। यह मैडिकल यूनिवर्सिटी किस स्थान पर है और किस ढंग से आप इस यूनिवर्सिटी को चलाएंगे? मंडी में ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बन रहा था। जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एकदम यू-टर्न ले लिया गया और कहा गया कि इसकी आगे की फंडिंग हम नहीं करेंगे। उस वक्त की कैबिनेट ने यह फैसला किया कि इस

मैडिकल कॉलेज को आगे चलाना है। इसके लिए करार किया गया, एम.ओ.यू. वगैरह साइन किए गए। जो 3-4 सौ करोड़ रुपये बचा हुआ था उन्होंने इस पैसे को लगाने से इंकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश के पास आर्थिक संसाधन नहीं है और आपने सारा बोझ हिमाचल प्रदेश के ऊपर डाल दिया है। क्या आप इस मसले को उनके साथ दोबारा से उठा रहे हैं? आप किस ढंग से इस ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज का इश्यू सैटल करेंगे? मदर चाइल्ड होस्पिटल के बारे में बयान आ रहे हैं कि 2 या 3 होस्पिटल खोल दिए गए हैं। इसमें 100-100 करोड़ रुपये की फंडिंग की बात लगातार कही जा रही है। आप हमें यह स्पष्ट करें कि अभी तक

26.03.2018/1530/RKS/YK-2

प्रदेश में टोटैलिटी में कितना पैसा आया है? क्योंकि यह बहुत बड़ी एक्सपैंशन है। इन सारे संस्थानों को चाहे वे एम्स हैं, आई.जी.एम.सी है, टांडा है, चाहे तीन मैडिकल कॉलेज हैं, पी.जी.आई. है या मैडिकल यूनिवर्सिटी है। यह बहुत बड़ा एक्सपैंशन है और इन संस्थानों को चलाने के लिए आपके कंधों पर जबरदस्त लोड है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में तभी आगे बढ़ पाएगा अगर इन सभी संस्थानों के बारे में सही तरीके से फैसला हो सके। डॉक्टर्ज़ की शोर्टेज का मसला तो हमेशा से ही रहा है। हमारी सरकार ने भी 6 या साढ़े 6 सौ डॉक्टर्ज की भर्ती की थी। लेकिन अभी तक बड़े पैमाने में डॉक्टर्ज की शोर्टेज़ चल रही है। हमने जितनी बार डाक्टर्ज के बारे में हैल्थ सैक्रेटरी से बात की तो एक ही बात आती है कि डॉक्टर्ज की कमी है। फिर भी इस समय डॉक्टर्ज की कितनी कमी है और इन संस्थानों को चलाने के लिए कुल कितने डॉक्टर्ज चाहिए? यह कमी कितने समय में पूरी हो जाएगी? अभी तो आप एक की टोपी दूसरे के सर लगा रहे हैं। कभी आप डॉक्टर्ज को टांडा, कभी शिमला और कभी सिरमौर भेज देते हैं। उसी लॉट को आप उठा-उठा कर, घूमा-घूमा कर 'अहमद की टोपी, महमूद के सर' उस ढंग से इस डिपार्टमैंट को चला रहे हैं। सारे संस्थान सही तरीके से चल पाएं।

26.03.2018/1535/बी0एस0/वाई.के-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा .....जारी

हम यह चाहतें हैं कि रेगुलर डॉक्टर्स भर्ती हों। अभी पीछे रोगी कल्याण समिति के माध्यम से डाक्टरों को रखना शुरू कर दिया । हमारी सरकार के समय में डाक्टरों की तनख्वाह बढ़ाई गईं, 26,000/- रुपये से बढ़ाकर उसे 42,000/- रुपये तक किया गया, ताकि डाक्टर्स उपलब्ध हो सकें। लेकिन आप रेगुलर डाक्टर्स किस प्रकार से पूरे करेंगे ? नर्सिज और फार्मासिस्ट की बड़े पैमाने पर भर्ती पहले भी हुई है और अब आप भर्ती करेंगे या नहीं यह भी स्थिति स्पष्ट, क्योंकि बजट में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इस स्थिति में इन संस्थानों को कैसे चलाया जाएगा। हालांकि कहा गया है कि 22 सौ करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। कुल-मिलाकर आयुर्वेदा और दूसरे बजट को ले करके 25 सौ करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो चीजें हल की जानी चाहिए जिनका हैल्थ के साथ सीधा-सीधा वास्ता है उन चीजों को इसमें नहीं दर्शाया गया है।

कांग्रेस शासन में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के समय में जो संस्थान खोले गए हैं उनके बारे में आप थोड़ी बार-बार संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपने यहां कहा कि 103 संसथान ऐसे हैं जिन पर गौर कर रहे हैं, आप उन्हें बंद करेंगे या चलाएंगे? आप सदन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बतला दें क्योंकि 200 के आस-पास हमने संस्थान खोले हैं। कुछ पी.एच.सीज खोली हैं कुछ पी.एच.सी. को अपग्रेड कर सी.एच.सीज किया और काफी भवन भी हमने उस समय बनाए हैं। लेकिन डाक्टर्स की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। माननीय सदस्य हमारे कुल्लू से यहां पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा की माननीय अध्यक्ष महोदय इन्हें भी बोलने के लिए समय दें। वहां पर किस तरह से मां और बेटी दोनों की मृत्यु हुई है । वहां पर डाक्टर ही अस्पताल में मौजूद नहीं था। वह भी एक ज्वलंत ईशू है। डाक्टर्स की कमी बार-बार आ रह

26.03.2018/1535/बी0एस0/वाई.के-2

दूसरा यह है कि जिला अस्पतालों में आप इस कमी को कब तक पूरा कर देंगे क्योंकि जिला अस्पतालों में बार-बार जब भी बात करें वहां बताया जाता है कि यहां से डाक्टर चला गया, दूसरी जगह लगा दिया गया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग पर जितना दबाव पड़ता, प्राथमिकता आती है उस हिसाब से डाक्टर्स जो वहां से बदल लिया जाता है। आपके पास क्या फार्मूला है कि आप डाक्टर्स की कमी को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद जो बोर्डर एरियाज पर डाक्टर्स काम कर रहे हैं, वे ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिला अस्पतालों में लगे हैं। यह बहुत बड़ा मसला बन बया है। क्योंकि डाक्टर समाज का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसे किसी भी एम.एल.ए. या मंत्री को पकड़ना बहुत आसान काम है। क्योंकि हर किसी को बीमारी लगी हुई है। वहां डाक्टर किसी न किसी को पकड़ कर अपना काम करवा रहा है कि मैं उसी स्टेशन पर रहूं। मरीजों के बाहर के अस्पतालों में आप्रेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में आप्रेशन नहीं हो रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोगों से आप्रेशन का पैसा लिया जा रहा है । इसका समाधान करने के लिए आप कोई बड़ा कदम उठाएं। आपने जो हैल्थ कार्डस बना रखे हैं उसके द्वारा भी ईलाज हो रहा हैं और मुख्य मंत्री राहत कोष से पैसा देने पड़ रहा है तथा जिलाधीश को भी पैसा देने पड़ रहा है। कोई ऐसा फार्मूल तैयार किया जाए जिससे कम से कम यह पता चले कि इस व्यक्ति का मुफ्त में ईलाज होना है । उसमें पत्रता स्पष्ट रूप से अपनाई जाए इस मरीज का ईलाज इस स्वास्थ्य नीति से फ्री होना है। राजनेताओं के लिए हर समय दिक्कत रहती है क्योंकि उसे मालूम नहीं होता की मरीज कहां-कहां से पैसा ले रहा है। इसलिए कोई न कोई नीति बनाई जानी चाहिए जिससे की स्थिति स्पष्ट हो।

26.03.2018/1540/DT/AG-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री...जारी

अध्यक्ष महोदय, ये जो हैल्थ के हमारे इशूज़ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है । हांलाकि यहां पर यह कहा गया है कि दवाईयां 66 की बजाए 330 देंगे । ये तो यूनियन गवर्मेंट की नीतियां है जोकि यहां पर बजट में इसका भार बढ़ाने के लिए आपने दो-तीन चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि दिल्ली के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने यहां पर डाल दी हैं। आपने कहा है कि किडनी का ट्रांसप्लांट हम यहां पर करेंगे।। चार करोड़ से मुझे नहीं लगता कि आप किडनी का ट्रांसप्लांट यहां पर एस्टेब्लिश कर लेंगे। मुझे नहीं पता इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? अगर देना है तो पूरा पैसा दो, नहीं देना है तो मत दो । खास तौर पर जितने भी हमारे प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ हैं, हमारा आपसे यह आग्रह है कि आपने अपना दस्तावेज़ पूरी तरह से साइलेंट रखा है कि इन्स्टीच्यूशन्ज़ जो खोले गए हैं, इनको आप कैसे चलाऐंगे और आपके राजनीतिक इरादे क्या हैं? आप कितने इन्स्टीच्यूशन्ज़ बंद करना चाहते हैं और इसमें आपने क्या एक्सरसाईज़ की हैं? आपने इस दस्तावेज़ में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि मुखमंत्री जी ने कहा कि मुझे आखिरी घर तक दीया जलाना है। हम चाहते हैं कि ये आखिरी व्यक्ति तक दीया जलाएं। लेकिन इस बजट में जितने भी बड़े ईश्यूज हैं, ये सारे जो ईश्यूज़ हैं, ये सिर्फ राजनीतिक भाषणों के मुद्दे बने हुए हैं और सरकार बतायेगी इन सब नींव पत्थरों के बाद क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है? पी0जी0आई0 का काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है? हमीरपुर मैडिकल कॉलेज का काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, पी0जी0आई0 की जहां तक बात करते हैं, उसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं कि कांग्रेस पी0जी0आई0 के बारे में गम्भीर नहीं थी। आपने मई-जून में तो इसकी घोषण करवायी है। घोषणा के बाद आप चाहते थे कि ऊना की सीट किसी भी ढंग से जीती जाये। इसलिये आपने मई-जून में घोषण करवा दी और फिर एकदम कहने लग गये कि कांग्रेस ने इसमें एकदम से गम्भीरता नहीं दिखायी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके राजनीतिक पहलू में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पी0जी0आई0 खोलें। केंद्र में भी आपकी ही सरकार है। आप ऊना और कुल्लू में भी

मैडिकल कॉलेज खोलें। अब हर जगह मैडिकल कॉलेज हो गये हैं तो ऊना और कुल्लू में भी एक-एक मैडिकल कॉलेज खोलें जोकि लैफ्ट आउट जिले हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित है, वह इस बजट में पूरी तरह से गोन है। इसका आपने इस बजट बुक में कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर बोलने वाले 14 माननीय सदस्य हैं और सभी ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोलना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र हरोली में बहुत अच्छा और बड़ा अस्पताल बना है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध करवायें, जिसकी डिमांड लगातार चल रही है। सभी माननीय सदस्यों की अस्पतालों को ले करके अलग-अलग डिमांड है और 14 सदस्य बोलने वाले हैं तथा इसमें बहुत लम्बी चर्चा होनी है। आप जब भी इनका जवाब दें तो हमें सिलसिलेवार इसके बारे में बतायें कि आपकी स्वास्थ्य नीति क्या है? हमने सोचा था कि आप 100 दिन में आप किसी-न-किसी नीति का उल्लेख करेंगे। माननीय मंत्री जी की हैल्प में हम यह क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आप अपने जवाब में दे देंगे, तब भी हम समझते हैं कि कुछ शंकाओं का निवारण हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मेरा एक आग्रह रहेगा कि समय प्रतिपक्ष का है, अगर इस तरह 15-20 मिनट लगेंगे तो आपकी एक या दो डिमांड ही आ पायेंगी। आप लोग विषय उठायें, मैं पांच मिनट के बाद घंटी बजाऊंगा, पांच मिनट में आप अपने विषय को पूरा करेंगे तब आपकी ज्यादा-से-ज्यादा डिमांड्स चर्चा में आ सकेंगी। अब श्री अनिरूद्ध सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

26.03.2018/1540/DT/AG-3

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 9 के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलनेका मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके माध्यम से मैं सरकार तक कुछेक बातें भी पहुंचाना चाहूंगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है।

26.03.2018/1545/SLS-HK-1

श्री अनिरूद्ध सिंह .....जारी

मैं समझता हूं कि हम लोग इसके ऊपर गंभीर नहीं रहे हैं। अगर आप आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर्ज़ की बात करेंगे, नर्सिज की बात करेंगे, मैडिशन्ज की बात करेंगे तो यह सब कागज़ों में तो है लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो वह कहीं नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने 5 मिनट का समय दिया है इसलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा। मैं सबसे पहले पी.एच.सी. से शुरू करूंगा। हमारी कुछ पी.एच.सीज. जैसे गुम्मा, कुफरी, ट्राई जो ग्राम पंचायत पीरन में है वहां पर ताले लगे हुए हैं, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। पी.एच.सीज. कोटी, जटोली, जुन्गा और न्यु शिमला में भी हैं। पी.एच.सी. न्यु शिमला की बिल्डिंग का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। वहां के लिए फंड्ज उपलब्ध हैं परंतु जो अतिरिक्त भूमि के लिए विभाग ने अप्लाई किया था वह अभी तक नहीं मिली है। वह एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक यह पी.एच.सी. म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के सामुदायिक भवन में चल रही है। मेरा अनुरोध है कि न्यु शिमला एक अहम जगह है, हैविली पापुलेटिड है इसलिए अगर वह अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं होती तो इस समय जो भी भूमि उपलब्ध है जो विभाग के नाम हो चुकी है, उसके ऊपर जल्द-से-जल्द काम शुरू हो।

मैं यहां पर स्नोडन की भी बात करना चाहूंगा। यह अहम अस्पताल पूरे शिमला जिले को केटर करता है। वहां आज के समय में एक बिस्तर पर 3-3 मरीज़ सुलाए जा रहे हैं। मैं

माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप स्वयं एक बार वहां का दौरा करें और देखें कि वहां की हालत बहुत बदतर है।

रिपन अस्पताल की बिल्डिंग अभी नई बनी है जो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई है।

26.03.2018/1545/SLS-HK-2

कमला नेहरू अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी स्थिति ज्यों-की-त्यों है। वहां बिल्डिंग तो काफी बड़ी है लेकिन वहां पर भी एक बिस्तर पर 2-2 पेशैंट्स को सुलाया जा रहा है। इसके बारे में मंत्री जी और सरकार ज़रूर विचार करें।

मेरे कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र में भट्ठाकुफर में पूर्व सरकार के समय एक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जिसके लिए मैं सैंट्रल गवर्नमैंट का भी धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमारे लिए बजट उपलब्ध करवाया था। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने और उस समय के माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने मिलकर उसका शिलान्यास किया था। उसका काम ज़ोरों पर है। उसको विदिन टाईम लिमिट पूरा करें। यह अस्पताल 250 करोड़ रुपये का बन रहा है और इसकी क्लीयरैंसिज हमने करा कर दी थी। इसलिए इसको जल्दी-से-जल्दी पूरा करवाएं ताकि स्नोडन का प्रैशर वहां के लिए शिफ्ट हो सके।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम जेनेरिक दवाइयों की बात करते हैं। उनके लिए जो दुकानें गवर्नमैंट ने प्राईवेट प्लेयर्ज़ को दी हैं, मैं बताना चाहूंगा और यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप प्राईवेट लोगों को शॉप्स तो अलॉट कर देते हैं लेकिन वह लोग उन्हें आगे सबलैट करते हैं और प्रति मास अपनी जेब में 70,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक डालते हैं। इस बात का ज़रूर ख़याल रखें। यह सबके ध्यान में है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। माननीय मंत्री जी इसके ऊपर खास ध्यान रखें कि मैडिशन्ज की शॉप्स केवल मात्र सरकार ही चलाए। वहां पर ग्लब्ज भी बिक रहे हैं और ऐसी दवाइयां और इंजैक्शन्ज भी बिक रहे हैं जो प्रैसक्राईब्ड नहीं हैं। वह उन पर 300-400 परसैंट का मारजिन लेते हैं और वह चीजें उन दुकानों में इलीगली बेची

जाती हैं। इसके ऊपर आप चैक रखें ताकि आम जनता को इस समस्या से राहत मिले। डॉक्टर्ज़ और नर्सिज को भी आप यह सलाह रीटन में दें क्योंकि वह पेशैंट्स से ग्लब्ज के फालतू पीस मंगवा लेते हैं। उनको कहते हैं कि फलां नाप का ग्लब ले आओ, फलां दवाई ले आओ या पट्टियां ले आओ जबकि वह चीजें अस्पताल में फ्री मिलती हैं जबकि

26.03.2018/1545/SLS-HK-3

दुकानदार उन्हें महंगे दामों पर बेच रहे हैं। कैजुल्टी या हॉस्पिटल में नर्सिज उन्हें अपने पास ही रखती हैं और फिर दोबारा उसी काऊंटर को सेल आऊट कर रही हैं। यह हकीकत है। मैं कोई मात्र टिप्पणी नहीं कर रहा हूं या कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। परंतु अगर इसको चैक करेंगे तो मैं समझता हूं कि पब्लिक का इसमें काफी भला होगा।

मैं जुन्गा की बात करूंगा। जुन्गा में हॉस्पिटल है। मंत्री जी, वहां पर न तो ऐंबुलैंस चलती है

...(व्यवधान)...

26/03/2018/1550/RG/DC/1
श्री अनिरूद्ध सिंह------जारी

वह शहर के 20-25 किलोमीटर के दायरे में है। जब सरकार ने यहां ऐम्बूलेंस की सर्विस दी हुई है, तो पूरे जिले को इसका फायदा मिलना चाहिए। ऐम्बूलेंस न चलने के कारण वहां दो-तीन मौतें भी हो चुकी हैं। हमने पिछली विधान सभा में भी यह बात रखी थी। मरीज रैफर नहीं हो पाया। न वहां डॉक्टर्ज होते हैं। यदि वहां डॉक्टर्ज हैं भी, तो वे डेपुटेशन पर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्फी के बारे में एक प्रश्न लगाया था जिसका उत्तर आया कि वहां स्टाफ फुल है। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करुंगा कि जब भी आप कुर्फी जाएं, तो वहां का निरीक्षण करें और देखें कि डॉक्टर वहीं पर ---(घण्टी)---डेप्यूट है या वहां से वेतन निकालकर डेपुटेशन शिमला शहर में कर रहे हैं? बातें तो बहुत हैं, परन्तु हमारे कई साथियों ने बोलना है। मैं यही अनुरोध करुंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हम सब मिलकर ध्यान दें ताकि हमारा और जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

26/03/2018/1550/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि मैं आज सुबह भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के आग्रह कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, रीजनल हॉस्पीटल, कुल्लू में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से उठकर चले गए, परन्तु माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, रीजनल हॉस्पीटल, कुल्लू में कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ दिन पहले मिला था और मैंने उनसे इसके लिए अनुरोध भी किया। हाल ही में 20 तारीख को एक महिला और उसकी बच्ची की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद भी कोई जागा नहीं। आज के हालात यह हैं कि आप देखिए कि उस महिला को 21 मार्च की प्रसव की तारीख दी हुई थी। उस महिला को 20 मार्च को एकदम से प्रसव पीड़ा शुरू हुई और 10.43 बजे महिला ने वहां मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। हैरानी की बात यह है कि यह प्रसव स्टाफ नर्सों की निगरानी में करवाया गया। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अपने जिले के लिए समर्थन चाहूंगा। हमारे मण्डी के सभी लोग यहां हैं। मैंने पीछे श्री जवाहर ठाकुर जी एवं श्री किशोरी लाल से भी से भी बात की थी। माननीय वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी और विशेषकर माननीय कृषि मंत्री श्री रामलाल मार्केण्डा जी और माननीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री श्री अनिल शर्मा जी के संबंध भी कुल्लू के साथ हैं और कुल्लू में आना और रहना सभी पसन्द करते हैं। इसलिए कृपया कुछ सहयोग कुल्लू के लिए भी दीजिए। कुल्लू में आज के दिन में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जरी गया था। जरी में इससे भी बुरे हाल हैं। वहां आधारभूत ढांचा भी नहीं है। मैं वहां रोगी कल्याण समिति की बैठक में गया था। मैंने स्वयं उनसे कहा कि रोगी कल्याण समिति में इतना पैसा बिना खर्च किए हुए पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई लगभग एक साल से चीफ आर्किटैक्ट को बिल्डिंग का डिजाईन बनाने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन वहां से नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप कोई अपना आर्किटैक्ट

लगाइए। आजकल बड़े-बड़े बेरोजगार आर्किटैक्ट अपने नए-नए विचारों के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कृपा करके तुरन्त वहां

26/03/2018/1550/RG/DC/3

किसी की पोस्टिंग कीजिए। ऐसा भेदभाव कुल्लू के साथ बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। क्योंकि मैं सभी स्तरों पर इस बात को कह चुका हूं। सारे प्रमाण मेरे पास हैं। इसके अतिरिक्त वहां भूटि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां भी यही हाल है। आज मेरे अपने गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेगूवेण का एक नया परिसर में बनकर तैयार हुआ है। पूर्व सरकार ने वह इतना खूबसूरत बनाया है और बहुत ही रिकॉर्ड समय में

26.03.2018/1555/जेके/डीसी/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः----जारी-------

एक साल में बन कर तैयार हुआ क्योंकि हम खुद उस बात के पीछे लगे रहे और वहां के ठेकेदार तथा डिपार्टमैंट के साथ हम जुड़े रहे। यहां तक कि मैं जानता हूं कि सरकारी फाइलें कैसे लटकती है? कैसे एक फाइल को फाइनल करने के लिए तीन-तीन महीने चीफ आर्किटैक्ट के दफ्तर में ठेकेदार को घूमना पड़ता है और फिर भी फाइलें फाइनल नहीं होती हैं। हमने ये काम कैसे करवाए हैं, हम जानते हैं । वहां पर बहुत ही खूबसूरत भवन कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर का बन कर तैयार हुआ है लेकिन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भुन्तर में भी है। वह मेरा अपना क्षेत्र है। वह मेरा अपना गांव है। वे महज़ एक दूसरे से सिर्फ डेढ़-दो सौ मीटर की दूरी पर है। वहां पर जो पोस्ट स्वीकृत है, जो पोस्ट भुन्तर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में है वह पोस्ट हमारी तेगूबेड़ को नहीं दी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि कृपया इसको क्लब कीजिए ताकि एक जगह पर तो बेहतर सुविधाएं हों। वहां पर बहुत बढ़िया परिसर बन गया है। वह इतना बड़ा परिसर है कि वह पूरी तरह से हॉस्पिटल के लिए सही है। आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि भुन्तर में सब्जी मंडी साथ है। यदि कोई भी वहां पर

बच्चे को लेकर जाता है तो वहां पर संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांसिज़ हैं। डॉक्टर्ज़ इस बात को कहते हैं। सभी लोग इस बात को मानते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। अभी तो बरसात भी नहीं हुई। चार-पांच दिन पहले का एक आर्टिकल देखें तो पूरे का पूरा सीवरेज़ का पानी उस हॉस्पिटल परिसर में था। अब जब एक बेहतर सुविधा बन गई है, पॉलिटिकल कोई कम्पलशन नहीं है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोगों की सुविधा के लिए वहां पर बिल्डिंग बन गई है इसलिए कृपा करके वहां पर पूरी सुविधा दीजिए। महज इसलिए नहीं कि मंडी वाले मंडी में नौकरी करना चाहते हैं और कुल्लू में कोई आना नहीं चाहते हैं। मंडी में आपके कोई कॉलेजिज़ बन रहे हैं और वहां के लिए सारे का सारा स्टाफ वहां पर भेज करके फेकल्टी तैयार की जा रही है। कुल्लू के साथ यह भेदभाव न करें। जब से वहां 20 तारीख को यह हादसा हुआ, वहां पर इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया कि उसमें अगर कोई चिंगारी भी लगा दें तो विस्फोट होने की स्थिति है। मैं तो आज अध्यक्ष महोदय से भी मिला था और अध्यक्ष

26.03.2018/1555/जेके/डीसी/2

जी हम ऐसे-ऐसे मुद्दों को लेकर आए, मुझे नहीं मालूम कि इस सदन की क्या कार्यवाही होनी चाहिए और किस प्रकार से आपने कालिंग अटैंशन मोशन को डिसअलाऊ किया । कृपया करके ऐसे मुद्दों को और खासतौर से जो हम नए लोग आए हैं जो अपनी बात को इस सदन में रखना चाहते हैं, आप हमें सहयोग दीजिए। आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जरी में यही पॉजिशन मैंने आपको बताई, भुन्तर, तेगूबेड़, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, भुट्ठी, ये सभी क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं। कृपया करके कुल्लू का, मैं सभी जन-प्रतिनिधियों और कुल्लू के विधायकों से तो सहयोग चाहता ही चाहता हूं, द्रंग क्षेत्र और हमारे बालीचौकी में मुख्य मंत्री जी की पूरी की पूरी तहसील,गाड़ागुसैनी पूरे का पूरा, one third of the constituency that the Hon'ble Chief Minister represents comes under this hospital. आज बंजार के हॉस्पिटल का भी वही हाल है। बंजार के

किशोरी जी यहां पर हैं और शायद ये इतनी बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी वही हाल है। लेकिन मेहरबानी करके जो रीज़नल हॉस्पिटल कुल्लू है और तेगुबेड़ का हॉस्पिटल बढ़िया ब**ना**ना जरूरी है, इससे कुल्लू के हॉस्पिटल में प्रैशर कम होगा। अगर आज तेगुबेड़ हॉस्पिटल की ओ0पी0डी0 देखें, वहां 120 की ओ0पी0डी0 है, जबकि वहां पर एक ही डॉक्टर है। भुन्तर में जहां पर दो डॉक्टर है ,वहां पर भी ओ0पी0डी0 80 से 100 के बीच में है। आप इनको क्लब कीजिए ।वहां पर बिल्डिंग तैयार हो गई है उससे रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में भी बहुत कम बोझ होगा। द्रंग क्षेत्र, सराज के क्षेत्र, लाहुल का क्षेत्र और पांगी का क्षेत्र और जिया लाल जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी हमें सहयोग दीजिए। आप अपने क्षेत्रों की बातें तो करते हैं, कुल्लू में आप से अधिकतर जनसंख्या रहती हैं। आप भी हमें सहयोग दीजिए। मेहरबानी करके इस मुद्दे को आपको तुरन्त आपको समाधान करना पड़ेगा। मैं यह देख रहा हूं कि कई अफसर लोग हमारे जो कुल्लू जिले से जुड़े हैं लेकिन क्या कम्पलशन है कि वे आपके सामने कुल्लू जिला की बात नहीं कर पा रहे हैं। आपने मंडी सारे कुल्लू वालों को शिफ्ट करके मंडी मैडिकल कॉलेज़ में लगा दिया।

26.03.2018/1600/SS-HK/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर क्रमागतः

मेहरबानी करके आप इस इश्यु को तुरन्त अड्रैस कीजिए। हमारे कुल्लू हॉस्पिटल में जो 13 पद आज के दिन डॉक्टर्ज़ के खाली पड़े हैं कृपा करके आप इस पर ध्यान दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका हमेशा इसी तरह से सहयोग चाहूंगा, धन्यवाद।

26.03.2018/1600/SS-HK/2

अध्यक्षः माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मांग नं0-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर दिए गए कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पीछे जो छुट्टियां थीं इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जिले के दौरे पर गए थे। हमारे चुनाव क्षेत्र में भी गए थे। बहुत सारी बातें जो मुकेश

अग्निहोत्री जी ने कहीं, अध्यक्ष जी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित ज़रूर करती हूं। मैं बात सिर्फ चम्बा जिले और अपने चुनाव क्षेत्र की करूंगी। आप हमारे चुनाव क्षेत्र में गए, आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम जितने मर्जी चाहे करिये मगर अब आप मंत्री भी हैं। पहली बार मंत्री बने हैं। अच्छा होगा कि आईंदा जब आप जिलों के दौरों पर जाएं और वह भी बैकवर्ड इलाका जैसे कि चम्बा तो आप अपनी स्वास्थ्य संस्थाओं को देखने तो जाते। देखते तो सही कि वहां पर कौन-सी बिल्डिंग बन रही है, कहां पर क्या कमी है, कहां क्या ज़रूरत है। हम तो वैसे खुशकिस्मत हैं कि श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमें केहार में 50 बैडिड हॉस्पिटल मिला। उसका काम लगा हुआ है। वहां बिल्डिंग बनाने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं? एफ0आर0यू0 सलूणी में उसका 10-15 साल लैंड ट्रांसफर नहीं हुआ। लास्ट जो सरकार थी, ठाकुर कौल सिंह जी मंत्री थे और वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से हमने सलूणी में लैंड ट्रांसफर करवाई। कुछ पैसा उसका डिपोजिट में पड़ा हुआ है लेकिन आगे हैल्थ डिपार्टमैंट ने पी0डब्ल्यू0डी0 को ट्रांसफर नहीं किया है। तो बिल्डिंग का काम लग नहीं पा रहा है। अनिल शर्मा जी की भी मैं धन्यवादी हूं, अब वे दूसरी साइड बैठे हैं और उनका महकमा दूसरा है मगर इनके वैटरिनरी डिपार्टमैंट की खाली जमीन सलूणी में पड़ी हुई थी, इन्होंने उस टाइम बहुत कॉपरेट किया और वह जमीन हैल्थ डिपार्टमैंट को ट्रांसफर हो गई। वह बिल्डिंग बन रही है। आप डलहौजी गए, सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से पांच मिनट की दूरी पर डलहौजी का अस्पताल है। आप उसको भी देख आते। अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई है मगर हमने निवेदन किया था और उसका प्रॅपोजल भी बनाकर भेजा था कि उसमें जो पुरानी Mortuary है उसके बदले नई Mortuary बनाने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है।

26.03.2018/1600/SS-HK/3

एक ऐस्टीमेट Mortuary-cum-Parking का 34 या 35 लाख का हम लोगों ने बनाकर भेजा भी था। क्योंकि पहले बिल्डिंग का काम लगा हुआ था तो हम लोग डबल चीज़ें नहीं करना चाहते थे। हम भी समझते हैं कि बजट की रेस्ट्रिक्शन होती है। बिल्डिंग अब in all respect कम्प्लीट हो गई है। डॉक्टर्ज़ के लिए जो और रैजीडेंसिज़ बने, वे भी कम्प्लीट ही होने वाले हैं। मेरा प्रश्न लगा था उसके जवाब में आपने उत्तर दिया है कि एक-दो महीने में वे

कम्प्लीट हो जायेंगे। वे बहुत अच्छे रैजीडेंसिज़ बने हैं, within the compound हैं। मगर यह भी बहुत ज़रूरी है।

अध्यक्ष महोदय, चम्बा का सबसे ज्वलंत मामला,चम्बा शहर में जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है उसका है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी अफवाहें आजकल चम्बा में चली हुई हैं। चम्बा वासियों का कंसर्न है क्योंकि चम्बा एक हैरिटेज टाउन है। 1000 साल मिलेनियम हम लोग उसका मना चुके हैं। सुनने में आया है कि वर्तमान सरकार में कोई ऐसी प्रॅपोजल चली है कि वहां का जो पुराना हॉस्पिटल है जोकि एक सांस्कृतिक धरोहर है, हैरिटेज धरोहर है, उसको तोड़ने की कोई प्रॅपोजल बनाई जा रही है। चम्बा मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए, मैं एक बार फिर अनिल शर्मा जी का ज़िक्र करूंगी कि सरोल में एक बहुत बड़ा भेड़ू फार्म था, उसकी पूरी जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर की गई। अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप इस बात को समझते हैं कि पढ़ाई ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां वातावरण अच्छा हो। चम्बा शहर में तो तिल रखने की जगह नहीं है। ये कौन ऐसी प्रॅपोजल बना रहा है कि चम्बा की जो खूबसूरत बिल्डिंग्ज़ हैं जोकि हमारा हैरिटेज/धरोहर है उसको तोड़ करके वहां पर कॉलेजिज़ बना दिए जाएं?

26.03.2018/1605/केएस/एचके/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी---

मैं नहीं समझती कि माननीय मंत्री जी के होते हुए इस तरह की कोई बात सरकार करेगी या विभाग कोई ऐसे कदम उठाएगा परन्तु मंत्री जी से यह निवेदन जरूर है कि मेरे ख्याल में कुछ पैसे मैडिकल कॉलेज बनाने के लिए विभाग को रिसीव हो चुके हैं । तो आप जल्द से जल्द सरौल में मैडिकल कॉलेज की स्थापना करने का कार्य शुरू करें। वहां पर कुछ बिल्डिंग्ज़ तो पुरानी है जो वैटरिनरी डिपार्टमैंट की थी। वहां पर वैटरिनरी वालों का रैस्ट हाउस है, कुछ दफ्तर हैं, कुछ और बिल्डिंग्ज़ हैं मगर कम से कम उसका काम तो चालू हो। हम गुलाम नवी आजाद जी के आभारी है कि उन्होंने चम्बा को मैडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। अगली सरकार आई, आप लोगों ने, माननीय नड्डा जी जो केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, कुछ पैसे सैंक्शन किए मगर उस पैसे का क्या फायदा जिसका युटिलाइजेशन न

हो रहा हो? अध्यक्ष महोदय, मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है कि उसको सरौल में न बनाकर चम्बा शहर के अंदर बना दिया जाए। गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज को तो हम चम्बा शहर से सुल्तानपुर तक ले गए इसलिए क्योंकि चम्बा बहुत ज्यादा कंजस्टिड है। It is highly congested town, न वहां उस लायक गाड़ियां जाने की सड़के हैं। मरीजों को दिक्कत आती है। जो वहां पर जोनल हॉस्पिटल है, हमारे माननीय सदस्य श्री पवन नैय्यर जी हर दूसरे-तीसरे दिन जोनल हॉस्पिटल चम्बा में जा कर वहां के मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। वहां पर एक-एक बिस्तर पर चार-चार लोग हैं और जो नई बिल्डिंग बनी है वह चालू नहीं हो पा रही है। जो हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? बनी हुई बिल्डिंग है उसमें मेरे ख्याल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नैय्यर साहब मेरे से ज्यादा जानते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ करने की जरूरत है। बैड्ज़ लगाने की जरूरत है। एक-एक बैड पर चार-चार मरीज होते हैं। चाहे वह गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे दूसरे मरीज हैं। अगर बनी हुई बिल्डिंग न हो तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा लेकिन इतनी

26.03.2018/1605/केएस/एचके/2

बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद, वह चाहे हमारे समय में चालू नहीं हो पाई या अभी तक भी चालू नहीं हो पाई है, यह दुखद बात है। कोई भी चीज़ है, it is for the welfare of the people, it is for the use of the people. इतना पैसा लगाने के बाद अगर हम उसको यूज़ न कर पाएं तो मैं समझती हूं कि it is a waste of money.

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि चम्बा की धरोहर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगें ऐसा मैं आपसे आश्वासन जरूर चाहूंगी। समय रहते, पैसा रहते आप बिल्डिंग्ज़ का काम पूरा करेंगें, स्टाफ की कमी को पूरा करेंगें, हमने भी कोशिश की, आप भी कोशिश करेंगें। कई नए अपग्रेड हुए हैं, जैसे डलहौजी में डॉक्टर्ज़ की स्ट्रैंथ बढ़ गई है, नर्सिज़ की

स्ट्रैंथ बढ़ गई है मगर पोस्टिंग्ज़ नहीं हो पाई है तो आप रैशनेलाइज़ करेंगें। आपने विक्रम सिंह जरयाल जी के प्रश्न के जवाब में भी बताया था कि कहीं पर डॉक्टर्ज़ ज्यादा हैं और वहां पर पोस्टें कम है तो उनको अगर आप रैशनेलाइज़ करेंगें कुछ राहत उससे मिलेगी कुछ आप भर्ती करेंगें। भर्ती के बारे में आपके डॉक्युमैंट में कोई जिक्र नहीं है कि क्या प्रक्रिया आप फॉलो करेंगें? कितनी पोस्टें आप इस साल भरेंगें? स्टाफ नर्सिज़ है, दूसरा पैरा मैडिकल स्टाफ है और सबसे ज्यादा कमी पैरा मैडिकल स्टाफ की है। उसको भी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने ट्रेनिंग के बैचिज़ बिठाए थे। आपके पास अब ट्रेंड लोग भी उपलब्ध होंगें। कुछ लोग जो रैकोग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स से ट्रेनिंग करके आते हैं उनमें से आप रखिए मगर कम से कम पैरा मैडिकल स्टाफ, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे प्लांट चलाने वालों की कमी को पूरा करने का प्रयास करें। एक बार फिर अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि चम्बा शहर की धरोहर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

26.03.2018/1605/केएस/एचके/3

अध्यक्षः श्री हर्षवर्धन चौहान जी।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसे कहते हैं कि "Health is Wealth" अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। विपिन परमार जी हाल ही में मंत्री बने हैं । ये नौजवान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद की जो जिम्मेदारी इनको दी गई है,

26.3.2018/1610/av/yk/1

श्री हर्षवर्धन चौहान-------जारी

ये इसमें सुधार लायेंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें यहां पर रखी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। हमारा नाहन मैडिकल कालेज यू0पी0ए0 सरकार की देन है। वहां पर दूसरा बैच बैठ चुका है और तीसरे बैच को बैठाने की तैयारी है। अभी यह कालेज जिला अस्पताल में चल रहा है इसलिए हम चाहेंगे कि उसके लिए जमीन का चयन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी मालूम है कि उसके लिए अभी जमीन का चयन नहीं हुआ है। जमीन आइडैंटिफाई करके उस कालेज के लिए एक सुन्दर भवन तैयार किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या हार्ड एरिया / ट्राइबल एरिया में पैरा मैडिकल और डाक्टरों का न जाना है। आज ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी को भेजना किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। चम्बा में भरमौर का हमारा हार्ड एरिया है, मण्डी का है, सिरमौर का है या दूसरे ट्राइबल एरिया हैं वहां पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्मचारी बहुत कम है। मेरी इस बारे में कुछ डाक्टरों से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी हाल ही में सौ-सवा सौ डाक्टरों की भर्ती हुई जिनमें से हमारे जिला सिरमौर में आपने केवल 11 डाक्टर भेजें। उन 11 डाक्टरों में से वहां केवल दो डाक्टरों ने ज्वाइन किया है। मैंने जब इस बारे में कारण जानने के लिए डाक्टरों से पूछा तो उनका कहना है कि उनको 26000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। अब मैडिकल साइड में तो ब्रीलियंट बच्चे जाते हैं और पांच साल पढ़ाई करने के बाद जब उनकी अप्वाईंटमैंट होती है तो उनको 26 हजार रुपये तनख्वाह देना मुझे लगता है कि बहुत थोड़ी राशि है। मैं चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि नौजवान डाक्टर हमारे हार्ड एरिया में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। आज प्राइवेट सैक्टर में डाक्टरों की बड़ी मांग है। प्राइवेट सैक्टर में डाक्टरों को लगते ही 50-60 हजार रुपये तनख्वाह दी जाती है, इसलिए अगर आप इसको बढ़ायेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्राइबल एरिया / हार्ड एरिया में आपने जो स्वास्थ्य संस्थान आइडैंटिफाई किए हैं उसमें इनसैंटिव

26.3.2018/1610/av/yk/2

के रूप में 10 हजार रुपये दे रहे हैं, इसको भी बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त, फिमेल हैल्थ वर्कर, मेल हैल्थ वर्कर और दूसरे पैरा मैडिकल स्टाफ की भी कमी है। मेरे चुनाव क्षेत्र शिलाई में 28 में से 23 हैल्थ सब सैंटरों में ताले लगे हुए हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक कैसे पहुंचेगी। मैं तो इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने यहां पर आशा वर्कर स्कीम को लागू किया। उन आशा वर्करों द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों को दवाइयां देना, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में गाइड करने से स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी जान आई है। स्वास्थ्य विभाग में काफी समय से पैरा मैडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है जिसमें खासकर फिमेल हैल्थ वर्कर और मेल हैल्थ वर्कर शामिल हैं। आप इनकी भी बड़े पैमाने पर भर्ती करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और ट्राइबल व हार्ड एरिया में कर्मचारी जायें। यह जो भर्तियां हुई हैं यह पिछले 25-30 साल पहले हुई हैं और आज उनमें से बहुत सारे लोग रिटायर / प्रमोट हो रहे हैं जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। हमारे पास फार्मासिस्ट्स उपलब्ध नहीं हैं जबकि आज यहां पर फार्मासिस्ट कालेज / नर्सिंग कालेज हैं जिसके कारण हैल्थ सैक्टर में वर्तमान में मैन पावर बढ़ गई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी जो नर्सिस हैं वह इंडिया में केरला के बाद नम्बर दो पर कनसिडर की जाती है। दिल्ली, मुम्बई जैसी मैट्रोपोलिटन सिटी से यहां कैम्पस में इनकी प्लेसमैंट के लिए लोग आते हैं और कैम्पस से प्लेसमैंट हो रही है। मेरे शिलाई अस्पताल में डाक्टर नहीं है। मेरे कांटी-माशवा, जाखना और कमराऊ पी0एच0सी0 में डाक्टर नहीं है और मैंने इनके नाम कटमोशन में भी दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और डाक्टरों की अप्वाईंटमैंट करें। यहां पर सुख राम जी बैठे हैं, हमारे पांवटा अस्पताल में 400-500 के बीच ओ0पी0डी0 है और वह जिला अस्पताल का मुकाबला करता है।

26.03.2018/1615/TCV/YK-1

श्री हर्षवर्धन चौहान... जारी।

मगर वहां पर डॉक्टरों की कमी है। वहां पर एनिस्थीसिया करने वाला नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट और सर्ज़न नहीं है। It has become a referral hospital. माननीय मंत्री जी पांवटा साहिब चार विधान सभा क्षेत्रों के बीच में पड़ता है, आप 3-4 डॉक्टर्ज़ वहां के लिए दे दें, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी और सुन्दर बिल्डिंग अस्पताल की बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 108 एंबुलैंस के कारण बहुत सुविधा मिल रही है और ये यू0पी0ए0 सरकार की देन है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पी0एच0सी, कफाटा में जो 108 एंबुलैंस है, वह राजपुरा ब्लॉक और पांवटा ब्लॉक में है, लेकिन वह 108 एंबुलैंस पेशैंट को शिलाई ले जाते हैं। हमने कई बार अनुरोध किया कि आप पेशैंट को शिलाई क्यों ले जाते हो, पांवटा क्यों नहीं ले जाते हैं? मैं माननीय मंत्री जी आपको लिखकर भी दूंगा और आप उनको डायरेक्शन दें कि वह सिरीयस पेशैंट्स को शिलाई के बजाय पांवटा ले जायें।

इसी तरह से बी0पी0एल0 फैमिली के जो स्वास्थ्य कार्ड बने हैं, उनको लेकर यह समस्या आती है कि वह एक साल के बाद समाप्त हो जाते हैं और फिर उनको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसलिए इन स्वास्थ्य कार्ड का रिन्यूल टाईम-टाईम पर होना चाहिए, क्योंकि जब पेशैंट अस्पताल में जाते हैं तो पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य कार्ड समाप्त हो गया है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं, अभी तो आपको बहुत लम्बा समय नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा, कि ये जो बातें मैंने यहां कही है, इन पर आप गौर करेंगे। हमारे यहां टिम्बी में नई पी0एच0सी0 खुली है। वहां पर बिल्डिंग के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह से कमरोह, पी0एच0सी0 में भी बिल्डिंग का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि मैंने जो यहां पर उल्लेख किया है, आप इन बिन्दुओं पर ध्यान देंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.03.2018/1615/TCV/YK-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने कहा कि नाहन मैडिकल कॉलेज में लैंड उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर लैंड उपलब्ध हो चुकी है। मैं भी इनकी हां-में-हां मिलाता हूं और जल्दी ही इसका काम शुरू करेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 9 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका धन्यवाद। पूरे प्रदेश में वैसे तो हमारा हिमाचल प्रदेश हैल्थ कॉशियस है। कई बार इसको ईनाम भी मिला है और पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बढ़-चढ़कर हिमाचल प्रदेश में हैल्थ इंफ्रास्ट्रैक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। इसी वज़ह से आज चाहे दूर-दराज़ का इलाका है, चाहे हमारा जन जातीय इलाका है, जहां पर आबादी बहुत कम है, वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई-कई घण्टों का रास्ता तय करना पड़ता है। आप जो नॉर्मज़ की बात करते हैं, उन नॉर्मज़ को दरकिनार करके जो हैल्थ इंस्टीच्यूशन्ज़ खुले हैं, ये वाकिय अपने आप में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आपकी सरकार बनी, आपने बहुत सारे वायदे किए और आपने एक दृष्टि पत्र भी छापा है। उसमें बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं । आपने सरकार में आते ही कहना शुरू कर दिया कि हैल्थ इंस्टीच्यूशन्ज़ फालतू में खोले गये हैं, नियमों को दरकिनार किया गया है। हम इनको बंद करेंगे। एक तरफ हमने इनको खोला था और दूसरी तरफ़ आप इनको बन्द करना चाहते हैं। ये जितने हैल्थ इंस्टीच्यूशन्ज़ खुले हैं, चाहे मेरे जन जातीय इलाकों में खुले हैं या अन्य इलाकों में खुले हैं, सभी नोटिफाईड हुए हैं, सभी पोस्टें इसमें क्रिएट की गई थी और हर प्रकार से हर काम इसमें हुआ था। आप क्या चाहते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ घर द्वार पर न मिलें? क्या आप चाहते हैं, उनको 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ें? आपको इस किस्म की सोच को ठीक करने की जरूरत है। जो काम कांग्रेस के समय में बहुत अच्छा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

26-03-2018/1620/NS/AG/1

श्री जगत सिंह नेगी ----जारी

अब आते ही आपने स्टेटमैंट दिया और यह स्टेटमैंट बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में छपा है कि हम 200 डॉक्टर्ज़ लगायेंगे। आपने एक दिन में तो यह स्कीम नहीं बनाई होगी, यह स्कीम ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के समय में थी। जब राजा साहब मुख्य मंत्री थे तो हर मंगलवार को एक वाक-इन इंटरव्यू रखा गया था। सीधा वाक-इन इंटरव्यू के द्वारा जो भी आये, अगर पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरा जाये। 200 पदों का टारगेट इसलिए रखा गया था कि हमारे आई0जी0एम0सी0 और टांडा मैडिकल कॉलेजिज़ से जो डाक्टर्ज़ बन करके आते हैं, उनकी संख्या लगभग 200 के करीब होती थी। आपने उस बात को बड़े जोरशोर से कहा और हमने सोचा पता नहीं 200 और डॉक्टर्ज़ इसके अलावा आ रहे होंगे। लेकिन बाद में जब प्रक्रिया शुरू हुई तो वही निकला जो हमने शुरू किया था, इसमें कोई नया नहीं आया है। क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में लगभग 600 से ज्यादा डॉक्टर्ज़ की कमी है? जो रिटायर हो रहे हैं, वे तो अलग हैं। मेरे हिसाब से यह कमी कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, जब तक हमारे सारे मैडिकल कॉलेजिज़ में एडमिशन शुरू नहीं होगी। डॉक्टर्ज़ की सीटें ज्यादा-से-ज्यादा बढ़नी चाहिए, तब जा करके हम बेहतर सुविधायें हैल्थ में दे पायेंगे और जो डॉक्टर्ज की कमी है, उनको खत्म कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है। आज के युग में खाली एम0बी0बी0एस0 करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। एम0बी0बी0एस0 करने के बाद पी0जी0 करना बहुत जरूरी है। तीन साल का समय पी0जी0 करने में लगता है। क्यूं न कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाये कि एम0बी0बी0एस0 के बजाय जो डायरैक्ट +2 का इग्ज़ाम पास करके आते हैं, उनके लिए यह सिस्टम बने कि वे सीधे ही चाहे 6 या 7 साल का कोर्स शुरू किया जाये और वह डायरैक्ट पी0जी0 का हो ताकि जब वे मैडिकल कॉलेज से निकलेंगे तो हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिस्ट और एम0डी0 होगें। हमें इस तरह की नई सोच पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मैडिकल यूनिवर्सिटी खोली है। हमारी मैडिकल यूनिवर्सिटी इस किस्म के नये रूल्ज़ बना सकती है। यहां पर पांच के करीब जो मैडिकल कॉलेजिज़ स्थापित होंगे, उनके माध्यम से देश के अंदर एक नयापन शुरू किया जाये ताकि हमारे पास पी0जी0 डॉक्टर्ज़ की कमी न हो। अध्यक्ष महोदय, आप पता नहीं इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश से आपको

200 से ज्यादा डॉक्टर्ज़ मिलने वाले नहीं हैं। तो क्या आप दूसरे प्रदेश में जा करके डॉक्टर्ज़ को यहां पर recruit करेंगे। विशेष तौर पर पी0जी0 डॉक्टर्ज़ की जरूरत है, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यहां पर मेरे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 25,000 रुपये मात्र हम एक डॉक्टर को दे रहे हैं। आपकी पोलिसी ऐसी है कि गौमाता के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हर बोतल से एक रुपया अलग से देना है। मैं गाय को अपनी माता नहीं मानता हूं। मैं तो मानवता को मानता हूं। मानव भूखा रह जाये और मानव को आप छत्त न दे पायें, मैडिकल ऐड न दे पायें तो यह गलत है। आप गौमाता को खाने-पीने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि दे रहे हैं और डॉक्टर को मात्र 25,000 रुपये की राशि दे रहे हैं। यह पैसा डॉक्टरों को भी दिया जा सकता है। आप गौमाता को जो पैसे देने की बात कर रहे हैं तो आप एक किस्म से यह कर रहे हैं कि सभी लोग गौमाता को बाहर छोड़ दो, अवारा कर दो। आप गौमाता को अवारा करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। यह पैसा जो आप फालतू कामों में खर्च कर रहे हैं, इस सारे पैसे को इक्ट्ठा करके हैल्थ सर्विसिज़ में लगाईये, डॉक्टरों को ज्यादा तनख्वाह दीजिये ताकि डॉक्टर्ज़ दूरदराज़ के क्षेत्रों में जाने से पीछे न रहें। जितने भी पंजाब और हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा डॉक्टर्ज़ नहीं रहने चाहिए। इसके लिए चाहे हमारी सरकार है या आपकी सरकार है, वे हमेशा वहीं नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनका जुगाड़ फिट है। वे सवेरे आयेंगे और दो घंटें अस्पताल में लगायेंगे तथा उसके बाद वे प्राईवेट प्रेक्टिसिज़ में चले जाते हैं। इन डॉक्टरों को आप हमारे इलाके की तरफ भेंजे। हम यह नहीं कहते कि आप इनको ट्राईबल एरिया में तीन-तीन साल तक रखें बल्कि आप इनको एक साल तक ही वहां रखें और एक साल के बाद उनको रिलीव कर दीजिए ताकि उनको विश्वास हो जाये कि एक साल तक काम करने के बाद मुझे पसंद का स्टेशन मिलेगा। आप इसकी शुरूआत कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि जहां-जहां पर पी0जी0 डॉक्टर्ज़ नहीं हैं, वहां के लिए आप अलग से एक टीम गठित कीजिए, जिसमें सारे स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़ हों और उनको हैलीकॉप्टर के द्वारा जो रीज़नल/डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, महीने में एक टाईम फिक्स कीजिए कि वे वहां के लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद जो ऑप्रेशन होने हैं, उसके लिए आप इनको हैलीकॉप्टर से पहुंचाईये और

डॉक्टर्ज़ को रहने के लिए वहां के विश्राम गृह में बढ़िया सुविधा दीजिये और फिर वापिस लाईये। ट्राईबल एरिया से

26-03-2018/1620/NS/AG/3

लगभग चार करोड़ से ज्यादा की राशि हर साल हैलीकॉप्टर पर खर्च होती है। हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल ट्राईबल के लोगों के लिए नहीं होता है, जनजातीय क्षेत्र में तो हैलीकॉप्टर आता ही नहीं है। पता नहीं कहां जाता है? ज्यादातर इसका प्रयोग मंत्रीगण या दूसरे लोग करते हैं। ट्राईबल के पैसे को पायलट के रूप में आप हिमाचल में ट्राईबल एरिया में शुरू कर सकते हैं।

26.03.2018/1625/RKS/AG-1

श्री जगत सिंह नेगी... जारी

पिछले सरकार के समय में एक टैली मैडिसन शुरू हुआ परन्तु इसमें एक कमी रह गई। पी.जी.आई. से टैली मैडिसन के लिए जो डॉक्टर नियुक्त किया जाता है वह अपने फिल्ड में विशेषज्ञ होता है। जैसे पूह में टैली मैडिसन है परन्तु पी.जी.आई. में जो डाक्टर बैठते हैं, वे चाइल्ड स्पैशलिस्ट हैं। वहां हमें एम.डी. की जरूरत है, हमें ऑर्थो के लिए कुछ करना है तो वे ऑर्थो का डाक्टर नहीं दे पा रहे हैं। इसमें भी आपको पी.जी.आई. वालों के साथ विचार करना पड़ेगा। पैनल्स ऑफ डॉक्टर्ज वहां पर होने चाहिए ताकि हम पहले ही फीडबैक दे दें कि हमे आज एम.डी. की जरूरत है या ऑर्थो वाले की जरूरत है। उस किस्म की बात करने की सख्त जरूरत है।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां डाक्टर्ज की ट्रांसफर होने से उनके पद खाली हुए हैं। उन डाक्टर्ज ने अपनी सेवाएं दी है और उन्हें जाना भी है। परन्तु उनकी जगह दूसरे डाक्टरों को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। जिला किन्नौर के मुख्यालय में जो क्षेत्रीय अस्पताल है, आज की तारीख में वहां पर एम.डी. नहीं है। वहां पर रेडियोलोजिस्ट नहीं है, ई.एन.टी. वाला डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से एनेस्थीसिया वाले नहीं है। वहां पर सर्जन है

परन्तु वे बिना एनेस्थीसिया के क्या काम करेगा? इसके लिए रामपुर या जो नजदीक के हॉस्पिटल हैं, जहां पर एनेस्थीसिया के डाक्टर उपलब्ध हैं, उन डाक्टरों को महीने में 3 दिन के लिए आने-जाने के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वहां पर एनेस्थीसिया से संबंधित जितने भी ऑप्रेशन होंगे वे वहां जाकर करें। (घंटी) माननीय उपाध्यक्ष जी, कटौती प्रस्ताव में तो विपक्ष का काम होता है और इसमें आपकी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2016 में क्षेत्रीय अस्पताल, रिकाँग-पीओ को काया-कल्प में 50 लाख रुपये का इनाम दिया गया। वहां पर सारी मशीनें उपलब्ध हैं। रेडियोलॉजी में 65 लाख रुपये की लागत से 3 डी अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है। लेकिन उसके लिए हैल्थ डिपार्टमैंट से पैसा नहीं लिया गया था। इसके लिए लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड से

पैसे का प्रावधान किया गया और पी.जी.आई. से पहले वहां पर उस मशीन को स्थापित किया गया। परन्तु आज उस मशीन को ऑप्रेट करने वाला कोई नहीं है। जनजातीय क्षेत्र में आप बढ़िया काम कर सकते हैं। बजट की कोई कमी नहीं है। परन्तु नैशनल हैल्थ मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्ज के लिए एक भी पैसा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। मुश्किल से 20 या 30 लाख रुपये साल में दिए जाते हैं जबकि करोड़ों रुपये अनस्पैंट पड़े हुए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज के लिए थोड़ा-सा पैसा देकर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आयुर्वेद में बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं परन्तु कुछ संस्थानों में ताले लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बहुत सारे डाक्टर्ज को ट्रांसफर किया गया। सुनम गांव में तो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी नहीं है। दाई को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। डाक्टर्ज भी वहां से ट्रांसफर करके चला गया। इसी तरह से असरंग, रिब्बा, छोटा खम्भा इन सभी जगह आयुर्वेदा के अस्पतालों में ताले लगे हुए हैं। आयुर्वेदा में तो डाक्टर्ज की कमी नहीं है। इनको वॉक-इन-इंटरव्यू के द्वारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जहां पर ऐलोपेथी

वाले डाक्टर्ज नहीं है वहां आयुर्वेदिक डॉक्टर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेदा में ऐलोपेथी की बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यहां पर सब-सैंटरों की बात हुई। सब-सैंटरों में कई जगह मेल और फीमेल दो-दो रख हुए हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां ताले लगे हुए हैं। इसके ऊपर रेशनेलाइजेशन करने की जरूरत है। वहां पर कम-से-कम एक आदमी तो होना ही चाहिए। चाहे वे मेल हो या फीमेल। दूसरा, सैनिट्री नैपकीन की बात की गई। बारहवीं तक के बच्चों से आप एक रुपया वसूल करने जा रहे हैं। फिर वही बात आ गई, गाय के लिए 17 करोड़ रुपये और सैनिट्री नैपकीन के लिए हर बच्चे से एक रुपया लेंगे। (...व्यवधान...) 17 करोड़ रुपये तो है ही परन्तु 2 रुपये बोतल का अलग से देना है। (चुटकी लेते हुए)कर्नल साहब (श्री इन्द्र सिंह) आपके कोटे का दारू भी मुझे पीना पड़ेगा तभी गौ-माता का फायदा होगा। मैं पहले पीता नहीं था या हमने अब पीना छोड़ दिया है। लेकिन गौ-माता के ऊपर आपने ऐसी पॉलिसी लाई कि अब मुझे दारू पीना पड़ेगा तभी जाकर मेरी गौ-माता मुझे स्वर्ग पहुंचाएगी और

26.03.2018/1630/बी0एस0/डी.सी-1

श्री जगत सिंह नेगी द्वारा .....जारी

अब मेरे बच्चे भी पीना शुरू करेंगे। आपकी ऐसी पॉलिसी आई है कि अब महिलाएं शराब बेचने लग गई हैं। यह राम राज्य आपका है, महिलाएं शराब बेचने लग गई। आगे- आगे देखते जाओ क्या होता है। 108 एंबुलेंस की भी यहां पर बात हुई। एक रूपया बोतल वहां भी आप ले रहे हैं। वहां भी हमारे को पीना पड़ेगा, ताकि हमारी 108 एंबुलेंस ठीक प्रकार से चले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे निचार ब्लॉक में कोई भी 108 एंबुलेंस नहीं है। कई बार विभाग से मामला उठाया और यह आश्वासन मिला कि 108 चलाएंगे। आपको 108 के नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा कि कितने अंतराल पर 108 है और कितने समय पर वह फस्ट ऐड देने पहुंचेगी। यदि वह बुलाने के 2 घंटे बाद पहुंचेगी तब तक तो मरीज की सांस ही निकल जाएगी। उसके बारे में

भी आपको सोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.03.2018/1630/बी0एस0/डी.सी-2

उपाध्यक्ष : अब कटौती प्रस्ताव में चर्चा के लिए श्री राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 पर जो कटौती प्रस्ताव हमने दिए हैं उसमें जो चर्चा हो रही है मैं उसमें शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो डॉक्टर्स की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए बाहर से वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती करने का प्रयास करें। मुझे मालूम है कि आप भर्ती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था तो लगभग 700 पोस्टें डॉक्टरों की खाली थीं। हमने मुम्बई और दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू रखा, अन्य जगहों पर भी गए। जहां से हमें अच्छे परिणाम मिले। मुझे नहीं पता कि आपने हिमाचल प्रदेश के बाहर भी वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं या नहीं? लेकिन अगर हम वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डाक्टरों को लेंगे तो हमारी काफी हद तक डाक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अगर राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ा है। कोई समय था जब यहां पर छुट-पुट डिस्पैंसरीज होती थीं या गांव में हमारे पुराने बैद होते थे वे ही ईलाज करने का काम किया करते थे। फिर कहीं पर बाद में जाकर सब सेंटर आए । आज खुशी इस बात की है कि प्रदेश का नाम बड़े-बड़े राज्यों की तुलना में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। आज हम चर्चा कर सकते हैं कि संस्थान खुल गए संस्थानों की जरूरत नहीं है । चुनाव से पहले खुल गए। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। उपध्यक्ष महोदय, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य संस्थान खोलने के

लिए मापदंड तय किए हैं। अगर हम नेशनल लैवल के मापदंडों पर चलें तो हमारे आधे संस्थान जो खुले हैं वे नहीं खुल सकते थे। भौगोलिक परिस्थति को ध्यान में रखते हुए यहां पर जरूरत के मुताबिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान खुले हैं। उसमें मैं

26.03.2018/1630/बी0एस0/डी.सी-3

आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर मान लो सब सैंटर खुलना हो तो केन्द्र सरकार का जो मापदंड है, 5,000 की आबादी में सब सैंटर खुलेगा। अगर आपका प्राईमरी हैल्थ सैंटर खुलेगा तो 25,000 की आबादी में खुलेगा। ऐसे ही उपध्यक्ष महोदय, जो हमारे अस्पताल है, चाहे वह 50 बिस्तरों का अस्पताल है चाहे 100 बिस्तरों का अस्पताल है , जिला अस्पताल है या हमारे जोनल अस्पताल हैं। इनके लिए अगर हम मापदंडो पर चलेंगे तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चहूंगा कि हम फंस जाएंगे। क्योंकि हमने मापदंड तोड़े हैं, इसलिए कि लोगों को सुविधा मिले और दूरियों को तथा भौगोलिक परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए यह सब संस्थान हमारे खुले हुए हैं।

26.03.2018/1635/DT/DC-1

श्री राम लाल ठाकुर... जारी

केन्द्र सरकार की ओर से और यहां तक जो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वह भी कई बिन्दुओं के ऊपर चिन्तित रही है। मैं यह भी रिर्कार्ड में लाना चाहूंगा कि जैसे एच0आई0वी0 पोजिटिव केसिज हैं, जो एडस की बीमारी है, इस बजट के अन्दर इसके ऊपर भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए था। लेकिन इसमें ज्याद ध्यान नहीं दिया गया है। इस के लिए वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन और केन्द्र सरकार चिन्तित है। अगर आप पिछले आंकड़े देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आज भी 600 से ज्यादा एच0आई0वी0 पोजिटिव केसिज हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एसे जो महत्वपूर्ण बिन्दू है उनको स्वास्थ्य सेवाओ में डालना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे लैपरसी इरैडिकेशन की बात थी या

टी0बी0 को खत्म करने की बात थी, इस मुल्क में बड़े पैमाने पर इसके उन्नमूलन के लिए काम चले। इसमें वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेश की मदद मिली और केन्द्र सरकार ने भी उसी के मुताबिक अपनी स्कीमें चलाई। आज मैं कह सकता हूँ की आज वह समय नहीं कि टी0बी0 से ग्रस्त मरीज को अलग रखा जाए। अब यह समय आ गया है और डॉक्टर्ज भी यह कह रहे हैं कि टी0बी0 का मरीज क्षेत्रीय अस्पताल में रह सकता है। पहले टी0बी0 के सेनेटोरियम चील के जंगलो में खोले जाते थे। आज जितनी भी बीमारियां है उनके ऊपर कंट्रोल हुआ है। जच्चा- बच्चा कार्यक्रम के अंतर्गत मां और बच्चे की रक्षा कैसे की जाए। मां को खुराक देने से लेकर बच्चे पैदा होन तक और उसके बाद बच्चा ह्रष्ट-पुष्ट हो, उसको कोई बीमारी न लगे इस तरह के अनेकों कार्यक्रम सरकार न चलाए । अभी अलग स्वरूप हो गया है। मान लीजिए मां और बच्चे के लिए 15 सौ रुपये की किट देने बात आई है। पहले भी ऐसा ही था। होस्पीटल में जो प्रसुता होती थी उसके लिए गाड़ी का प्रबंध, 700 रुपये बच्चे के लिए और कुल मिला कर 11-12 सौ रूपये मां और बच्चे के लिए दिए जाते थे । अब इस में फोक्स किया गया है और हम इसमें आगे बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की रूग्ण व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए? हमारे जितने भी बॉर्डर एरिया है वहां पर जो डॉक्टर्ज की तैनाती हुई हैं, वे या तो पंजाब से हैं या

26.03.2018/1635/DT/DC-2

हरियाणा से हैं। वे बॉर्डर एरिया में कार्यरत हैं और उनके क्लीनिक पंजाब में चल रहे हैं। उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलता है। लेकिन फिर भी वे वहां से 2 घंटे का टांका मार लेते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोबा, नैना देवी और भाखड़ा के जो एरिया है वहां पर डॉक्टर्ज ऊना की तरफ के हैं। ऊना मैं भी वही कल्चर है जो पंजाब में हैं। यह टांका मार कर चले जाते हैं और पीछे मरीज रह जाता है। ये जो डॉक्टर्ज हैं उनको हिमाचल के अंदर लगाया जाए। इसको रोकने की जरूरत है। जब उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिल रहा है तो इनको यह करने की क्या जरूरत है। आदरणीय नेगी जी यहां से चले गए, नेगी जी अपने ट्राईबल

एरिया की बात कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जितने ट्राईबल एरिया के डॉक्टर्ज लगे हैं मुझे एक नाम बता दो जो ट्राईबल एरिया में कार्यरत हो। कारण यह है कि जब डॉक्टर बनना है तब हमें ट्राईबल एरिया की रिजर्वेशन की सीट मिलेगी। जब वे एम.बी.बी.एस.,एम.डी. कर लेते हैं तो वे शिमला से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। सरकार ट्राईबल एरिया में जाने के लिए डाक्टर्ज/ फार्मासिस्ट को अतिरिक्त पैसा दे रही है। लेकिन आज वहां पर कोई नहीं जा रहा है। ट्राईबल एरिया का आदमी वहां पर रहना नहीं चाहता। हमारे होस्पिटल खाली करके उनको किन्नौर या लाहौल स्पिति भेजते हैं।

26.03.2018/1640/SLS-HK-1

श्री राम लाल ठाकुर .....जारी

उपाध्यक्ष महोदय, आज परिस्थितियों के दृष्टिगत हमें थोड़ी-सी व्यवहारिकता देखनी चाहिए। व्यवहारिकता न देखने के कारण जिले में जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां न जाकर डाक्टर्ज़ जिला अस्पतालों में या नज़दीकी पैरेफरी में बैठे हैं।

क्षेत्रीय अस्पताल की बात वहां के विधायक करेंगे, मैं अपने क्षेत्र तक सीमित रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नैणादेवी में एक कम्युनिटी हैल्थ सैंटर घवांडल नाम से है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने उसे कम्युनिटी हैल्थ सैंटर बनाया था क्योंकि पहले यह प्राईमरी हैल्थ सैंटर था। उस समय सरकार बदली और मेरे बाद नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के हैल्थ मीनिस्टर बने। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि उस समय ग्रेडिंग की गई कि यह 'ए' ग्रेड का प्राईमरी हैल्थ सैंटर है, यह 'बी' ग्रेड का प्राईमरी हैल्थ सैंटर है और यह 'सी' ग्रेड का प्राईमरी हैल्थ सैंटर होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो नैणा देवी में जो घवांडल नाम से कम्युनिटी हैल्थ सैंटर था, that was down graded. उसकी नोटिफिकेशन हो गई कि वहां एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक क्लास-IV कर्मचारी रहेंगे। वहां के कम्युनिटी हैल्थ सैंटर के लिए हमने जो पद स्वीकृत करवाए थे, उसमें डॉक्टर्ज़ की 6 पोस्टें

स्वीकृत थीं लेकिन वह सैंटर बंद हो गया। अभी हमने उसे दोबारा से चालू करवाया था और उसे 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाया था। उसकी नोटिफिकेशन हो गई है और उसके लिए कर्मचारियों के 21 पद भी स्वीकृत हो गए हैं। मेरा निवेदन यह है कि पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय वहां पर स्टैंपेड हुआ था जिसमें 125-130 के लगभग लोग मरे थे। उस समय वहां केवल एक डॉक्टर था क्योंकि the Community Health Centre was down graded to PHC. उस समय हादसे में फंसे उन लोगों को ट्रकों में भर कर आनंदपुर साहब शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर गुरुद्वारा के लोगों ने उनका प्रबंध किया। मुख्य मंत्री जी भी वहां हैलिकॉप्टर में बैठकर उन्हें देखने गए थे। क्योंकि वह हमारे स्थानीय लोग थे, इसलिए मैं भी वहां

26.03.2018/1640/SLS-HK-2

पर गया। उस समय, दूसरे दिन जब उन मृतकों को ले जाने के लिए लोग आए, तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको हैरानी होगी कि एक 12 साल का लड़का दिन-रात उन मृतकों के शरीरों के बीच में रहा क्योंकि उनको फटाफट उठाकर ट्रकों में डालकर आनंदपुर साहब ले जाया गया था क्योंकि बिलासपुर और नैणा देवी में कोई प्रबंध ही नहीं था। वह लड़का जीवित था। उसके मां-बाप उसका मृतक शरीर लेने आए थे लेकिन वह बच्चा जीवित था जिसको वह घर लेकर गए। नैणा देवी में इस तरह की परिस्थितियां हैं। वहां पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने इसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा था। यह प्रश्न संख्या 154 था। आपने उत्तर दिया कि अभी हम देखेंगे क्योंकि नए संस्थान खुले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संस्थान थोड़ा-सा पहले का खुला हुआ है, चुनाव के समय नहीं खुला है। उस समय धूमल साहब भी इसके लिए अनाऊंसमैंट करके गए थे कि इस स्टैंपेड को देखते हुए नैणा देवी के घवांडल में हम ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। मेरा यह कहना है कि इसमें राजनीति नहीं है। जो 50 बिस्तरों का अस्पताल खुला है, उसके लिए मुझे उत्तर मिला है कि नैणा देवी ट्रस्ट ने कोई रैज्योल्यूशन पास नहीं किया था। लेकिन मंत्री जी, यह रैज्योल्यूशन की कॉपी मैं आपको दे

रहा हूं। यह मीटिंग 7 जून, 2017 को हुई है और इसकी अध्यक्षता जिलाधीश ने की थी। उस बैठक में 19 लोग उपस्थित थे। सीरियल नंबर 15 पर टैंपल ट्रस्ट ने कहा है कि यह यहां पर ऐसा एरिया है जहां बहुत से लोग बाहर से आते हैं। यहां मेलों के समय लाखों लोग आते हैं इसलिए यहां पर सुविधा होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखें। माता नैणा देवी के दर्शनों हेतु लाखों लोग आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने और मापदंड देखने हों तो उनके अनुसार नैणा देवी कभी भी म्यूनिसिपल कमेटी नहीं बन सकती थी क्योंकि वहां पर जनसंख्या पंचायत से भी आधी है। लेकिन डॉक्टर परमार के समय से ही माता नैणा देवी के महत्व को ध्यान में रखते हुए नैणा देवी को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्ज़ा मिला है जो कि नार्म्ज के मुताबिक नहीं था। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके इसके ऊपर आप ध्यान देंगे और जो

26.03.2018/1640/SLS-HK-3

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। ट्रस्ट ने लिखा है कि हम 5 करोड़ रुपये इकट्ठा अस्पताल बनाने के लिए देंगे।ऐसा ही हाल मारकण्डा का है। मारकण्डा कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर में एक भी डॉक्टर नहीं था। अभी दियोथ से डॉक्टर उठाया गया और उसको बी.एम.ओ. लगा दिया।

26/03/2018/1645/RG/HK/1

श्री राम लाल ठाकुर------जारी

जुखाला में कोई डॉक्टर नहीं है। दियोट में कोई फार्मासिस्ट नहीं है। डॉक्टर बी.एम.ओ. बना दिया। इसी प्रकार से मेरा आपसे एक निवेदन है कि वहां जो गुजरात, अंबूजा सीमेंट की फैक्ट्री हैं या अभी जो जे.पी. अल्ट्राटैक के नाम से एक फैक्ट्री आई है। इनके चलते वहां रोज ही एक-न-एक सड़क दुर्घटना हो ही जाती है। पर्यटक मनाली की ओर जाते हैं, तो कोई-न-कोई दुर्घटना उस सड़क पर हो जाती है। ब्रेन हेमरेज के लिए जिन मशीनों की

आवश्यकता है, वहां पर नहीं हैं। अस्पतालों के लिए बिल्डिंग तो बन गईं, लेकिन वहां एक भी मशीन नहीं है। There is no Para-Medical Staff and Doctor. --(घण्टी)----अगर मान लो कोई रोगी वहां चला जाए, तो उसको सीधे पी.जी.आई. के लिए रैफर करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि शिमला में भी इसका इलाज ठीक से नहीं होगा। लेकिन पी.जी.आई. जाते-जाते वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए हमारे इन अस्पतालों का आप ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे यहां कोठीपुरा में एम्स की बात चली है। मैं उस विवाद में आज नहीं पड़ना चाहता। चुनाव निकल गए। अगर अब बधाई लेनी है, तो इसके लिए मुझे बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी, इसलिए चुप रहिए।

उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप लंबी बात न करें।

श्री राम लाल ठाकुर : मेरा समय और न बढ़ाएं। मैं कहूंगा कि वह जैसे मरजी खुला, लेकिन अभी खुलने में तो समय लगेगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा ने कहा है कि एक साल तो अभी उसकी ड्रॉइंग बनने में लगेगा और अभी उनका बयान आए हुए दो महीने ही हुए हैं। आज 1351 करोड़ रुपये के फट्टे वहां लगे हुए हैं और यहां बोल भी दिया, बजट बुक में भी छप गया कि 1351 करोड़ रुपये बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स खुलने के लिए केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। लेकिन जब मैं जवाब मांग रहा हूं, तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? --(घण्टी)----हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि यह केन्द्र सरकार को करना है। जमीन भी हमने दे दी और अब 150 बीघा जमीन और दी जा रही है। अगर जमीन देने के अलावा हमारा कोई काम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि पठानिया जी, उसमें धन्यवाद और मुबारक़वाद देने की क्या जरूरत रह गई? अभी लोक सभा के चुनाव आ गए,

26/03/2018/1645/RG/HK/2

तब तक मैं कहूंगा कि वहां एक भी कमरा नहीं बनेगा। सिर्फ लोगों को बताने की बात है। अभी --(घण्टी)- --एक साल तक ड्रॉइंग भी नहीं बनेगी। जब यहां जवाब मिल गया कि यह हमारा काम नहीं है, यह केन्द्र सरकार का काम है, तो बजट बुक में डालने की जरूरत भी

क्या है? जब आपने कोई पैसा ही नहीं देना है, then why it is including in the Budget Book?

उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी, कटौती प्रस्ताव आपके ही हैं और इस पर बाकी माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री राम लाल ठाकुर : इसलिए इन मुद्दों को यदि वास्तविकता और धरातल के साथ जोड़कर देखा जाए तब उसका फायदा होगा। यह कहना कि फलानी संस्था बन्द कर दो, उसको बन्द कर दो, तो मैं कहना चाहूंगा कि बंद करना बहुत आसान है, लेकिन खोलना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको श्री नैनादेवी का उदाहरण दे दिया है। अगर माता श्री नैनादेवी की तरफ गलत निगाह से आप देखेंगे, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि माता श्री नैनादेवी से डरो --(घण्टी)----और ऐसे बंद करने वाले काम न करो।

उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी, कृपया समाप्त करिए।

श्री राम लाल ठाकुर : मेरा आपसे निवेदन है कि कई बार उनका कोप भी हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में कुछ नई सोच के साथ हमारे नौजवान स्वास्थ्य मंत्री हैं, कृपा करके आप पुरानी परिपाटी पर न चलें। ये न कहें कि आपकी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया। ठीक है कि डॉक्टर नहीं थे, तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर नहीं थे।

उपाध्यक्ष : बस हो गया, अब आप बैठ जाएं।

श्री राम लाल ठाकुर : मैं कोई उनको सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़े ही खड़ा हूं। मैं कहूंगा कि आपको इसलिए चुना है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे। You are a young dynamic Minister. मेरा आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग की जो सेहत खराब हो रही है, उसको संभालना का काम है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26/03/2018/1645/RG/HK/3

उपाध्यक्ष : अब श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

26.03.2018/1650/जेके/yk/1

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक रहे तो सरकार का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश की अधिकतर जनता, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसकी उम्मीद सरकारी हॉस्पिटल होता है। वह ब्लॉक के हॉस्पिटल में जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर भी जब उसको उपचार के लिए सही ट्रीटमैंट नहीं मिलता है तो हिमाचल प्रदेश का गरीब नागरिक, आम आदमी अपना रुख चण्डीगढ़ की तरफ, दिल्ली की तरफ, पी0जी0आई, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ करता है। यह ठीक है कि प्रदेश में डॉक्टर्ज़ की कमी है। इस कमी को ठीक कैसे करना है? डॉक्टर्ज़ की कमी को पूरा करने की लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जबसे नई सरकार बनी है एक बड़ी चर्चा सामने आई है कि कांग्रेस सरकार जाते-जाते शिलान्यास कर गई। फट्टे लगा कर के चली गई। ऐसी चर्चाएं बहुत सारी यहां पर आई हैं। ..व्यवधान...मैं ज़वाब दे रहा हूं और यह सच्चाई है। आप लोग सुनिए। अगर बोलने की केपेसिटी रखते हो तो सुनने की भी रखा करो। कोई भी नया संस्थान, चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, जब भी खुलता है तो पहले फट्टा ही लगाया जाता है। उसके लिए बज़टरी प्रोविज़न किया जाता है। ऐसा नहीं है कि घोषणा करने से पहले बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, स्टाफ तैनात कर दिया जाता है और फिर सरकार फट्टा लगाती है। पहले कोई भी संस्थान खुलता है, हॉस्पिटल बनता है तो उसका शिलान्यास होता है। मुझे नहीं लगता है कि नई सरकार ऐसा करने वाली है कि पहले बिल्डिंग तैयार कर देगी, हॉस्पिटल तैयार करके दे देगी और उसके बाद फिर जा करके उसका शिलान्यास करेगी। यह प्रक्रिया पहले से ही सरकारों में चलती आ रही है। जो हमारे समय में फट्टे लगे हैं उनको आप आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी आपकी सरकार रही, आपने भी फट्टे ही टांगे थे और नई सरकार ने उनका काम आगे पूरा किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सुजानपुर क्षेत्र और

खास करके सुजानपुर नगर परिषद् का जो क्षेत्र है यह कांगड़ा और मण्डी दोनों जिलों को फीड करता है। मण्डी क्षेत्र का संधोल वाले एरिया के सारे लोग सुजानपुर आते हैं। मंत्री जी

26.03.2018/1650/जेके/वीके/2

तो सुजानपुर के नज़दीक के हैं, वाकिफ़ हैं। कांगड़ा का एरिया जिसमें जयसिंहपुर का क्षेत्र है, ज्वालाजी क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग सुजानपुर आते हैं। पिछली सरकार में माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहां सी0एच0सी0 हॉस्पिटल को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल कर दिया था। अब वहां पर बिल्डिंग बननी है और उसके लिए बजट घोषित हुआ है। उसमें रैजिडैंशियल एकोमोडेशन फॉर मैडिकल एण्ड पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए बिल्डिंग का शिलान्यास हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार उसका काम भी जल्दी से जल्दी लोक निर्माण विभाग से शुरू करवाएगी। इसके साथ चबूतरा में ज़मीन भी हैल्थ डिपार्टमैंट के नाम है, वहां पर नई पी0एच0सी0 बनी है। वहां पर वर्ष 1968 से डिमांड कर रहे थे। वहां पर पोस्टें सेंक्शन है। वहां पर भी नई बिल्डिंग बननी है। ज़मीन भी हैल्थ डिपार्टमैंट के पास है तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस काम को करेगी। मैं पहले भी डिमांड रख चुका हूं कि सुजानपुर सिविल हॉस्पिटल में जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट को प्लीड करता है, सुजानपुर को भी, मण्डी क्षेत्र को भी और कांगड़ा को भी तो यहां पर कम से कम दो स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़ होने चाहिए। इसके लिए स्वीकृति सरकार दें। एक तो वहां पर चाइल्ड स्पैशलिस्ट होना चाहिए और एक मैडिसिन का डॉक्टर होना चाहिए, जिसकी लोगों की बहुत डिमांड है। अक्सर होता क्या है कि गांव से जब लोग सुजानपुर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रैफर किया जाता है और जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर वहां से टांडा के लिए रैफर कर दिया जाता है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हमारी सबकी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं मज़बूत हों। यह आम आदमी से जुड़ा विषय है, यह गरीब आदमी से और कॉमन मैन से जुड़ा विषय है इसलिए लोगों को इसमें सुविधाएं मिले। दूसरे डॉक्टर्ज़ की शॉर्टेज़ की बात चल रही है।

26.03.2018/1655/SS-YK/1

श्री राजेन्द्र राणा क्रमागतः

मुझे लगता है कि इस बात को हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर्ज़ अक्सर सरकारी क्षेत्र से नौकरी छोड़कर जा क्यों रहे हैं। डॉक्टरों को अच्छी सैलरी सरकार देगी तो मुझे लगता है कि सरकार के पास डॉक्टर्ज़ टिकेंगे। इसलिए सरकार इस विषय पर सोचे कि डॉक्टर्ज़ को अच्छे पर्क्स दें, अच्छी तनख्वाह दें ताकि वे प्राइवेट सैक्टर की तरफ दौड़ लगाने की बजाय सरकार के पास काम करें। --(व्यवधान)-- मेरी बारी आती है तो आप बड़ी घंटियां मारते हैं। प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। सरकार जल्दी-से-जल्दी हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को चलाए। मुझे एक बात की आशंका और है। मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि हमारा आई0जी0एम0सी0/टांडा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। इस बात की आशंका है कि जो नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं वहां पर आई0जी0एम0सी0 और टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्ज़ को शिफ्ट करके भेजा जायेगा। इस प्रकार से जो वर्तमान में हॉस्पिटल चल रहे हैं इनमें डॉक्टर्ज़ की शॉर्टेज हो जायेगी। इस बात की भी सरकार चिन्ता करे, इसका ध्यान रखे।

एक हमारे पी0एच0सी0, ऊठपुर में है और वहां पर न तो डॉक्टर है, न नर्स है। मेरा हैल्थ मिनिस्टर साहब से अनुरोध है कि कम-से-कम वहां पर डॉक्टर और स्टाफ तैनात किया जाए ताकि इंटीरियर इलाके के लोगों को सुविधा मिले।

अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य, ठाकुर राम लाल जी ऐम्स की चर्चा कर रहे थे कि 1351 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। सरकार को केन्द्र में बने हुए चार साल हो गए हैं, पांचवां साल शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पांच साल भी पूरे हो जायेंगे, हम उस प्रोजैक्ट को जल्दी-से-जल्दी शुरू करें ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो बाहर चंडीगढ़, दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं लेने जाना पड़ता है उससे निजात मिले। अच्छे डॉक्टर्ज़ यहां पर तैनात हों। मैं लम्बी बात नहीं करूंगा क्योंकि उपाध्यक्ष जी बार-बार घंटियां मार रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए आप इसे और ज्यादा मजबूत करें ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे। लोगों की सेहत ठीक रहेगी तो मैं श्योर कह सकता हूं कि सरकार की भी सेहत ठीक रहेगी। अब डॉक्टरों की तैनाती और मेडिकल स्टाफ पूरा होना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता था कि जो डिस्ट्रिक्ट

26.03.2018/1655/SS-YK/2

हॉस्पिटल्ज़ हैं, जहां भी हैं, लोगों को टांडा/आई0जी0एम0एम0 या चंडीगढ़ जाने के बजाय अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज़ को स्ट्रैंथन किया जाए तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम होगा। जिला हमीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टरों की बहुत कमी है उसको भी पूरा किया जाए। वहां पर दो डायलेसिज़ की मशीनें डोनेट करवाई गई हैं और उन मशीनों को अभी तक चलाया नहीं गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि काफी लम्बा समय हो गया और एक टेक्निशियन वहां पर नहीं रखा जा रहा है। मेरे ख्याल से चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है इसलिए जल्दी-से-जल्दी वहां टेक्निशियन रखा जाए। --(व्यवधान)-- हमीरपुर में दो डायलेसिज़ की मशीनें हमने डोनेट करवाई थीं ताकि गरीब आदमी जिसको जालंधर, होशियारपुर, चंडीगढ़ जाना पड़ता है और दाएं-बाएं पैसा खर्चता है उससे निजात मिले। उसको यहां पर ही सुविधा मिले। सिर्फ एक टेक्निशियन रखना है, सरकार जल्दी-से-जल्दी टेक्निशियन रखे और वे मशीनें चालू हों ताकि लोगों को फायदा हो।

उपाध्यक्ष जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

26.03.2018/1655/SS-YK/3

उपाध्यक्षः अब श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लालः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, मैं भी उसमें बोलने के लिए अपने आपको शामिल करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो विभाग है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जनहित से जुड़ा हुआ विभाग है। अभी जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट अनुमान प्रस्तुत किये थे, उस बजट बुक के अंदर स्वास्थ्य पर इतना कुछ ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ। उसमें जो पूर्व सरकार की नीतियां/पॉलिसिज़ थीं जैसे इंश्योरैंस की बात है या कोई बीमा की बात है, ये सब बातें उसमें रिपीट की गईं है ।

26.03.2018/1700/केएस/एजी/1

श्री नन्द लाल जारी---

Private hospital facility in the rural sector यह नई चीज़ देखने में आई है। यह कई राज्यों में शुरू भी किया है परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, इसको शुरू किया गया है in the Government institutions to be taken over by the private parties . हम आग्रह करना चाहेंगें कि जब रूरल सैक्टर में प्राइवेट हैल्थ फैसिलिटी के नाम पर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्ज़ डॉक्टर जा कर वहां काम करेंगें तो जो गावं के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके इंट्रस्ट को प्रोटैक्ट किया जाएगा। Immunization campaign जो हिमाचल के अंदर चला है, मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनको मुबारकवाद भी देना चाहूंगा कि the success rate is 95 per cent. सिर्फ पांच परसेंट खींचना है, उसके लिए आपको मुबारकवाद और उम्मीद है कि i.e. measles and rubella, बाकी पांच परसेंट आपको करना है, शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे ठाकुर राम लाल जी ने कहा कि जो बड़े राज्य हैं, उनमें हैल्थ के मामले में हिमाचल प्रदेश भी काफी आगे कि पंक्ति में हैं। क्योंकि हमारी पूर्व सरकार ने हैल्थ सैक्टर में बहुत काम किया है। जो ये तीन मैडिकल कॉलेजिज़ की बात हो रही है, इसमें हमीरपुर को छोड़कर जो अभी चालू नहीं हुआ because of certain reasons बाकी जितने कॉलेजिज़ खोलने की बात है, कितने प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज़ खोले गए, कितने सी.एच.सी. खोले गए, कितने एच.एस.सी. खोले गए जिनकी वजह से आज गांव के और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। आज हमें आपसे यही कहना है कि ये जो हैल्थ सब सैंटर्ज़ हैं, पोलियो ड्रॉप्स के लिए मेल एण्ड फीमेल हैल्थ वर्कर अगर दो नहीं है तो कम से कम एक अवेलेबल हो ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। इसी तरह से जो दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज़ हैं, वहां डॉक्टर्ज़ नहीं है, वहां उनकी कमी को पूरा किया जाए । ये सभी कमियां पूरी करना सरकार का काम है। अभी जैसे काफी चर्चा

भी चली है कि 200 डॉक्टर्ज़ भर्ती किए जा रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, अभी सरकार का जो पॉलिसीज़ or प्रोसिज़र रहा है कि एक तो डॉक्टर्ज़ वॉक इन इन्टरव्यू से लिए जा

26.03.2018/1700/केएस/एजी/2

रहे थे दूसरे, कमिशन के थ्रू लिए जा रहे थे और काफी इन्सैंटिव्ज़ भी दिए जा रहे थे मगर फिर भी डॉक्टर्ज़ की कमी है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इन इन्सैंटिव्ज़ को और बढ़ाया जाए ताकि हमारे पास नए-नए डॉक्टर्ज़ आएं और स्वास्थ्य संस्थानों में उनके पदों को भरा जा सके। इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। इसी तरह से हिमाचल में फार्मासिस्टों की भी बहुत कमी है। उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। अधिकतर प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज़ में आपको फार्मासिस्ट के खाली पद मिलेंगें। मैं चाहता हूं कि इन पदों को अगर सरकार भर दें तो यह सरकार का बहुत बड़ा कदम होगा। मैं मानता हूं कि if Doctor is not available in the interior तो वहां पर कम से कम फार्मासिस्ट थोड़ा बहुत रिलीफ तो लोगों को दे सकता है। इसलिए उनके पदों को भरने के बारे में सरकार गम्भीरता से सोचे। इसी तरह से नर्सिज़ के पद भी खाली पड़े हैं। उनकी भर्तियों को भी ठीक किया जाए क्योंकि trained Nurses are available. बैच वाईज़ या कमिशन के थ्रू, जैसे भी सरकार को करना है, करें ताकि जो हमारी ट्रेंड नर्सिज़ जो अपने घरों में बेकार बैठी हैं, उनको जॉब भी मिल जाए और रिक्तियां भी भर जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रामपुर के अस्पताल में sanctioned strength of Doctors is 31. Today it is not even 50 per cent. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि immediately after the formation of the Government the only Radiologist available in the hospital was shifted to Shimla just to benefit a particular individual जिसका तो प्राइवेट में अपना अल्ट्रासाऊंड का कारोबार चलता है आज 100 प्रतिशत लोग वहां जा रहे हैं और वह अच्छी कमाई कर रहा है । हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वहां पर रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जाए ताकि वहां पर अल्ट्रासाउंड के केसिज़ सरकारी तौर पर हो और जो डॉक्टर्ज़ की वेकेंसिज़ हैं,

26.3.2018/1705/av/ag/1

श्री नन्द लाल -------जारी

कई महीनों से Eye सर्जन नहीं है। आई ओप्रेशन के लिए हमारे लोगों को शिमला आना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि वहां पर जल्दी-से-जल्दी Eye सर्जन की पोस्ट को फिलअप किया जाए। आजकल इतने ऐक्सिडैंट हो रहे हैं जिसके मद्देनजर वहां पर एक ट्रामा सैंटर बन रहा है। उस ट्रामा सैंटर के काम को भी ऐक्सपीडाइट किया जाए। रामपुर में 200 बैडिड होस्पिटल है मगर वहां पर दो सौ बैड्स फंक्शनल नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा रश रहता है और वहां केवल रामपुर के लोग ही नहीं बल्कि किन्नौर, आउटर सराज, कुमारसेन इत्यादि क्षेत्रों के लोग भी आते हैं जिसके कारण वहां हमेशा दो सौ से ज्यादा पेशैंट एडमिट रहते हैं। अगर आप आजकल जाकर देखेंगे तो वहां पर एक-एक बैड पर दो-दो, तीन-तीन पेशैंट हैं। इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि उस दो सौ बैडिड होस्पिटल को दो सौ बैड्स के लिए फंक्शनल कर दें और whatever has to be done for additional accommodation, please do that. इसी तरह से सी0एम0रिलीफ फंड के बारे में माननीय अग्निहोत्री जी ने सुझाव दिया था कि एक नीति बनाई जाए। हार्ट सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि केसिज में टोटल बीमारी के लिए एक नीति बने so that the people know it. क्योंकि हो यह रहा है कि मान लो एक लाख रुपये का खर्चा है और सी0एम0 रिलीफ फंड से 70 या 80 हजार रुपये मिल गये। एक गरीब आदमी 70 या 80 हजार रुपये में ओप्रेशन नहीं करवा पाता। इसलिए इसके लिए एक नीति बने ताकि हमारा गरीब आदमी/ पेशैंट अपना ईलाज समय पर करवा सकें। इस बुकलैट में आयुर्वेदा के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि हमारे यहां पर जो आयुर्वेदा होस्पिटल की बिल्डिंग का काम चला हुआ है उसको ऐक्सपीडाइट किया जाए और यह तकरीबन कम्पलीशन स्टेज पर है। इसलिए इसको पूरा करने के आदेश दिए जाएं ताकि इसको फंक्शनल किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग को बहुत कुछ करने की जरुरत है and today the dignity of the Health Department in the big States is supposed to be number one in the country. इस स्टेटस को मेन्टेन करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरुरत है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि

स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा स्ट्रैंथन करने के लिए जो कुछ कदम उठा सकते हैं, आप उठाएं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

26.3.2018/1705/av/ag/2

डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का विषय अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य श्री राम लाल जी, नन्द लाल जी ने जो इस पर अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि वह अपने आपमें बहुत मायने रखते हैं। हमारे शीर्ष नेताओं ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसके कारण हमारा प्रदेश एक अग्रणी राज्य में गिना जाता है। चाहे वह आज के आदरणीय नेता हों या हमारे लोकप्रिय माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और केंद्र में श्री गुलाम नबी आजाद जी हों। हमारे राज्य के लिए एम्स और तीन मैडिकल कालेज आए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सब प्रयत्नशील रहे हैं और बहुत सारी अच्छी ऊंचाइयां भी छुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चाहे आशा वर्कर हैं या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं; ये केंद्र की स्वास्थ्य सम्बंधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी आज हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में डाक्टरों का न जाना या तैनात न होना है।

26.03.2018/1710/TCV/DC-1

डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल... जारी।

मैं जब मैम्बर पार्लियामैंट था तो मैंने संगड़ाह में देखा कि वहां कई कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर हैं, परन्तु वहां पर अच्छे डॉक्टर काम नहीं करना चाहते हैं। मैं जब इसकी गहराई में गया तो मैंने पाया कि उनके पास रहने के लिए ठीक सुविधा नहीं है। मैंने उनके लिए एम0पी0लैड से रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई और वे रहे भी। परन्तु बड़ी मुश्किल से एक साल ही रहे

होंगे। उसके बाद वे फिर बदल गये, क्योंकि वे बाहर के रहने वाले थे। लेकिन वहां पर अच्छे डॉक्टरों की तैनाती होना आवश्यक है। We have young and dynamic Health and Family Welfare Minister, ये सोलन हॉस्पिटल गये, उसका मुआयना किया, धरातल पर जो समस्याएं नज़र आई, उनके लिए ये प्रयास भी कर रहे हैं कि वे ठीक हों। लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पर कितना बड़ा प्रैशर है। वहां की जनता उसे बड़े पॉपुलर हॉस्पिटल की संज्ञा देती है। वहां पर जिला शिमला, सिरमौर और वहां की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वह इतनी ज्यादा है कि कितना ही काम डॉक्टर करें उसके बावजूद भी उन पर प्रैशर बना ही रहता है। उनकी कई बार कंप्लैंट्स भी आती रहती है। मैं स्वयं भी कई बार वहां जाता रहता हूं। I am so grateful to the Hon'ble Minister that he went there. Despite that हम क्यों नहीं किसी चीज की जड़ में जाते हैं और वह है फीडर सिस्टम। अगर नौणी की तरफ से ठीक प्रकार के प्राइमरी हैल्थ सैंटर हो, कण्ड़ाघाट की तरफ से अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो तो कैसे प्रैशर कम नहीं किया जा सकता है। मुझे दुःख से कहना पड़ता है, । don't know for what reason but the construction work of hospital at Kandaghat is withheld. मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना भी करूंगा कि उसे रिव्यू किया जाये क्योंकि almost 50 percent of the construction work of that hospital has already been done and the work done is very good. उसे ठीक तरीके से आगे ले जाना चाहिए। अगर उसमें कोई और समस्या है, उसको ठीक करके अगर हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो यह जनहित में होगा। जहां तक डॉक्टरों की ट्रेनिंग का सवाल है, जो यंग डॉक्टर्ज़ हैं, उनको इंसैंटिव दिए जाये। मैं समझता हूं Col. Inder Singh is here he knows it very well that in Indian Army they are working,. I was myself in

26.03.2018/1710/TCV/DC-2

Siachen area and I had 6 doctors with me. आर्मी उनको अच्छी सुविधाएं देती हैं इसलिए उनको किसी भी कठिन परिस्थिति में, यदि 18-19 और 20 हजार की हाईट में भी जाना पड़े तो वह सिलैंडर लेकर जाते हैं। इसके बाद वहां काम होता है। हमें अपने बच्चों

को सुविधाएं देने चाहिए। We should provide them good motivational trainings so that they go in different areas and serve our people. The shortage of doctors जैसे माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी ने कहा कि हमारे यहां फार्मासिस्ट्स की कमी होती है, paramedics कमी होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत दूर-दूर के इलाके हैं। मैंने सोलन (बाईपास) में एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेशन दी है और माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने स्वयं इसे कबूल किया कि यह बनेगा। ताकि हॉस्पिटल पर जो प्रैशर है, वह कम हो। इससे लोगों को पी0जी0आई0 और टांड़ा नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास स्प्रैड-आउट एरिया- कुफ्टू, कनैर, सायरी, ममलीग और दूसरी तरफ छावसा, चैल और नौणी है। मेरी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से विशेष प्रार्थना रहेगी कि please, make this Nauni PHC functional क्योंकि लैंड दी जा चुकी है, इसमें ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ इसको खोलना बाकी है।। shall be grateful for this act and it will help us in feeder system. माननीय उपाध्यक्ष जी यदि आप थोड़ा-सा समय दें। My final suggestion, मैं चाहूंगा कि हमारे पाठयक्रम में बच्चों के लिए ये चीजें सिखाई जाएं like first aid, dog bite and snake bite. कोई बूढ़ा चल रहा हो और वह गिर जाय उसको resuscitation की जरूरत हो।

26-03-2018/1715/NS/DC/1

डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल ----जारी

mouth to mouth resuscitation, it is a very simple thing. These are very little things. This is my request from the Hon'ble Health and Family Welfare Minister that if we put them into our syllabus, they will support our Medical System and we will have very vibrant population. In other countries like Australia and England this is being practiced , so why can't we do it here. In the end I would like to say that this is joint responsibility of each one of us, rather than saying यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ कि बजाय जो काम हैल्थ में फैमिली वैल्फेयर का है, उसको एक मिशन के रूप में किया जाये। मैं समझता हूं कि इसमें जो हमने स्थान पाया है,

हिमाचल प्रदेश उसमें कायम रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26-03-2018/1715/NS/DC/2

उपाध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्याः 9 के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं देश की स्वास्थ्य स्थिति पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर यह कहना जरूरी है कि बहुत दुःख का विषय है कि आज हमारे राज्य का इन्वैस्टमैंट जो हम स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं, दुनिया के देशों की तुलना में हम लगातार नीचे आ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, I am subject to correction. बांगला देश से भी नीचे आ गये हैं। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण यह जो नारा हम बार-बार देते हैं " minimum government and maximum governance" यह बीमारी स्वास्थ्य की बीमारी उत्पन्न होती है। जब आप स्वास्थ्य को निजी हाथ में देने की सिफारिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सबसे खतरनाक प्रश्न है। मैं जानता हूं कि हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यंग ही नहीं हैं बल्कि विश्वविद्यालय में हम साथ रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ़ बहुत जोर से बोलते रहे हैं। मैं इनसे यही उम्मीद करता हूं कि हम जो कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की समस्याओं का हल निजीकरण में आगे बढ़ करके निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि यह इनके विचार के भी विरूद्ध है और इससे यह बचेंगे। इसलिए बचेंगे क्योंकि जितनी भी रिपोर्टस आज आती हैं, मैं यहां पर उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन चार साल पहले "ट्रिब्यून" ने पांच अलग-अलग डेट्स की अखबारों में निकाला था कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य का निजी अस्पताल क्या हाल करते हैं? मैं समझता हूं कि यह इसका हल नहीं है। इसका हल यह है कि जब तक हम राज्य की इन्वेस्टमैंट इसमें नहीं करेंगे, इसका हल नहीं निकल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां पर एक और विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हम बार-बार इसका ज़िक्र कर रहे हैं कि जैनरिक-जैनरिक। मैं confident नहीं हूं। लेकिन इस पर आपको पुर्नविचार करना होगा। हां, यह सही है कि दवाईयों का मूल्य कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जब हम जैनरिक के प्रश्न में चले जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम मरीज़ के

साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके सामने एक कल्पना पैदा कर रहे हैं, वह उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसकी बीमारी के लिए ठीक नहीं है। उसकी दवाई क्या लाइन ऑफ

26-03-2018/1715/NS/DC/3

करनी है या ट्रीटमैंट करनी है, इसके लिए डॉक्टर सबसे बैस्ट ज़ज है कि first line of treatment या second line of treatment होगी या advance line of treatment होगी, कौन-सी दवाई रिस्पोंड करेगी? यह हम तय नहीं कर सकते हैं। यह विषय डॉक्टर का है, विशेषज्ञ का है और अगर हम यह दायरा उस तक ही छोड़ें और इसमें हस्तक्षेप न करें तो मैं समझता हूं कि यह पूरे सदन और प्रदेश के लिए बेहतर होगा। लेकिन बार-बार जैनरिक-जैनरिक कहना मैं समझता हूं

26.03.2018/1720/RKS/HK-1

श्री राकेश सिंघा...जारी

यह ठीक नहीं है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। कुछ विषय में मेरे साथी कह चुके हैं इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। जब तक हम निचले स्तर पर स्वास्थ्य को मजबूत नहीं करेंगे तो सारा प्रेशर स्टेट हॉस्पिटल पर आ जाता है। निचले स्तर पर जो आशा वर्कर्ज है, वे ग्रास रूट लैवल पर स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। उनको हम इक्विप कर सकते हैं और उनकी इक्विपमैंट इस पर भी निर्भर करती है कि हम उनको क्या रिम्युनरेशन दें। क्या यह आज की तारीख में सम्भव है? क्या कोई अपना और अपने परिवार का गुजारा मात्र 1250 रुपये के इंसैंटिव पर कर सकता है? यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। उसे महीने के अंत में यह इंसैंटिव मिलेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसको भी मिनिमम दायरे में लाने की जरूरत है। जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यदि हम सर्विस

प्रोवाइडर को वेतन देंगे, वेजिज़ देंगे, अलाउंसिज देंगे तो वे हमे एक बढ़िया परिणाम दे सकते हैं। परन्तु मात्र 1250 रुपये में रखेंगे तो मैं समझता हूं यह एक भद्दा मज़ाक है।

कुछ बाते मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं। यहां पर कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य एडवांस हुआ है। मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोटगढ़ का अस्पताल अंग्रेजों के समय का है। उस समय मरीज को खाना भी प्रदान करते थे। आज बिस्तरे खाली पड़े हैं। मरीज़ जाते नहीं है। आपको जो सुपोर्टर स्टाफ चाहिए, टैक्निशियन स्टॉफ चाहिए, एक्स-रे मशीन चाहिए, टैस्ट मशीन चाहिए, जब तक ये चीजें उपलब्ध नहीं होगी तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोटीघाट के अस्पताल की जमीन को हम आज भी हैल्थ डिपार्टमैंट के नाम नहीं कर सके हैं। वह जमीन फोरैस्ट विभाग के नाम है। वहां तक

26.03.2018/1720/RKS/HK-2

सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है कि यह अस्पताल जंगल में बना है। । इसलिए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी मैं आपसे विनती करूंगा कि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, चाहे वे डाक्टर्ज, नर्सिज, तकनीशियन या सुपोर्टर स्टाफ के हैं, इनकी भर्ती के बिना हम अपने स्वास्थ्य को हल नहीं कर सकते। अभी चर्चा चली थी कि सरकार का ग्राफ कहां है? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि किसी भी सरकार का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा यदि हम हैल्थ, शिक्षा, पानी, बिजली में सर्विस प्रोवाइडर नहीं देंगे। आप चाहेंगे कि हमारा ग्राफ ऊपर जाए, वह नहीं जा पाएगा। लोग बड़ी जल्दी हमें नीचे ले आएंगे। आप 15 साल का स्वपन देखते हो वह अच्छी बात है। लेकिन वह तभी सम्भव होगा जब हम सर्विस प्रोवाइडर की भर्ती करेंगे। बिना भर्ती किए जो पार्लियामैंट के चुनाव आएंगे, वह तय कर देंगे कि आपकी ग्राफ कहां है? यदि आप सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइड करेंगे, रिक्रूटमैंट करेंगे तो यह सम्भव हो सकता है। लेकिन बिना भर्ती किए हुए यह सम्भव नहीं है। जो स्वपन आप देख रहे हो, वह स्वपन कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस पर काम करें तभी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। मैं समझता हूं

आप समझदार है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.03.2018/1725/बी0एस0/एच.के-1

उपाध्यक्षः अब श्री पवन कुमार काजल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री पवन कुमार काजलः माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार से सम्बन्धित है, इस कटौती प्रस्ताव में चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी ने अपने -अपने विचार यहां पर रखे। मैं एक बात कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में जो भी अस्पताल हैं, खासकर हर चुनाव क्षेत्र में जो सिविल अस्पताल है कहीं पर क्षेत्रीय अस्पताल हैं। जहां तक मेरी समझ है उन अस्पतालों में डाक्टर्स की पूरी संख्या हो। डाक्टर्स की जितनी पोस्टें हैं वह भरी हुई होनी चाहिए। वहां जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं उनमें जंग न लगा हो, वहां पर रेडियोलॉजिस्ट हों और एक्स रे की मशीनों पर टक्नीशियन हो। पूरे प्रदेश में चाहे वह क्षेत्रीय अस्पताल हैं चाहे वह सिविल अस्पताल है उन्हें संट्रेग्थन करने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरे प्रदेश की जनता भी जानती है। खास तौर से मैं अगर अपने कांगड़ा की बात करूं, वहां पर 8 स्वीकृत पोस्टें डाक्टरों की हैं। लेकिन अभी वहां पर 4 डाक्टर्स हैं और चारो ही महिला डाक्टर हैं। हम महिला डाक्टर्स का सम्मान करते हैं। चारों की चारों एम.बी.बी.एस हैं, कोई भी डाक्टर वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी चुनाव क्षेत्रों में सिविल अस्पताल है या क्षेत्रीय अस्पताल है, उन्हें स्ट्रेग्थन करने की जरूरत है। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, जो बड़े-बड़े नेता लोग हैं उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्रों में 4-5 पी.एच.सी. खोल रखी हैं और सब सैंटर खोल रखे हैं। जिन पी.एच.सी. में दो-दो डाक्टर्स एम.बी.बी.एम हैं, वहां पर ओ.पी.डी. को भी चैक करने की आवश्यता है। वहां पर कितनी ओ.पी.डी. होती हैं। यह बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो झोली छाप

डाक्टर उन्हें कह सकता हूं, उनकी ओ.पी.डी. 100 तक पहुंच गई है और सरकारी पी.एच.सी. में ओ.पी.डी. की संख्या 10 हो गई है। इसके लिए हमें चिन्तन करने की जरूरत है। इसी

26.03.2018/1725/बी0एस0/एच.के-2

तरह जो हमारे छोटे-छोटे सब सैंटर हैं उनकी ओ.पी.डी. हो गई 150 और कई जगह हो गई 5 इसके लिए भी आपको विचार करना होगा। यह ठीक है, डाक्टर्स की कमी है। मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे भी जिला कांगड़ा में हमें मार इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां टांडा मैडिकल कालेज नजदीक है। जब भी कांगड़ा में डाक्टरों की बात करें तो बोलते हैं कि कांगड़ा टांडा से नजदीक है। आज की डेट में पिछले 4-5 सालों में जो भी वहां पर प्रतिदिन की ओ.पी.डी. थी वह 900-950 की ओ.पी.डी. होती थी। आज की तारीख में वहां पर 250-300 तक की ओ.पी.डी. सीमित होकर रह गई है। यह ठीक है कि कांगड़ा से टांडा मैडिकल कॉलेज नजदीक है परंतु जो 700-800 मरीज सिर दर्द व बुखार के लिए टांडा मैडिकल कॉलेज जाता है वह भारी पड़ जाता है। हमरे जो नूरपुर से कोई अपनी गम्भीर बीमारी के ईलाज के लिए आ रहा है या जयसिंहपुर से आ रहा है या कहीं और जगह से आ रहा है उन्हे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप चुनाव क्षेत्र वाईज इन्हें स्ट्रेंग्थन कीजिए। क्या आपके अस्पतालों में पूरे डाक्टर्ज हैं? क्या आपकी जो एक्सरे की मशीन है वह ठीक से काम कर रही है?

26-03-2018/1730/DT/YK/1

श्री पवन कुमार काजल ----जारी

क्या वहां पर टेक्निशियन है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार सालों में वहां पर लगभग 900-950 व्यक्तियों की ओ0पी0डी0 थी। आज यह घट करके 200-250 के बीच रह गई है। इसका बोझ कहां पड़ रहा है? इसका बोझ टांडा मैडिकल कॉलेज में पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर मैडिकल कॉलेज़िज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। जैसे टांडा मैडिकल कॉलेज, कांगड़ा में है वैसे ही मैडिकल कॉलेज हमीरपुर और चम्बा में भी खुलना चाहिए। आज बड़ी मुश्किल से टांडा मैडिकल कॉलेज एस्टैबलिश्ड हुआ है। आपको पता है कि जब यह कॉलेज नया-नया खुला था तो वहां पर डॉक्टर्ज़ नहीं जाते थे, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। आज वहां पर सुविधायें भी मिल रही हैं। आप इन डॉक्टरों को मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर या चम्बा में शिफ्ट कर देंगे तो यह गलत होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा न करें। आपने टांडा मैडिकल कॉलेज से 16 डाक्टर्ज़ हमीरपुर के लिए या अन्य क्षेत्रों के लिए शिफ्ट किये हैं, लेकिन वे अभी नहीं गये हैं। उनका यह मानना है कि हम यहां से नहीं जायेंगे और अगर जाना पड़ा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टरों को ऐसी सुविधायें दी जायें ताकि ये नौकरी छोड़ कर न जायें। ऐसी सुविधायें होनी चाहिए ताकि हमारे अस्पताल स्ट्रैन्थन हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा कि जो नर्सिज़ जी0एन0एम0 या बी0एस0सी0 करके लगी हैं, प्राईवेट अस्पताल 10-10 घंटें उनकी सेवायें लेते हैं और उनको तीन हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं। इसके लिए भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि कैसे हम इनकी सेवायें सरकारी संस्थानों में ले सकें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26-03-2018/1730/DT/YK/2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेलः उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हैल्थ के ऊपर चर्चा चल रही है, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह सबसे जरूरी विभाग है। इस विभाग की जब हम बात

करते हैं तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ हरेक अस्पताल/पी0एच0सी0 में सबसे पहले सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने पालमपुर के अस्पताल में सफाई के कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। यह माननीय मंत्री जी का भी अस्पताल है और बाकी अस्पतालों से ज्यादा साफ-सुथरा है। मैं समझता हूं कि जो बाकी स्थान हैं, वहां पर भी किसी-न-किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी जरूर हो और हरेक अस्पताल में सफाई की सुविधा हो। इसके लिए मैं समझता हूं कि बज़ट में कुछ-न-कुछ प्रावधान करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले यह अस्पताल 100 बैडिड था, फिर इसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 150 बैड का किया था और पिछली सरकार ने पालमपुर के अस्पताल को 200 बैड का कर दिया है। पिछली सरकार में जब यह 200 बैड का हुआ तो वहां पर सी0टी0स्कैन की सेवा भी उपलब्ध करवाई गई थी, इसका काफी लोगों को लाभ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गुज़ारिश करना चाहूंगा कि पालमपुर के अस्पताल में डायलिसीज़ की मशीन रखी गई है। लेकिन इस मशीन को अभी तक चालू नहीं किया गया है। आप इसको जल्दी-से-जल्दी चालू करवायें। आप इसे इतफ़ाक की बात कह लीजिये कि पिछले तीन या चार महीनों में

26.03.2018/1735/SLS-YK-1

श्री आशीष बुटेल .....जारी

पालमपुर विधान सभा क्षेत्र में मैं कम-से-कम ऐसे 10 लोगों को जानता हूं जिनकी डायलिसिज न होने के कारण किडनी फेल्योर से मौत हो गई है। डायलिसिज करवाते थे लेकिन इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। कई जालन्धर में करवाते थे और उन्हें हफ्ते में कभी 2 बार डायलिसिज करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। अगर पालमपुर अस्पताल में ही डायलिसिज की सुविधा होगी तो निश्चित रूप से कई जाने

बचेंगी भी और लोगों को अच्छा उपचार भी उपलब्ध हो पाएगा; उपचार उनको सस्ता और नज़दीक में मिलेगा, यह मेरा मानना है।

अभी हाल ही में जब पदम श्री डॉ. रणदीप गुलेरिया जी, जो कि कांगड़ा से ही हैं, उन्हें पदमश्री से नवाजा गया था। आदरणीय शांता कुमार जी, जो हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, पालमपुर में उनके लिए एक दिन का फैलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा था जिसमें आप भी मौजूद थे और मैं भी वहीं था। महोदय, उस प्रोग्राम में एक बात आदरणीय शांता कुमार जी ने बहुत खुल कर रखी। जो विवेकानंद मैडिकल रिसर्च ट्रस्ट (VMRT) है, उसके अंदर एक जे.पी. द्वारा चल रहा अस्पताल है और एक कायाकल्प का नैचुरोपैथी संस्थान है। उन्होंने एक बात रखी कि एम्ज के जो हमारे डायरैक्टर हैं जो हिमाचल से हैं, वह भी किसी-न-किसी तरह से उसमें कोई सहयोग दें और कुछ-न-कुछ वहां पर आए।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार भी एम्ज में बात करे और यह कहे कि जो ट्रौमा सैंटर की एक पौलिसी है, जिसके अंदर 50 किलोमीटर के रेडियस में हरेक जगह पर एक ट्रौमा सैंटर होना चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर पालमपुर भी आ जाता है क्योंकि जोगिन्द्रनगर से लेकर टाण्डा तक का एरिया उस रेडियस में आएगा। अगर VMRT में ही हमें एक सरकारी ट्रौमा सैंटर मिल सके तो मुझे लगता है कि उससे कई लोगों को, चाहे किसी तरह का भी ट्रौमा हो, उसमें लोगों की जाने बच सकती हैं। मेरा यह भी मानना है कि आपने जो बजट में प्रावधान किया है, आपने 29 करोड़ रुपये से 6 ट्रौमा सैंटर्ज़ बनाने की बात की है। मैंने पिछली बार भी आपके सामने यह बात रखी थी, उसमें 5 करोड़ रुपये की लागत से अगर आप एक ट्रौमा सैंटर

बनाएंगे तो शायद वह राशि कम है। मुझे लगता है कि उतनी राशि से एक MRI की मशीन भी नहीं आएगी। अगर हम लोग यह नहीं कर पाएंगे तो ट्रौमा सैंटर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

मुझे लगता है कि पालमपुर के अस्पताल में अभी जो स्पैस्लिस्ट्ज हैं वही अभी नाईट ड्यूटि और कैजुल्टी सर्विसिज दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कैजुल्टी सर्विसिज के लिए अलग डॉक्टर्ज़ अप्वायंट किए जाएं ताकि जो स्पैस्लिस्ट्ज हैं, उनको कम-से-कम तभी बुलाया जाए जब कोई ऐसा केस आ जाए जहां उनकी ज़रूरत हो। अगर नाईट ड्यूटि के समय या कैजुल्टी में कोई ऐसी पर्टिकुलर पेशैंट वहां पर आता है तो उसको एक MBBS डॉक्टर भी ट्रीट कर सके और स्पैस्लिस्ट की वहां पर ज़रूरत न पड़े। स्पैस्लिस्ट को बहुत रेयरली और सोच-समझ कर ही यूज किया जाए, मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए।

मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा and, I quote "Further these benefits are extended to other families under the "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme" with a suitable premium". I would like to say here, Sir, कि पिछली सरकार ने जिसमें राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, एक "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme" निकाली थी जिसके अंदर 365 रुपये के हिसाब से एक प्रीमियम लिया जाना था। अब अगर हम इसको एक्सटैंड कर रहे हैं और यह लाभ बैनेफिसरीज को दे रहे हैं, it is not clear. What is the suitable premium that you are talking about? The premium can be of any amount, it can be Rs. 1000 or Rs. 10,000. It is not mentioned here कि यह प्रीमियम है क्या? इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, there is scarcity of technicians and other paramedical staff. It is not only in Palampur, but it is all over the State. हमारे जितने भी हैल्थ सब-सैंटर्ज़ हैं वहां पर आधे समय ताला लगा रहता है। वह इसलिए क्योंकि वहां पर स्टॉफ की उपलब्धता नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही गुज़ारिश करूंगा कि वहां पर जल्द-से-जल्द और स्टॉफ उपलब्ध करवाएं। आदरणीय नन्द लाल जी ने भी यही बात आपके सामने रखी कि स्टॉफ, विशेषकरफार्मासिस्ट्ज की भर्ती जल्दी-से-जल्दी की जाए ताकि हर जगह पर यह स्टॉफ उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय,

26/03/2018/1740/RG/AG/1
श्री आशीष बुटेल------जारी

अभी डॉक्टर्ज की सेलरीज़ की बात चली थी। अध्यक्ष महोदय ने अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा था, तो वहा भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य

मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने तो यह बताया कि हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह कहा है कि there is no restriction on the salaries that will be given to the Doctors. उन्होंने कहा कि आप अपना वेतन निर्धारित कीजिए और उस वेतन से अपने डॉक्टर्ज को दीजिए। लेकिन यदि ऐसा है तब भी डॉक्टर्ज नहीं आ रहे, then I think we are lacking somewhere and we must see कि हमारे पास डॉक्टर्ज क्यों नहीं हो पा रहे हैं या क्यों नहीं आ पा रहे? इसके बावजूद भी कि हम वेतन पूरा दे रहे हैं या और वेतन दे सकते हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, ---(घण्टी)----मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अरली डायग्नोसेज की बात करनी चाहिए। आधी बीमारी विशेषकर जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर लाईलाज बीमारियां हैं। वे तब ट्रीट हो सकती हैं जब उनका अरली डायग्नोसेज हो सके। जिस तरह से आदरणीय श्री राकेश सिंघा जी ने कहा कि हम आशा कार्यकर्ताओं को तो 1250/-रुपये महीने दे रहे हैं। इस पैसे से वे किस-किस के पास जाएंगी, क्या-क्या बताएंगी और क्या-क्या कर पाएंगी? यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन हमको यह जरूर देखना है कि उस स्तर पर हम लोग अरली डायग्नोसेज के लिए कम-से-कम उनको इतना इक्विप कर सकें ताकि वे जाकर कैंसर के बारे में बता सकें या जो भी लाईलाज बीमारियां हैं, उनके बारे में कम-से-कम लोगों को जागरुक कर सकें। जिससे हमारे अस्पतालों में भीड़ कम हो और रोगियों की फर्स्ट स्टेज पर ही डायग्नोसेज हो सके ताकि आगे जाकर उनका इलाज हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26/03/2018/1740/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब श्री सतपाल सिंह रायजादा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह रायजादा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे दो दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऊना आए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि वहां पर जो राजा साहब ने पी.एच.सी. वसोली दी थी और उसमें पैसा भी आ गया था, वहां आप उसका शिलान्यास करेंगे। क्योंकि उसमें जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है। यदि वहां शिलान्यास रखते, तो उसका काम भी शुरू हो जाता। लेकिन वह नहीं हुआ और हम रह गए। हमारे वहां पीरगाह एक स्थान है। बहुत जनता वहां आती है, पंजाब से बहुत से लोग

आते हैं। अगर वहां पी.एच.सी. की बिल्डिंग बन जाएगी, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं बार-बार एक ही बात पूछना चाहता हूं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी हैं, उन्होंने जगह-जगह बैनर्ज लगा रखे हैं कि पी.जी.आई. के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर हो चुका है, आ चुका है। बड़ी-बड़ी बातें हैं और बातों से बहुत काम हो रहा है। इस बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पी.जी.आई. का कितना काम हो चुका है? कहते हैं कि उसके लिए जमीन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बातों और पोस्टर्ज में वह नजर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऊना अस्पताल की बात करुंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप पत्थर में किसी का भी नाम लिखवांए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वह कोई सरकारी ओहदे पर होगा, उसके लिए आप उनको डायरैक्टर या चेयरमेन इत्यादि कुछ भी बना दें, उसके बाद सतपाल जी जितना मरजी करते रहें, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के तौर पर वह अभी नहीं कर सकते। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ध्यान देना चाहिए। नहीं है, तो आप जो परम्परा शुरू करेंगे, हम भी उसीको आगे लेकर चलेंगे, इसमें क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप द्वेष भावना रखेंगे, तो हम भी रखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे मुख्य मंत्री महोदय वहां आए थे, तो उससे पहले वहां चार ऐसे काण्ड हुए जिनमें 15 दिन से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। मैं इस बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और

26.03.2018/1745/जेके/एजी/1

श्री सतपाल सिंह रायज़ादाः--------**जारी**-------

उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। आजकल खनन भी चल रहा था लेकिन वह विषय अभी नहीं है, लेकिन आज स्वास्थ्य का विषय है, जब खनन का चलेगा मैं उसकी बात भी करूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया कटौती प्रस्ताव के विषय से बाहर न जाएं।

श्री सतपाल सिंह रायज़ादाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ही बात करूंगा। मैं, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि सिर्फ बातों में ही बातें न हों। अगर ऊना हॉस्पिटल की बात करें तो अभी तीन दिन पहले वहां पर हड्डियों के एक डॉक्टर के पास मरीज़ गया तो पहले उन्होंने उससे पूरा सामान मंगवा लिया, जब वह गरीब 12-15 हजार रूपए का सामान ले कर आया तो उसको फिर पी0जी0आई0 रैफर कर दिया गया। ऐसे हालात हॉस्पिटल्ज़ के अन्दर हैं। मै, माननीय मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि हॉस्पिटल्ज़ की ओर ध्यान दें। मेरी सलाह तो यह भी रहेगी कि हॉस्पिटल्ज में हर जगह कैमरें होने चाहिए और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि क्या चल रहा है? इस तरह से डॉक्टर्ज़ भी ठीक काम करेंगे और पता भी चलेगा कि डॉक्टर्ज़ अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं? जब हमारे जैसे लोग वहां पर जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये बिना मतलब के यहां पर चले आते हैं। मैं तो वहां पर कई बार जाता हूं। वे यह कहते हैं कि यह बिना मतलब के चले आते हैं लेकिन वहां पर आम लोगों की पूछ नहीं होती। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन किसी की सिफारिश के बिना गरीब व्यक्ति का इलाज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे हॉस्पिटल्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार ऐसी कोशिश करें कि गरीब आदमी का जो इलाज है वह बिना फोन के और बिना किसी सिफारिश के हो। धन्यवाद, जय हिन्द।

26.03.2018/1745/जेके/एजी/2

अध्यक्षः श्री जगत सिंह नेगी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा का जो परिसर है, क्या इसके अन्दर किसी भी पार्टी को नारेबाजी करने का अधिकार दिया गया है? जिस गेट से हम अन्दर आते हैं और बाहर जाते हैं वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और पर्टिकुलर पार्टी के नारे लग रहे हैं। ...व्यवधान... आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग मुझे रोक नहीं सकते । इस विधान सभा परिसर में नारे लग रहे हैं, इससे हमारी विधान सभा की गरिमा खत्म हो जाएगी। कल हमारी पार्टी वाले आ जाएंगे, दूसरी पार्टी के लोग आ जाएंगे, आप किसको रोकेंगे? इस विधान सभा की अपनी गरिमा है और

इसको ये लोग खत्म करने जा रहे हैं। ये सारे संस्थानों को एक-एक करके खत्म करने जा रहे हैं। विधान सभा को भी इन्होंने नारों का एक अड्डा बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से कभी भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विधान सभा परिसर के अन्दर नारे नहीं लगाए। आप बाहर से लोगों को ला रहे हैं। विधायकों को नारे लगाने का हक है। वे विधायक नहीं है। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज। जगत सिंह नेगी जी, आपने मेरे ध्यान में यह विषय लाया। धन्यवाद।

अभी मांग संख्याः9 के ऊपर 15 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

26.03.2018/1745/जेके/एजी/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मांग संख्याः9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इस विषय पर माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर कटौती प्रस्ताव रखा गया। जैसा कि आपने कहा कि 15 माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ सुझाव दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ साथियों ने चिन्ता प्रकट की कि अगर स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक होगा तो सरकार का स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा।

26.03.2018/1750/SS-DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार का ग्राफ भी आंका जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि तीन महीनों में जो सरकार ने ठाकुर जय राम जी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल की है उससे स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश का भी ठीक होगा और उसकी नींव में जो हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य है उसका रंग और रूप भी दिखने को मिल जायेगा। जो बजट प्रस्तुत किया गया यानी किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए

उसमें धन का कितना प्रबन्धन है, किन-किन योजनाओं को प्राथमिकता से लिया जा रहा है, समाज का हर व्यक्ति उन योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहा है, ये शायद बजट से, योजना से और उन योजनाओं में कितना धन प्रस्तावित है उस पर निर्भर करता है।

इसलिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश का 41440 करोड़ का बजट है उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का 2300 करोड़ का बजट है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं पिछले वर्ष की इस बजट राशि को देखूं तो यह 1720 करोड़ था। अगर हम प्रतिशत में देखें तो यह 1720 करोड़ यानी 4.80 प्रतिशत की वृद्धि थी और हमारा जो यह बजट है इसमें 5.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। --(व्यवधान)-- वीरभद्र जी, आप हमारी बात तो सुन लीजिए, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं।

अध्यक्षः मंत्री जी, एक मिनट प्लीज़। माननीय वीरभद्र सिंह जी।

श्री वीरभद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था मगर माननीय मंत्री जी जो आंकड़े दे रहे हैं ये सही नहीं हैं। अगर इस साल के बजट में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वृद्धि से यह दर्शाया जा सकता है कि नये इंस्टिट्यूशन्ज़ खुले हैं। इस दौरान में जो नये इंस्टिट्यूशन खुलने हैं उनके लिए यह बजट प्रावधान हुआ है। Nothing more than that.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में आनुपातिक वृद्धि 16 प्रतिशत है तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में प्रयास कर रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

26.03.2018/1750/SS-DC/2

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरे मित्र साथियों ने स्वास्थ्य संस्थानों, डॉक्टर्ज़, पैरा-मेडिकल स्टाफ, अधोसंरचना, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 के बारे में बहुत चिन्ता प्रकट की। परन्तु यह चिन्ता अगर यहां पर (सत्तापक्ष में) रहते हुए की होती, इसके लिए कोई कारगर योजना और नीति बनाई होती तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश कहीं और होता। जहां पर कहा जा रहा है कि हैल्थ इंस्टिट्यूशन्ज़ में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं, क्यों नहीं हैं? सरकार आने के तुरन्त बाद दो महीने के अंदर-अंदर 262 डॉक्टर्ज़ हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग संस्थानों भरे गए हैं। ये कहां से आए हैं? --(व्यवधान)-- ज्वाइन भी कर जायेंगे और कर भी

रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 262 डॉक्टर्ज़ हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग संस्थानों/हैल्थ इंस्टिट्यूशन्ज़ में लगे हैं।

26.03.2018/1755/केएस/डीसी/1

स्वास्थ्य मंत्री जारी---

दूसरे, ये चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि सरकार अपनी मन्शा तो बताएं। मन्शा हमारी बिल्कुल साफ है। चुनाव आचार संहिता के कुछ दिन पहले अगर स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने का एक जगह पर फैसला कर लिया जाए और वहां पर दृष्टिकोण राजनीतिक हो, जनसेवा दिख नहीं रही हो तो उसका परिणाम यह है। अध्यक्ष महोदय, हम बन्द करने की बात नहीं कर रहे हैं परन्तु वहां पर एक स्वास्थ्य संस्थान के लिए जो जरूरी मानक होने चाहिए, क्या वह वहां पर है? वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर है? वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मिली है? वहां पर ओ.पी.डी. है? 6 या 7 अक्तूबर को बहुत फैसले ले लिए गए और 12 अक्तूबर को आचार संहित लग गई। अब यहां पर हमें कहा जाए कि स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कमिटिड है । 262 डॉक्टर लगे हैं और पैरा मैडिकल स्टाफ को भरने की प्रक्रिया में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पैरा मैडिकल स्टाफ की अलग-अलग श्रेणियों को भरने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें कहा है। इसके लिए आदेश दिए हैं। अब कोई यह कहे कि ये दिख नहीं रहा है और अस्पताल का स्वास्थ्य ठीक नहीं हैं इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिला कर सरकारी संस्थानों को मज़बूत करने की दिशा में हमारी सरकार श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है। बजट में सारी बातें प्रस्तावित की गई है, यहां पर बातें रखी गई है। अगर एम्ज़ की बात की जाए, भारत सरकार ने उसके लिए अपनी संस्तुति दी है, उसको अनुमोदित किया है। 1351 करोड़ रुपया उसमें लगना है। जमीन इत्यादि का मामला हल हो गया है। उतनी ही जमीन और चाहिए तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय प्रयास कर रहा है। पी.जी.आई., चण्डीगढ़ के सैटेलाइट सैंटर की एक टीम का दौरा हुआ है और उन्होंने कुछ बातों का

जिक्र किया है। अभी 31 तारीख को चीफ सैक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है और उसको ले कर जो कुछ ऑब्जर्वेशन्ज़ लगाई गई है, मुझे लगता है कि वे दूर होंगी और उसमें

26.03.2018/1755/केएस/डीसी/2

हिमाचल प्रदेश सरकार को जमीन को ले कर, रोड़ को ले कर या वहां हमारा जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा था कि हमें चार कमरे चाहिए वह हमने दे दिए हैं और सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो रही है। यह जितना पैसा आएगा यह प्रदेश सरकार या हमारे विभाग के पास नहीं आएगा। एच.एस.सी.सी. कम्पनी ने प्रारम्भिक इन्वैस्टिगेशन करने के बाद काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, निरंतर कोशिश कर रही है।

26.3.2018/1800/av/hk/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-------जारी

यहां पर युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन कार्ड के बारे में आशीष जी ने कहा कि इसमें कितना पैसा लगेगा। इसमें कनफ्यूज़न है; एक हजार रुपये लगेंगे या दो हजार रुपये लगेंगे। इसमें कोई कनफ्यूज़न नहीं है, हम 365 रुपये देंगे और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन कार्ड में से अब 30 हजार रुपये छोटी बीमारी, 1.75 लाख रुपये बड़ी बीमारी और अगर शरीर में कैंसर के सिम्पटम आ जाए तो 2.20 लाख रुपये का प्रावधान है। यह काम शुरू हो चुका है और अब तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 हजार कार्ड बन चुके हैं। मैं इस बारे में जानकारी ले रहा था तो मुझे बताया गया कि इस कार्ड के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये अलग-अलग बीमारियों पर खर्च भी हो चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री के आदेश हैं कि इस योजना को और ज्यादा स्पीडअप किया जाए। इसमें अढ़ाई लाख परिवार लाभान्वित होने वाले हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर निःशुल्क दवाओं के बारे में बात की जा रही है कि यह भारत

सरकार की योजना है। ठीक है, भारत सरकार भी सम-विचारों की ही सरकार है। हमने उनसे आग्रह किया और अब 330 नहीं बल्कि उससे ज्यादा मुफ्त दवाइयां देने का प्रावधान उस सूची में रखा गया है और इसके लिए एक साल का बजट गत वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपये के लगभग हो चुका है। कुल मिलाकर के हमारी सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। यहां पर बीच में बात आई कि जब मुख्य मंत्री राहत कोष है तो उसके बाद मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष बनाने की क्या जरुरत है। एक नई शुरुआत है, आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे पास भी बहुत आते हैं और तब मन यह करता है कि हमारे पास जितने पैसे हैं इस गरीब व्यक्ति को अपनी जेब से निकाल कर दे दें। लेकिन हर किसी की मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। आप भी सहायता करते हैं और हम भी करते हैं। हमने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि कुछ घातक बीमारियां ऐसे लाचार लोगों के शरीर में लग जाती है कि उनके पास उपचार के लिए

26.3.2018/1800/av/hk/2

पैसा नहीं होता। इसलिए हमने निवेदन किया और इसके लिए बजट में प्रावधान किया। इसकी मोडेल्टीस तय हो रही है और हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष में इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गरीब/ लाचार लोग चाहे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों; लोग तो हिमाचल प्रदेश के ही हैं। वह राजनीतिक आधार या पार्टी के आधार पर बंटने वाले नहीं है। हम उनके दु:ख में शामिल होना चाहते हैं इसलिए एक नया प्रयास और नई कोशिश शुरू कर रहे हैं। यहां पर कहा गया कि गाय को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? अब तो सब लोग शराब पीना शुरू कर देंगे, इस तरह से राम राज्य कैसे आयेगा? राम राज्य शब्दों से नहीं व्यवहार में दिखना चाहिए। शब्द और भाषण जितने लच्छेदार और बड़े-बड़े हो जाएं, कई बार लोगों की वाणी और व्यवहार में तालमेल नहीं होता। वाणी कुछ बोलती है और व्यवहार कुछ बोलता है। लेकिन यहां पर श्री जय राम जी बैठे हैं और इनकी वाणी और व्यवहार में

तालमेल है। इसलिए प्रयास किया गया है और यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां से कुछ रुपया लेकर के गो-माता के लिए

26.03.2018/1805/TCV/HK-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ... जारी।

जो यहां पर गोशाला की बात की गई है---(व्यवधान)--- हम मजबूर नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि बहुत-सी योजनायें---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय मंत्री जी आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, बेहतर रहेगा कि आप टू-दि-प्वाईंट आ जायें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री साहब मैंने कोई राजनीतिकरण नहीं किया, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं और मैं सीधा आदमी हूं। मैं यह कह रहा था कि बहुत-सी योजनाओं का जिक्र इस बार के इस बजट में किया गया है। इंस्टीच्यूशनल डिलीवरी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि हमारी माताएं-बहनें वहां पर आएं और प्रसूति के बाद शिशुओं बच्चों के लिए जो जरूरत होती है, वह उस किट में सब कुछ दिया जाये। ये किट लगभग 1500/- रुपये की होगी। ये भी एक प्रयास किया जा रहा है। हमने यह देखा है कि कई बार हम 'इंस्टीच्यूशनल डिलीवरी' से बचते हैं और इसके कारण माताएं कई बीमारियों की चपेट में आती हैं। इसके अलावा नवजात बच्चों को भी डिलीवरी के बाद पीलिया हो जाता है। यहां पर कहा गया कि प्राइवेट सिस्टम को एनकरेज़ न किया जाये। लेकिन एक अच्छी शुरूआत है, हमने 'सहभागिता योजना' शुरू की है। शहरों में ही क्यों, यदि कोई डॉक्टर गांव में कोई अच्छा अस्पताल बनाना चाहता है, अपनी सेवाएं अस्पताल में देना चाहता है, तो सरकार ने उसके लिए इंसैंटिव रखा है। यदि वह अस्पताल एक करोड़ रुपये में बनता है तो उसमें 25 लाख रुपये के उपदान का प्रावधान किया गया है। एक अच्छी शुरूआत है। एनकरेज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा

में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मैडिकल कॉलेजिज़ हैं, उन मैडिकल कॉलेजिज़ के सुदृढ़ीकरण के लिए ये वर्तमान सरकार कटीबद्ध है। नाहन में अच्छा कॉलेज चले, चम्बा में अच्छा कॉलेज चले, नेरचौक में अच्छा कॉलेज चले और हमीरपुर का कॉलेज भी अच्छा चले, इसलिए हमने वहां पर फेकल्टी मजबूत करने

26.03.2018/1805/TCV/HK-2

के लिए अधिकतर प्रोफेसर्ज की नियुक्ति कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं, यहां पर एक आवाज यह भी आ रही है कि यहां के डॉक्टरों को वहां, यहां की टोपी को वहां रखा जा रहा है। ये माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री जी ने कहा था। लेकिन यह टोपियां रखने वाली सरकार नहीं है। हमीरपुर में जो मैडिकल कॉलेज है, उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी भेज दी है कि उसकी हमें स्वीकृति दे दी जाये। वहां पर भी शीघ्र ही काम करना है। इसके लिए ज़मीन भी स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम होने वाली है। इंतकाल हमारे विभाग के नाम होने वाला है। यहां पर एक बात नाहन मैडिकल कॉलेज के बारे में आई है।

26-03-2018/1810/NS/YK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ----जारी

अध्यक्ष महोदय, यह आपका भी विधान सभा क्षेत्र है। यहां पर ज़मीन का कोई विषय नहीं है। यहां पर पिछले दिनों एच0एस0सी0सी0 ने टैंडर प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन यह प्रक्रिया किसी कारणवश रुकी पड़ी है। मैं इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी हमारे मैडिकल कॉलेज़िज हैं, उन मैडिकल कॉलेज़िज में अधिकतर स्थानों पर ज़मीन का विषय हल हो चुका है। माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि आप डल्हौजी तो गये पर आप अस्पतालों में नहीं गये। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मैंने मैडिकल कॉलेज, चम्बा का पूरा दौरा किया है। उसके बाद मैं सलूणी अस्पताल में गया

हूं। शायद आपको जानकारी नहीं है। शायद आप पंजाब के दौरे पर होंगी। क्योंकि आप वहां की प्रभारी हैं। माननीय सदस्या ने कहा कि आपका प्रवास चम्बा में हुआ है। मैं चम्बा भी गया हूं। मेडिकल कॉलेज में भी गया हूं और जो अस्पताल है, मैंने उसका भी दौरा किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी है तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है और कैसे चलना है? मुझे आपकी राय और सुझाव भी चाहिए। आपने जो अच्छे सुझाव दिये हैं, उनको मैंने लिखा है और अगर इन सुझावों की जरूरत होगी तो इनको अम्ल में भी लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जो हमारा सचिवालय या विश्वविद्यालय हैं, ये पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त ज़ोन बन जाये। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्य सरकारों से कमिटमैंट ली है कि हमारा हिन्दुस्तान टी0बी0 मुक्त हो जाये, इसके लिए हर प्रदेश सरकार को कोशिश करनी है। हिमाचल प्रदेश टी0बी0 मुक्त/क्षय रोग मुक्त हो जाये, इसके लिए बजट में जो 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि "क्षय रोग उन्मूलन" के लिए हमारा "Revised National Tuberculosis Control Programme" (RNTCP) कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत सरकार ने भी हमें प्रशस्ति पत्र दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि कुल मिला करके प्रदेश के 10 जिलों में हम मोबाइल मैडिकल यूनिट चलाने जा रहे हैं जोकि प्रस्तावित है। यह मोबाइल मैडिकल यूनिट 10 जिलों में चलेंगे और हर

26-03-2018/1810/NS/YK/2

जिले के सी0एम0ओ0 इसको को-ओर्डिनेट करेंगे। यह अभी 10 जिलों में शुरू हो रहा है और अगले चरण में अन्य जिलों को भी इसमें शामिल कर लेंगे। इस यूनिट में डॉक्टर्ज़, फार्मासिस्ट्स और हैल्पर्ज़ होंगे। यह मोबाइल यूनिट जहां-जहां जायेगी, वहां पर मुफ्त दवाईयां और तमाम टैस्ट फ्री होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह एक नई शुरूआत है। आने वाले दिनों में बचे हुए दो जिले भी इसमें शामिल हो जायेंगे।

26.03.2018/1815/RKS/YK-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में कई जगह सड़कें तंग हैं जिस कारण वहां पर 108 नम्बर एम्बुलैंस नहीं पहुंच पाती है। हम आने वाले दिनों में दो मोटरसाइकिल एम्बुलैंस चलाना चाहते हैं जोकि प्रस्तावित हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे चिकित्सा संबंधी उपकरण हैं, कई अस्पतालों में वे खराब हैं। खराब होने के कारण वे समय में ठीक नहीं हो पाते हैं। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चिकित्सीय उपकरणों को 24 घंटे के भीतर ठीक किया जाए। हिमाचल प्रदेश में टैली रेडियोलॉजी की सुविधा मिले, उसके लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। जैनेरिक दवाइयों के ऊपर काफी लम्बी बात हुई है। सभी को जैनेरिक दवाइयां मिलें यह कोशिश हो रही है। माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने एम.सी.एच. होस्पिटल बनने के लिए प्रस्तावित हैं? ये अस्पताल लगभग 10 हैं और इनके लिए लगभग 172 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। यह राशि प्रयोग नहीं की जा सकी है। जिन चीजों की जरूरत है उनको करने की हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हमें इसके लिए आदेश दिए हैं। एम.सी.एच., कुल्लू के लिए 20 करोड़ रुपये, एम.सी.एच., टांडां के लिए 40 करोड़ रुपये और एम.सी.एच. सोलन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रकार की सूची मेरे पास है, जिसे मैं माननीय सदस्य तक पहुंचा दूंगा। । यहां पर एक बात का जिक्र किया गया कि चम्बा में एक धरोहर है जिसे तोड़ा न जाए। हम कहां किसी धरोहर को तोड़ने के लिए चले हैं। अफवाहों के शायद पैर नहीं होते हैं। ऐसा फैसला किसी स्तर पर नहीं किया गया है कि हम किसी महल या भवन को तोड़ रहे हैं। आदरणीय श्री राम लाल ठाकुर जी भी पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और आप अच्छे सुझाव भी देते हैं। इन्होंने नैना देवी जी का विषय उठाया कि वहां पर टैम्पल ट्रस्ट ने फैसला किया है कि अगर वे 5 करोड़ रुपये देंगे, अगर वे देंगे तो स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें किसी तरह का ऑब्जैक्शन नहीं होगा। आप इस काम

को करवाइए। माननीय मुख्य मंत्री जी से हम इस बात को डिस्कस करेंगे और वह काम शुरू हो सकता है। इसके लिए मैं आपको

26.03.2018/1815/RKS/YK-2

आश्वस्त करना चाहता हूं। कुल मिलाकर ये सारी बातें यहां पर आ गई हैं। यहां पर ऐसी बाते भी आई कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में अस्पताल खाली हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 262 डॉक्टर्ज अप्वाईंट किए गए हैं। पैरा मैडिकल स्टाफ में लगभग 2000 और कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। यहां पर एक बात और आई है कि आयुर्वेदिक डिस्पैंसरिज भी खाली पड़ी हुई हैं। मै यह भी बताना चाहूंगा कि 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर्ज भी हम आने वाले दिनों में भरेंगे। 100 डाक्टर्ज हम हमीरपुर के माध्यम से और 100 डाक्टर्ज बैचवाइज भरेंगे। कुल मिलाकर यह कोशिश और प्रयास हो रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कॉलेजिज हैं उनमें 500 बच्चे एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं। अगर हम सोलन के प्राइवेट कॉलेज का जिक्र करें तो वहां पर भी बच्चे एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं। जब ये बच्चे एम.बी.बी.एस. करने के बाद लगभग तीन सालों के बाद पास आउट होंगे तो मुझे लगता है कि जो आवाज यहां उठ रही है कि मेरे स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर्ज नहीं हैं या उस संस्थान में नहीं है, यह कमी पूर्ण हो जाएगी और डॉक्टर्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी।

26.03.2018/1820/बी0एस0/ए.जी-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .....जारी

हम कटिबद्ध हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी बने, बढ़िया बनें। भारत के उस परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश के मानक बहुत ऊपर हैं, हम उनको बर्करार रखना चाहते हैं। कुल-मिलाकर ये सारी बातें यहां पर आ चुकी हैं। यहां पर कहा गया, जैसे आई.जी.एम. सी. का जो सुपर स्पेस्लिटी ब्लॉक है वह चमियाना में निर्माणाधीन है। मैडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है। जब सारे संस्थान रिव्यू हो रहे हैं तो ये भी रिव्यू में हैं। क्योंकि उस समय तो काफी कुछ बातें कह दी है। कुल मिला करके मैंने कोशिश

की है कि जो मेरे भाइयों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं वे सुझाव हमने नोट भी किए हैं और वे हिमाचल प्रदेश के लिए कारगर भी सिद्ध होंगे उनको हम शामिल करेंगे । इसलिए मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इस कटौती प्रस्ताव को वापिस ले लें। यह मैं आपसे आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं।

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे।

सदस्यगणः जी नहीं।

26.03.2018/1820/बी0एस0/ए.जी-2

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिलावार विधायकों ने अपने-अपने जिलों में अपने-अपने संस्थानों में जो हालात हैं उसका जिक्र किया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि आपके समय में भी ऐसा ही था। अब सरकार बदली है अब आप सत्तापक्ष में बैठे हैं इसको ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर हमारे टाइम में गलती रही है तो हम विपक्ष में आ गए हैं। मैं तो बिल्कुल ही बाहर था, अब यहां पर बैठा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो-जो हमारे विधायकों ने शंकाएं जाहिर की है, कहीं पैरामैडिकल स्टाफ नहीं लगा है, कहीं पर अस्पताल खाली हो गए हैं वहां से आपने दूसरे अस्पतालों में स्टाफ तैनात कर दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे मारकण्डा में सी.एच.सी. है। वहां पर एक भी डाक्टर इस समय नहीं है। एक दियोथ से डाक्टर उठाया उसको वहां बी.एम.ओ. बनाकर भेज दिया अब न दियोथ में डाक्टर है न वहां पर फार्मासिस्ट है। ऐसे ही नैना देवी का हाल है, जो वहां पर सी.एच.सी. है वहां पर एक डाक्टर जो शिकायत पर आया और शिकायत पर ही बदला गया। वह वहां पर बैठा हुआ है पंजाब का है, पंजाब में ही अपनी प्रैक्टिस करता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया परंतु जो शंकाए हमारे माननीय सदस्यों को हैं अपने-अपने प्रश्नों पर उनका उसका जवाब भी आना चाहिए। ताकि ये संतुष्ट भी हो जाएं। आपने AIIMS की बात की, मैं कहना चाहूंगा कि आपने बड़े शब्दों में इस बारे में बात की, लेकिन यह तो आपकी अन्तर आत्मा जानती होगी, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन कारण

यह है कि घर-बार को हाथ नहीं लगाना, बाकी देखते रहो, यह हाल आपका है। सारा कार्य करना केन्द्र सरकार ने करना है। जो सूचना आपके पास है उसके मुताबिक आपने उत्तर देना है। लेकिन जब आपके पास इस बारे में सूचना हीं नहीं है तो आप जवाब भी क्या देंगे? मैंने पहले भी एक प्रश्न किया था उसमें भी आपका उत्तर था कि जी हमारा कार्य नहीं है। यह तो केन्द्र सरकार ने करना है। मुझे नहीं लगता उसके बारे में चर्चा करना ठीक होगा। क्योंकि जब करना ही केन्द्र सरकार ने है, केन्द्र सरकार में मंत्री भी हमारे ही हैं, हमारे ही बिलासपुर से हैं। मैं अब क्या करूं और किसको बोलूं । अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लो। हम कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेंगे। आगे प्रक्रिया है आप उसके मुताविक जोर से हां कर लेना। लेकिन हमें बोलने तो दो जो हमारा अधिकार है।

26.03.2018/1825/डी0टी0/ए.जी-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र को ले करके जो चिन्ता जाहिर की है, चाहे वह डाक्टर्स को ले करके हो, चाहे पैरामैडिकल स्टाफ को ले करके हो, चाहे उपकरण इत्यादि को ले करके हो, वह हमारे ध्यान में बात आ गई है। अध्यक्ष महोदय, अभी तीन महीने तो हुए हैं। ये कुछ समय तो मुझे दें । माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ समय तो दे दें। मैं आपको इस हाऊस के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी इस प्रकार की कमी है,उसे हम हल करेंगे। मैं आपको इस हाऊस के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूं। भाई सुन्दर सिंह ठाकुर जी बार-बार उठ रहे हैं। कुल्लू के बारे में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ बैठ करके जरूर बात करूंगा। माननीय राजेन्द्र राणा जी, माननीय हर्ष वर्धन जी और माननीय जगत सिंह नेगी जी ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए। माननीय विधायक जी आपने अपनी बात कह दी है, आप तो इस सदन के उपाध्यक्ष रहे हैं आपको तो सारी प्रक्रिया का पता है, लेकिन मैंने फिर भी बोलने की अनुमति दी है।

तो प्रश्न यह है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री अनिरूद्ध सिंह जी, श्रीमती आशा कुमारी जी, श्री हर्ष वर्द्धन चौहान जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री राम लाल ठाकुर जी, श्री राजेन्द्र राणा जी, श्री नन्द लाल जी, डॉ0 धनी राम शांडिल जी, श्री राकेश सिंघा जी, श्री पवन कुमार काजल जी, श्री विक्रमादित्य जी, श्री आशीश बुटेल जी और श्री सतपाल सिंह रायजादा जी के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

प्रस्ताव गिर गया
कटौती प्रस्ताव अस्वीकार

26.03.2018/1825/डी0टी0/ए.जी-2

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित मु0 19,94,23,21,000/- (राजस्व) और 1,86,77,30,000/- (पूंजी) की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित निधि में से दे दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मैं माननीय सदन से जानना चाहता हूं कि अगली मांग प्रारम्भ करें या कल प्रातःकाल प्रारम्भ की जाए।

माननीय सदस्यगणः कल प्रातःकाल प्रारम्भ की जाए।

अध्यक्षः सदन की भावना का ध्यान रखते हुए कल प्रातःकाल सिंचाई एवं जलापूर्ति एवं सफाई विषय पर चर्चा होगी।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो विपक्ष का प्रेरोगेटिव है, सर, आधा घंटा बचा हुआ है।

26.03.2018/1825/डी0टी0/ए.जी-3

अध्यक्षः मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं अपने शब्द वापिस ले लेता हूं। और दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू कर देता हूं। मैंने विपक्ष के इशारे पर यह निर्णय लिया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक कल प्रातः पूर्वाह्न 11.00 बजे 27 मार्च, 2018 तक के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 26 मार्च,2018 **सचिव।**